चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित | 16 जनवरी– 22 जनवरी 2017 | नई दिल्ली | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

विधानसभा चुनाव आते ही बेपर्द होने लगे राजनीतिक दल, तेज़ हुआ दंगल

फोटो : प्रभात पाण्डेय

बेटे और बाप की कुश्ती

सत्ताग्रह का दुराग्रह चरम पर

प्रभात रंजन दीन

राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने सामाजिक मर्यादा रौंद डाली. मुलायम परिवार का सत्ताग्रह न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के आधुनिक राजनीतिक इतिहास का पहला काला अध्याय बन गया है. सत्ताग्रह के दुराग्रह ने चाचा–भतीजे और पिता–पुत्र के रिश्ते की ऐसी–तैसी कर दी. जबकि सत्ताभोग के लिए ही मुलायम ने प्रदेश की राजनीति में परिवारवाद का सृजन किया था. समाजवाद के नाम पर परिवारवाद की स्थापना की मुलायम–यात्रा के जरिए ही प्रो. रामगोपाल यादव से लेकर शिवपाल यादव, अखिलेश यादव से लेकर डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव से लेकर अक्षय यादव, तेज प्रताप यादव, आदित्य यादव और तमाम रिश्तेदार राजनीति के अलग–अलग पायदान पर स्थापित होते चले गए. यह प्रयास आगे भी जारी था. अपर्णा यादव से लेकर कई अन्य मुलायम पीढ़ियां सियासत के दरवाजे पर कतार बांधे खड़ी थीं, लेकिन इस रिश्ताभियान में अचानक बाधा पड़ गई. उत्तर प्रदेश के विशाल राजनीतिक परिवार में सत्ता की महत्वाकांक्षा ने सारी मर्यादाएं तोड़ डालीं. जिस रिश्ते से वशीभूत मुलायम ने सारी राजनीतिक मर्यादा ताक पर रख कर बेटे को मुख्यमंत्री बनाया था, उस बेटे ने रिश्ते की मर्यादा ताक पर रख दी और पिता को हटा कर खुद को समाजवादी पार्टी का अलमबरदार घोषित कर दिया. सत्ता लोलुपता का मुगलकालीन इतिहास दोहराया गया. अब दोनों साथ चुनाव लड़ें या अलग–अलग, गुणा–गणित साथ–साथ हो या अलग–अलग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. भारतीय समाज ने पिता–पुत्र संघर्ष के उत्तरार्ध को स्वीकार नहीं किया है. समाजवादी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता और पुराने प्रतिबद्ध समाजवादियों की ऐसी राय अच्छे भविष्य के संकेत नहीं दे रही है. समाजवादी पार्टी के इस ऐतिहासिक रार में राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक मर्यादा के साथ–साथ कृतज्ञता के भाव की भी मिट्टी पलीद हो गई. मुलायम की कृपा से ऊंचे पदों पर विराजमान होते रहे लोगों ने भी ऐसे मौके पर मुलायम का साथ छोड़कर अपनी नैतिक–ऊंचाई का सार्वजनिक प्रदर्शन करने से परहेज नहीं किया. इनमें किरणमय नंदा, अहमद हसन, नरेश अग्रवाल, कुंअर रेवती रमण सिंह, अवधेश प्रसाद, धर्मेंद्र यादव जैसे स्वनामधन्यों के नाम अग्रगण्य हैं. राजनीतिक अवसरवाद के ये संकेत–चेहरे मुलायम के खिलाफ 1 जनवरी 2017 को आयोजित विद्रोह सभा में मंच पर विराजमान थे. सत्ता का लोभ मनुष्य को क्या–क्या बना देता है.

उधर, 'जीवस्य जीवयो भोजनम' की शाश्वतता को बहाल रखते हुए अन्य राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी के समापन की मनौती और सत्ता–स्वाद की बंटौती का अभी से जतन करने लगे हैं. बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने तो मान ही लिया कि सपा के इस युद्ध का फायदा उन्हें मिलेगा. कलह से विक्षुब्ध मुसलमानों का वोट उन्हें प्राप्त होगा और वह दलित–मुस्लिम समीकरण के कंधे पर सवार होकर सत्ता तक पहुंच जाएंगी. भाजपा अलग अपनी स्वाद–साधना में लगी है और 40 सीटों से सीधे तीन सौ पर पहुंचने का ख्वाब बुनने लगी है. कांग्रेस भी सत्ता का कुछ टुकड़ा पाने की अभिलाषा में कभी सपा से गलबहियां लेने तो कभी बसपा से झप्पी लेने की कोशिश में इधर–उधर डोल रही है. आम लोगों की रायशुमारी और सर्वेक्षण पर पतंगबाजियां हो रही हैं, लेकिन वह सर्वेक्षण सपा की तख्तापलट–सभा के काफी पहले किया गया था, जो बदली हुई स्थितियों में प्रासंगिक नहीं रहा. उस सर्वेक्षण के आधार पर समाजवादी पार्टी को पहले पायदान पर, भाजपा को दूसरे और बसपा को तीसरे स्थान पर रखा जा रहा है, लेकिन अखिलेश यादव द्वारा खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करने और पार्टी मुख्यालय पर जबरन कब्जा करने के बाद उनका ग्राफ अचानक नीचे चला गया. शिवपाल के खिलाफ अखिलेश के आक्रोश–प्रसंग पर आम लोगों ने अखिलेश के प्रति अपनी सहानुभूति जताई थी और तब उनका सियासी ग्राफ ऊपर था, लेकिन बाद की प्रगति ने अखिलेश के कद की प्रगति अचानक रोक दी. जब तक वे अपने अधिकार के लिए जूझ रहे थे, तब तक लोग अखिलेश के साथ थे, लेकिन जब सत्ताकांक्षी विधायकों की जमात लेकर उन्होंने अपने पिता मुलायम के अस्तित्व पर ही प्रहार किया, तब लोगों को यह रास नहीं आया. यह सर्वेक्षण के बाद की प्रगति है. यादव समुदाय से लेकर समाज के अन्य तबकों में भी पिता के खिलाफ बेटे की बगावत पच नहीं पाई है. खुद समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग ही इसे पचा नहीं पा रहे हैं. समाजवादी पार्टी के विद्रोह के दिन, यानि, एक जनवरी 2017 को जो भीड़ रामगोपाल–नियोजित सभा में जुटी थी और जो भीड़ समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर अखिलेश समर्थकों द्वारा की गई तोड़फोड़ और कब्जेबाजी की हरकतों की चश्मदीद थी, उसमें से अधिकांश लोगों ने खुली राय दी कि यह ठीक नहीं हो रहा. आम लोग भी सपा मुख्यालय पर हो रही उस ऐतिहासिक घटना के चश्मदीद बने थे, जिन्होंने खुलेआम कहा कि इस तरह की हरकतों से लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जियां उड़ गईं. बदले हुए राजनीतिक परिदृश्य में समाजवादी पार्टी के लिए अब तक प्रतिबद्ध रहा मतदाता भी पूरी तरह भ्रम में भटक गया है कि वह किधर जाए. बेटे की तरफ या पिता की तरफ! मतदाताओं का यह भ्रम उसे सपा में वोट डालने से रोकेगा, इसके साफ संकेत मिल रहे हैं. समाजवादी पार्टी के ही एक वरिष्ठ नेता बोले कि डॉ. लोहिया ने कहा था, सुधरो या टूटो, ये सुधर नहीं सकते तो इनका टूट जाना ही बेहतर है. सपा मुख्यालय परिसर में ही एक किनारे खड़े कुछ अधेड़ कुछ बुजुर्ग समाजवादी मुलायम के योगदान और पार्टी खड़ा करने के उनके समर्पण को रेखांकित करते हैं, लेकिन साथ ही यह भी कहते हैं कि पुत्र मोह में नेताजी की फजीहत हो गई. इसके बावजूद सपा के ये सामान्य नेतागण अखिलेश और उनके समर्थकों की ऐसी कार्रवाई को फूहड़ और अराजक बताने से नहीं हिचक रहे थे. उनका कहना था कि ऐसे पिता के साथ अखिलेश को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी.

एक जनवरी 2017 को जो भीड़ रामगोपाल-नियोजित सभा में जुटी थी और जो भीड़ समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर अखिलेश समर्थकों द्वारा की गई तोड़फोड़ और कब्जेबाजी की हरकतों की चश्मदीद थी, उसमें से अधिकांश लोगों ने खुली राय दी कि यह ठीक नहीं हो रहा. आम लोग भी सपा मुख्यालय पर हो रही उस ऐतिहासिक घटना के चश्मदीद बने थे, जिन्होंने खुलेआम कहा कि इस तरह की हरकतों से लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जियां उड़ गईं.

लेकिन शिवपाल ने भी जिस तरह का रुख अपनाया और जिस तरह की कार्रवाइयां कीं, उसे सराहा नहीं जा रहा है. सरकार से लेकर संगठन तक खींचतान और अखिलेश समर्थकों की बर्खास्तगी की सिलसिलेवार कार्रवाइयों ने तल्खी बढ़ाने का काम किया. अखिलेश के प्रदेश अध्यक्ष होते हुए भी सांगठनिक फेरबदल और टिकटों के बंटवारे में अखिलेश की उपेक्षा ने कलह को गहराने का काम किया. अखिलेश को हटाकर जब शिवपाल खुद प्रदेश अध्यक्ष बन गए तो उसने आग में बारूद का काम किया. मुलायम का सहारा लेकर शिवपाल अनाप–शनाप फैसले लेने लगे. अखिलेश के विरोध के बावजूद माफिया

(शेष पृष्ठ 2 पर)

नोटबंदी : पचास दिन के पचास भद्दे रंग | P-4

नोटबंदी : वे नौकरी से निकालते रहे, सरकार फायदे गिनाती रही | P-5

मणिपुर : नोटबंदी के दौर में नाकेबंदी ने जीना मुहाल किया | P-6

बेटे और बाप की कुश्ती

पृष्ठ 1 का शेष

सरगना मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल का सपा में विलय करा दिया. अपराधिक छवि के लोगों को धड़ल्ले से टिकट बांटा जाने लगा. फिर मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी और संगठन से निष्कासन की परस्पर प्रतिक्रियात्मक कार्रवाइयों ने माहौल और खराब किया. फिर शिवपाल ने अखिलेश के तीन खास मंत्रियों राम गोविंद चौधरी, अरविंद सिंह गोप और पवन पांडेय का टिकट काट कर सीधी भिड़ंत का न्यौता दे दिया. जबकि अखिलेश मंत्रिमंडल के दर्जनों निष्कासित मंत्रियों को टिकट दिया गया. माफिया सरगना अतीक अहमद, भ्रष्टाचार के आरोपी मुकेश श्रीवास्तव, पत्नी-हंता अमनमणि त्रिपाठी और माफिया सरगना मुख्तार अंसारी के भाई सिगबतुल्लाह को भी टिकट दे दिया गया. इस पर अखिलेश बिफर पड़े. अखिलेश ने अपना अधिकार मांगा, जिसे पार्टी ने देने से मना कर दिया. इसमें पार्टी सुप्रीमो मुलायम ने भी शिवपाल का ही साथ दिया. मुलायम यह नहीं सोच पाए कि जिस पुत्र को उन्होंने पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, जिसे बाद में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया, उसे उसकी प्रतिष्ठा के मुताबिक उसके सांगठनिक अधिकार भी मिलने चाहिए थे. मुलायम पुराने समय में जी रहे थे. उन्होंने बदलते समय का आकलन नहीं किया और शिवपाल की घेरेबंदी ने उन्हें बदलते समय का एहसास नहीं होने दिया. जबकि वास्तविकता यही थी कि अखिलेश के रूप में नया युग आ चुका था. अखिलेश ने अपना अधिकार प्राप्त करने में राजनीतिक-अराजनीतिक और लोकतांत्रिक-अलोकतांत्रिक तौर-तरीकों का मिश्रण बनाया और पार्टी पर सीधे कब्जा कर लिया.

एक जनवरी 2017 को सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रो. रामगोपाल यादव की ओर से लखनऊ में बुलाए गए अधिवेशन को राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने भले ही असंवैधानिक करार दिया, लेकिन वही सभा मुलायम-युग के पटाक्षेप का अध्याय लिख गई. मुलायम के भाई रामगोपाल यादव ने ही अपने राजनीतिक गुरु नेताजी मुलायम सिंह यादव को पार्टी का मार्गदर्शक बना कर दरकिनार करने और उनकी जगह अखिलेश यादव को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित कराया. उन्होंने शिवपाल यादव को प्रदेश अध्यक्ष पद से और अमर सिंह को पार्टी से हटाने का भी प्रस्ताव ध्वनि मत से पास कराया. अखिलेश समर्थकों के हुजूम ने नए नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के साथ लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग स्थित पार्टी मुख्यालय पर हमला बोल दिया. अखिलेश सरकार की पुलिस भी दर्शक दीर्घा में खड़ी रही और अखिलेश समर्थकों ने तोड़फोड़ मचाकर पार्टी मुख्यालय पर कब्जा कर लिया. हमलावरों ने शिवपाल यादव के अध्यक्ष का नेमप्लेट उखाड़ कर जमीन पर फेंका और पैरों से कुचला. नरेश उत्तम भीड़ में से निकले और शिवपाल की कुर्सी पर आकर धंस गए. लोकतंत्र और समाजवाद गेट से

फोटो : प्रभात पाण्डेय

बाहर निकल गया. आपस में संधि कराने की कोशिश करने वाले वरिष्ठ सपा नेता आजम खान तक ने कहा कि जो कुछ हुआ उसकी उन्हें कतई उम्मीद नहीं थी. जबकि अखिलेश का कहना था कि नेताजी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था पर कुछ लोगों ने उनके खिलाफ साजिश करके न केवल पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम किया, बल्कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के सामने भी संकट पैदा किया. साजिश करने वालों ने अपने घर से टाइपराइटर मंगवा कर उनके खिलाफ मनमानी चिट्ठियां लिखवाईं और नेताजी से हस्ताक्षर करवाकर जारी किया. अखिलेश का इशारा साफ तौर पर शिवपाल की तरफ था. निर्णायक विद्रोह-सभा में पार्टी-अधिग्रहण की कार्रवाई का अंदेशा तभी हो गया था, जब अखिलेश के बुलावे पर तकरीबन दो सौ विधायक और तीन दर्जन से अधिक विधान परिषद सदस्य उनके आवास पर पहुंचे थे. इसके अलावा भारी संख्या में प्रत्याशी और संगठन के पदाधिकारी भी अखिलेश के सरकारी आवास पर मौजूद थे. उधर मुलायम के आवास पर भी विधायकों, प्रत्याशियों और पदाधिकारियों को बुलाया गया था, लेकिन वहां बमुश्किल दो-ढाई दर्जन विधायक और कुछ प्रत्याशी व पदाधिकारी ही पहुंचे. आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में सपा के 229 विधायक और 67 विधान परिषद सदस्य हैं. अखिलेश-रामगोपाल के विद्रोही अधिवेशन से मुलायम का मनोबल इतना दब गया कि उन्होंने पांच जनवरी को बुलाए आधिकारिक अधिवेशन को स्थगित कर दिया.

अखिलेश के लिए बांहें खोले है कांग्रेस, बसपा पर भी डाल रही डोरे

अब समाजवादी पार्टी में पिता और पुत्र की दो अलग-अलग धाराएं हो चुकी हैं. मुलायम सिंह यादव औपचारिक तौर पर चुनाव आयोग जाकर अपना दावा दाखिल कर चुके हैं. अखिलेश यादव भी करीब सवा दो सौ विधायकों के हस्ताक्षर वाला शपथ पत्र चुनाव आयोग भेज कर अपने खेमे को असली समाजवादी पार्टी बता रहे हैं. यानि, अब स्पष्ट है कि मुलायम की समाजवादी पार्टी और अखिलेश की समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव में अलग-अलग उतरेंगी. मुलायम पूर्व में घोषणा कर चुके हैं कि वे किसी भी दल के साथ चुनावी गठबंधन नहीं करेंगे. बदली हुई स्थितियों में उनके साथ कोई दल गठबंधन करने की पहल करेगा कि नहीं, यह भी नहीं कहा जा सकता. लेकिन अखिलेश खेमे और कांग्रेस के गठबंधन की संभावनाएं बनी हुई हैं. अखिलेश यादव के लिए मुख्यमंत्री की दावेदारी छोड़ देने का कांग्रेस नेता शीला दीक्षित का प्रस्ताव दोनों दलों के बीच तालमेल की संभावनाओं का स्पष्ट संकेत है. शीला दीक्षित को कांग्रेस की ओर से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद की प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत किया गया था. शीला दीक्षित ने कहा, 'समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के मौजूदा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री पद के लिए मुझसे कहीं बेहतर प्रत्याशी हैं और मैं अखिलेश के लिए रास्ता छोड़ देने में खुशी महसूस करूंगी.' आप याद करते चलें कि चुनाव की घोषणा होने के फौरन बाद कांग्रेस ने सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता में आने से रोकने के लिए सपा के साथ अपने गठबंधन के विकल्प खुले रखने के स्पष्ट संकेत दिए. कांग्रेस ने साफ-साफ कहा कि गठबंधन पर फिलहाल तो कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ वह हाथ मिलाने को तैयार है. दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने भी कहा कि कांग्रेस और उनकी पार्टी के बीच गठबंधन होता है तो नतीजे अच्छे होंगे. उन्होंने कहा, 'यदि अखिलेश चुनाव अभियान का नेतृत्व करने की बात सही है तो मेरे लिए यह उपयुक्त होगा कि मैं दौड़ से हट जाऊं. वह युवा और अनुभवी हैं.'

वैसे, कांग्रेस ने सपा (अखिलेश गुट) के साथ-साथ बसपा से भी तालमेल का विकल्प खोल रखा है. कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि जिस भी दल के साथ सीटों की हिस्सेदारी पर सम्मानजनक बात बन जाएगी, कांग्रेस उस दल के साथ तालमेल कर लेगी. कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी महासचिव गुलाम नबी आजाद इसी रणनीति पर काम कर रहे हैं. बसपा प्रमुख मायावती कांग्रेस की मांग के मुताबिक सीटें देने पर राजी नहीं हैं. उधर, अखिलेश यादव पहले ही यह कह चुके हैं कि कांग्रेस से अगर चुनावी गठबंधन हो गया तो गठबंधन को 300 सीटें मिलेंगी. कांग्रेस सपा के अखिलेश गुट के साथ जाने को अधिक प्राथमिकता दे रही है. उसकी वजह यह भी है कि सपा कांग्रेस के लिए सौ से अधिक सीटें छोड़ सकती है, जबकि मायावती इसके लिए राजी नहीं हैं.

मुस्लिम वोट खींचने की जद्दोजहद में लगी हैं सारी पार्टियां

जहां तक टिकट की घोषणा की अद्यतन स्थिति का सवाल है, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है. मुलायम सिंह यादव की तरफ से समाजवादी पार्टी के 403 प्रत्याशियों की सूची जारी हो चुकी है. उस पर अखिलेश यादव ने भी अपने 235 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी थी. लेकिन समाजवादी पार्टी के झगड़े में प्रत्याशियों की सूची भी दो-धार में फंस गई है. हालांकि, प्रो. राम गोपाल यादव बार-बार यह कह रहे हैं कि उनकी पार्टी (अखिलेश खेमा) ही असली है, और 403 सीटों पर अखिलेश टीम ही चुनाव लड़ेगी. दूसरी तरफ बसपा भी 403 प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है. मायावती और मुलायम दोनों ही मुस्लिम वोटों पर अपनी-अपनी दावेदारी जता रहे हैं. मायावती ने आगे बढ़ कर 97 मुसलमानों को अपना उम्मीदवार बनाया, जबकि दलित प्रत्याशियों की संख्या 87 ही है. साफ है कि दलितों की पार्टी बसपा ने मुसलमानों का वोट पाने की आशा में अपनी प्राथमिकताओं को ताक पर रख दिया है.

अनिर्णय में फंसी भाजपा, योगी की उपेक्षा पर काडर में नाराजगी

प्रत्याशियों के चयन में भारतीय जनता पार्टी सबसे ढीली है. भाजपा अभी-अभी परिवर्तन यात्राओं, यानि प्रचार यात्राओं से उबरी है. अब जाकर भाजपा ने अपनी चुनाव समिति गठित की है, जो प्रत्याशियों का चयन करेगी. विडंबना यह है कि जिस योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए जाने की बात की जा रही थी, उन्हें चुनाव समिति तक में शामिल नहीं किया गया. यानि, प्रत्याशियों के चयन में योगी आदित्यनाथ की कोई भूमिका नहीं होगी. जिस तरह की चुनाव समिति बनी है, उससे प्रत्याशियों के चयन में सिरफुटौव्वल सुनिश्चित है. प्रत्याशी घोषित किए जाने में हो रही अप्रत्याशित देरी और मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं होने के कारण भाजपा की किरकिरी पहले से हो रही है. प्रदेश चुनाव समिति में प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य के अलावा पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व मौजूदा केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, उमा भारती और कलराज मिश्र को भी शामिल किया गया है. कांग्रेस से आईं डॉ. रीता बहुगुणा जोशी और बसपा से आए स्वामी प्रसाद मौर्य व बृजेश पाठक भी चुनाव समिति के सदस्य बनाए गए हैं. मायावती पर विवादास्पद बयान देने के कारण पार्टी से निष्कासित किए गए दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह भी चुनाव समिति में सदस्य नामित हुई हैं. इनके अलावा ओम प्रकाश माथुर, डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी, शिव प्रकाश, डॉ. दिनेश शर्मा, अरुण सिंह, डॉ. महेन्द्र सिंह, सुनील बंसल, ओम प्रकाश सिंह, विनय कटियार, रमापति राम त्रिपाठी, सूर्यप्रताप शाही, सुरेश खन्ना, सुनील ओझा, वीरेन्द्र खटिक, रमेश विधूरी, रामेश्वर चौरसिया, स्वतंत्र देव सिंह, सलिल विश्नोई और रमाशंकर कठेरिया को भी भाजपा प्रदेश चुनाव समिति का सदस्य बनाया गया है. भाजपा यह दावा कर रही है कि 17 जनवरी को चुनाव के पहले फेज़ के नामांकन के पहले प्रत्याशियों की लिस्ट आ जाएगी.

(शेष पृष्ठ 3 पर)

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 08 अंक 46
16 जनवरी- 22 जनवरी 2017

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-6451999
6450888
विज्ञापन व प्रसार 022-65500786
+91-8451050786
+91-9266627379
फैक्स न. 0120-2544378
पृष्ठ-20++ (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त क़ानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

बेटे और बाप की कुश्ती

पृष्ठ 2 का शेष

प्रत्याशियों के चयन पर अभी से भाजपा कार्यकर्ता और नेता ध्यान लगाए हुए हैं. भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि भाजपा में बाहरी दलों से टपके नेताओं को प्राथमिकता दी गई, तो भाजपा को चुनाव में असली जमीन का दर्शन करा दिया जाएगा. भाजपा के प्रतिबद्ध कार्यकर्ता यह मानते हैं कि दूसरे दलों से आए नेता टिकट और पद की महत्वाकांक्षा लेकर भाजपा में शामिल हुए. ऐसे नेताओं को टिकट या पद नहीं मिला तो ये भाजपा छोड़ भी देंगे. और अगर टपके नेताओं को प्राथमिकता के आधार पर टिकट दिया गया तो भाजपा के अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं का विरोध भाजपा को मुश्किल में डाल देगा.

छोटे दलों के दलदल से दलों को डर, मेल-मिलाप की कोशिशें

चौधरी अजित सिंह के राष्ट्रीय लोक दल में भी प्रत्याशियों का चयन नहीं हो पाया है, क्योंकि चौधरी भी गठबंधन के नए-नए अवसर तलाशने में लगे हैं, ताकि चुनाव के बाद किसी तरह प्रदेश की सत्ता में उन्हें भागीदारी मिल सके. चौधरी कभी समाजवादी पार्टी और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को कोसते हैं, तो कभी सपा से गठबंधन के प्रयास भी करते हैं. रालोद का जनता दल (यू) से तालमेल है, लेकिन चौधरी को भी पता है कि इससे उन्हें कोई फायदा नहीं मिलने वाला. रालोद किसी तरह अपनी आठ सीटें बढ़ा पाने की जद्दोजहद में लगा है. उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में छोटे-छोटे दलों की भूमिका रही है. कुछ छोटे दल सीटें जीतते भी रहे हैं और अधिकतर बड़ी पार्टियों के प्रत्याशियों को हरवाते भी रहे हैं. लिहाजा, बड़ी पार्टियां भी छोटे दलों को अपने साथ लेकर चलने में ही अपनी भलाई समझती हैं. उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोक दल के अलावा पीस पार्टी, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन (एआईएमआईएम), आम आदमी पार्टी, शिवसेना, अपना दल समेत कुछ अन्य छोटे दल भी इस चुनाव में अपनी भूमिका निभाएंगे. ये दल कुछ कहावर प्रत्याशियों की नाक में दम भी भरेंगे. उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए जनता दल (युनाईटेड), राष्ट्रीय जनता दल (राजद) राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और एआईएमआईएम भी काफी अर्से से सक्रिय हैं. बिहार से लगे उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में जदयू-राजद गठबंधन किसी भी बड़े दल को नुकसान पहुंचा सकता है. दूसरी तरफ ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुसलमीन (एआईआईएम) मुस्लिम मतदाताओं को अपनी तरफ खींच कर बड़े सेकुलर दलों को परेशान कर सकती है. ओवैसी खास तौर पर मायावती के लिए बेहद चुनौती वाले दल के नेता साबित हो सकते हैं. इन दलों के अलावा तृणमूल कांग्रेस, लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल (सेकुलर), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) जैसी पार्टियां भी उत्तर प्रदेश में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए लगातार सक्रिय और बेचैन हैं. तृणमूल कांग्रेस के पास तो एक विधायक पहले से है. बिहार चुनाव में भारी जीत से उत्साहित जनता दल(यू) ने देवरिया के रामपुर कारखाना विधानसभा सीट से जुझारू किसान नेता शिवाजी राय समेत उत्तर प्रदेश की अन्य विधानसभा सीटों से भी अपना प्रत्याशी उतारने की घोषणा की है. जद (यू) अध्यक्ष व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश में खासे सक्रिय हैं.

ऐसी स्थिति में सारे बड़े दल छोटे दलों के साथ तालमेल कर चलना चाहते हैं. उन्हें यह एहसास है कि पिछले चुनावों में इन दलों ने उनको किस हद तक नुकसान पहुंचाया था. पिछले विधानसभा चुनाव में पीस पार्टी ने चार, कौमी एकता दल ने दो और राष्ट्रवादी कांग्रेस, अपना दल, इत्तेहाद-ए-मिल्लत व तृणमूल कांग्रेस ने एक-एक सीटें जीती थीं. इन छोटे दलों ने सीटें चाहे जितनी भी जीती हों, पर इन्होंने कई सियासी समीकरण गड्डमड्ड कर के रख दिए थे. छोटे दलों के कारण ही लगभग दो दर्जन सीटों पर सपा, बसपा, भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी एक हजार या उससे भी कम वोट से चुनाव हार गए थे. उस चुनाव में रालोद नौ सीटों पर दूसरे स्थान पर, 14 पर तीसरे स्थान और पांच सीटों पर चौथे स्थान पर रहा था. पीस पार्टी तीन सीटों पर दूसरे स्थान पर, आठ सीटों पर तीसरे और 24 सीटों पर चौथे स्थान पर रही थी. इसके अलावा कौमी एकता दल ने एक सीट पर दूसरा स्थान, चार सीटों पर तीसरा और एक सीट पर चौथा स्थान प्राप्त कर के कई बड़े दलों के प्रत्याशियों की जीत में बाधा डाल दी थी. 2012 के विधानसभा चुनाव में अपना दल ने 76 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए थे. अपना दल का केवल एक ही प्रत्याशी जीता, लेकिन अपना दल दो सीटों पर दूसरे, सात सीटों पर तीसरे और सात सीटों पर चौथे स्थान पर रहा. इसी तरह कई अन्य छोटे दलों ने भी व्यापक पैमाने पर बड़े दलों के वोट काटे. यही वजह है कि कोई भी बड़ा दल इन छोटे दलों की उपेक्षा नहीं कर सकता.

अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ तालमेल कर सांसद बन गईं. अपना दल में भी महत्वाकांक्षाएं इस तरह प्रबल हुईं कि अनुप्रिया पटेल की मां कृष्णा पटेल और बहन पल्लवी पटेल ने मिल कर अनुप्रिया को ही पार्टी से निकाल दिया. कृष्णा पटेल उपचुनाव लड़ीं लेकिन हार गईं. उन्होंने अपना दल का अपना अलग गुट बना लिया है. अब कई दल उनके साथ तालमेल की कवायद कर रहे हैं. कुर्मी वोटों पर पकड़ के कारण अपना दल की पूछ बढ़ी हुई है. यही हाल पूर्वांचल में असर रखने वाली भारतीय समाज पार्टी का है. भासमा के अध्यक्ष पूर्व सांसद ओम प्रकाश राजभर भाजपा के साथ गठबंधन में शामिल हैं. पूर्वांचल में ही मुस्लिम मतदाताओं पर पकड़ रखने वाले कौमी एकता दल का समाजवादी पार्टी में विलय हो चुका है. संत कबीर नगर से विधायक डॉ. अय्यूब की पीस पार्टी पर भी कई दलों की निगाह है.

वोट के कुचक्र में मुस्लिमों को उलझाती हैं पार्टियां

सुप्रीम कोर्ट की राय जो भी हो, लेकिन जाति और धर्म को केंद्र में रख कर राजनीति होगी और इसे कोई नहीं रोक पाएगा. बसपा ने जिस तरह टिकट बांटे, समाजवादी पार्टी ने जिस तरह टिकट बांटे और कौमी एकता दल का विलय कराने के लिए अखिलेश यादव तक को ताक पर रख दिया उससे यही जाहिर हुआ कि जाति धर्म की राजनीति को रोकना मुमकिन नहीं है. राजनीतिक दलों ने खास तौर पर मुसलमानों को महज वोटों की गिनती बना डाला है. इसके लिए मुसलमान भी दोषी हैं. हर बार की तरह इस बार का चुनावी खेल भी मुसलमानों को ही दांव पर रख कर खेला जा रहा है. राजनीतिक दलों के झगड़े और रगड़े होते रहें, लेकिन इससे ये कयास क्यों लगने लगते हैं कि मुसलमान किधर जाएगा! राजनीतिक दलों द्वारा उठाए जाने वाले ऐसे सवालों के खिलाफ मुसलमानों की तरफ से विरोध क्यों नहीं होता! यह विचारणीय है. इस बार भी वही सवाल उठ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के झगड़े में मुसलमान किधर जाए? देश में करीब-करीब सारे राजनीतिक दल और खास तौर पर क्षेत्रीय दलों की पहचान तो जाति और धर्म को लेकर ही है. लेकिन कुछ खास सवाल मुसलमानों के लिए ही खास हो गए हैं. जबकि उत्तर प्रदेश में मुसलमान मतदाता निर्णायक भूमिका में है, लेकिन उसे ऐसे सवालों में फंसा कर रखा जाता है. यह भी सियासत का ही हिस्सा है. उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की आबादी 19 फीसदी से अधिक है. करीब 140 विधानसभा सीटों पर 10 से 20 फीसदी तक मुस्लिम आबादी है. 70 सीटों पर 20 से 30 फीसदी और 73 सीटों पर 30 फीसदी से अधिक मुस्लिम आबादी है. 140 सीटों पर मुस्लिम सीधे तौर पर असर डालते हैं. अधिक टिकट दिए जाने के कारण बसपा और अधिक तवज्जो दिए जाने के कारण एआईएमआईएम जैसी पार्टियां मुसलमानों का ध्यान अपनी ओर अधिक खींच रही हैं. बाबरी विध्वंस के बाद से उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मुस्लिम वोट मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी को मिले. यहां तक कि मुलायम को मुल्ला मुलायम तक कहा जाने लगा. लेकिन, सपा के हालिया पारिवारिक झगड़े के कारण यह कहा जाने लगा कि मुसलमान सपा से बिदक कर बसपा की तरफ जा रहा है. जबकि सर्वे संस्था सीएसडीएस के आंकड़े देखें तो आप पाएंगे कि सपा को मिलने वाले मस्लिम वोटों के प्रतिशत का ग्राफ 2002 के बाद से ही नीचे जा रहा है. 2002 के विधानसभा चुनाव में सपा को 54 फीसदी मुस्लिम वोट मिला था, जो 2007 के विधानसभा चुनावों में घटकर 45 फीसदी रह गया और 2012 के चुनावों में 39 फीसदी पर आ गया. जबकि समाजवादी पार्टी को 2012 में सबसे बड़ी जीत हासिल हुई. लिहाजा, पारिवारिक कलह के कारण अचानक मुस्लिमों का मुलायम से मोहभंग हो जाने का विश्लेषण सटीक नहीं है. मुस्लिम समुदाय के कुछ नागरिकों का कहना है कि किसी पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध वोटर महज इसलिए नहीं भाग खड़ा होता कि दल के अंदर कलह है. अलग-अलग किस्म की कलह और अंदरूनी झगड़े तो प्रत्येक दल में हैं. इलाहाबाद के डॉ. नूर आलम कहते हैं कि मुसलमान सपा से अलग नहीं हो सकते. हालांकि वे यह भी कहते हैं कि जो कुछ काम होना चाहिए था, उतना नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मुसलमान अखिलेश यादव या मुलायम सिंह से नाराज नहीं हैं. वे यह भी कहते हैं कि शिवपाल ने भी बहुत संघर्ष किया है, उनसे भी लोगों को हमदर्दी है. पार्टी के टूटने की हालत में वोटों का दोनों तरफ बिखराव हो सकता है. लखनऊ के फुरकान अहमद का कहना है कि मुसलमान मुलायम के साथ ही रहेंगे. उनके सामने कोई और विकल्प नहीं है. पूर्व विधायक शेख सुलेमान कहते हैं कि मुसलमानों के लिए नेताजी ने बहुत कुछ किया है. इसलिए मुसलमान नेताजी के साथ खड़े हैं, उनमें कोई बिखराव नहीं है. कन्नौज के हाजी जरार खां का कहना है कि मुसलमान अखिलेश के साथ हैं. पार्टी अगर बंटी तो मुसलमान अखिलेश के साथ चले जाएंगे. अखिलेश ने मुसलमानों को जो सहूलियतें दी हैं उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. मेरठ के गुलशेर मलिक कहते हैं कि मुसलमान तो अखिलेश की ही तरफ हैं. कब्रिस्तान की चारदीवारी बनाने का मसला हो या कई अन्य मामले, अखिलेश ने मुसलमानों के लिए बहुत काम कराए हैं. पार्टी में टूट हुई तो 80 फीसद मुसलमान अखिलेश की ही तरफ जाएंगे. बलिया के परवेज रौशन का कहना है कि जो लोग यह कह रहे हैं कि अखिलेश ने मुसलमानों के लिए काम नहीं किया, वे ठीक जानकारी नहीं रखते. अखिलेश ने मुसलमानों के लिए कोई गलत काम नहीं किया. मुलायम की असली विरासत हैं अखिलेश, इसलिए मुसलमान उनसे अलग नहीं हो सकते. पूर्वांचल के मोहसिन खान कहते हैं कि अगर टिकट का वितरण और उम्मीदवारों का चयन निष्पक्ष तरीके से हुआ तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सपा को ही स्पष्ट बहुमत मिलेगा. मोहसिन खान सपा के वे नेता हैं जिन्हें सपा के कलह का खामियाजा भुगतना पड़ा है. इसके बावजूद वे बसपाई दावे को पूरी तरह ठुकरा देते हैं. गोरखपुर के जिला अध्यक्ष मोहसिन खान और गोंडा के जिला अध्यक्ष मो. महफुज खान को हटा दिया गया था, लेकिन इनकी सपा के प्रति वफादारी कायम है. मोहम्मद मोहसिन खान स्टेट गेस्ट हाउस कांड में अभियुक्त बनाए गए थे और जेल भी गए थे. वह मुकदमा आज भी चल रहा है.

मुस्लिम बुद्धिजीवी डॉ. मोहम्मद सरफे आलम कहते हैं कि राजनीतिक विकल्प की छटपटाहट अन्य धर्म के मतदाताओं का एकाधिकार नहीं होती. मुस्लिम मतदाताओं में भी विकल्प की तलाश और छटपटाहट हो सकती है, और यह लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, इसका किसी खास राजनीतिक दल और किसी खास नेता से मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए. 2007 और 2012 के विधानसभा चुनाव में बसपा को मिला क्रमशः 17 प्रतिशत और 20 प्रतिशत मुस्लिम वोट और 2012 के ही चुनाव में कांग्रेस को हासिल हुआ 18 फीसद मुस्लिम वोट यही अभिव्यक्ति देता है. डॉ. आलम के विचार के बरक्स एक तथ्य यह भी है कि छोटे-मोटे आकर्षण और बदलती प्राथमिकताओं के कारण मुस्लिम वोट भी वैसे ही बंटता रहा है जैसे अन्य जाति-धर्म के मतदाताओं के वोट बंटते रहे हैं. उसमें विकल्प की तलाश कम, अवसरवाद की तलाश अधिक बड़ी वजह होती है. हैदराबाद के मुस्लिम नेता असदुद्दीन ओवैसी द्वारा या पीस पार्टी या कौम एकता दल जैसी पार्टियों द्वारा मुसलमानों का वोट काट लेना आखिर क्या है! अब छोटे-छोटे मुस्लिम संगठनों को मिला कर बने इत्तेहाद फ्रंट की भूमिका क्या होगी, इसे आसानी से समझा जा सकता है. एक तरफ बसपा दलितों और मुसलमानों का साझा समीकरण बनाने की कवायद कर रही है तो दूसरी तरफ ओवैसी की राजनीति भी दलित और मुस्लिम गठजोड़ पर केंद्रित है. ओवैसी अपनी सभी सभाओं में मुस्लिमों और दलितों की एकता पर जोर देते हैं. ओवैसी से बड़े दल इतने आशंकित रहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने तो उत्तर प्रदेश में उनकी कई सभाएं नहीं होने दीं. उत्तर प्रदेश में 30 फीसदी तक वोट पाने वाली पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती है. इसीलिए मायावती दलितों और मुस्लिमों को मिला कर 39 फीसदी वोट पाने और सत्ता हासिल करने का सपना देख रही हैं. राजनीतिक विश्लेषक यह भी मानते हैं कि अगर सपा के अखिलेश गुट का गठबंधन कांग्रेस से हो जाए तो मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ चला जाएगा. भाजपा के साथ मिल कर दो-दो बार सरकार बनाने वाली मायावती के प्रति मुस्लिम समुदाय का संशय बना रहता है. सपा और कांग्रेस का गठबंधन मुसलमानों को भाजपा का रास्ता रोकने के प्रति आश्वस्त कर सकता है. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 403 में से 253 विधानसभा क्षेत्रों में 40 फीसदी से ज्यादा वोट मिले थे. 94 विधानसभा क्षेत्रों में उसे 50 फीसदी से ज्यादा वोट मिले थे. लिहाजा, वोटों का बदलता प्रतिशत चुनावी आकलनों को इधर-उधर भी कर सकता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

फोटो : प्रभात पाण्डेय

तो ऐसे होंगे यूपी में चुनाव

उत्तर प्रदेश में सात विभिन्न चरणों में चुनाव होगा जो 11 फरवरी से 8 मार्च के बीच चलेगा. यूपी में पहले चरण का चुनाव 11 फरवरी को होगा जिसमें 15 जिलों की 73 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव कराए जाएंगे. दूसरे चरण में 11 जिलों की 67 विधानसभा सीटों के लिए 15 फरवरी को चुनाव कराए जाएंगे. तीसरे चरण में 12 जिलों की 69 विधानसभा सीटों के लिए 19 फरवरी को चुनाव होंगे. चौथे चरण में 12 जिलों की 53 विधानसभा सीटों के लिए 23 फरवरी को चुनाव होंगे. पांचवें चरण में 11 जिलों की 52 विधानसभा सीटों के लिए 27 फरवरी को चुनाव कराए जाएंगे. छठे चरण में सात जिलों की 49 विधानसभा सीटों के लिए 4 मार्च को चुनाव होंगे. आखिरी सातवें चरण में सात जिलों की 40 विधानसभा सीटों के लिए 8 मार्च को चुनाव होंगे.

सात चरणों में चुनाव असंवैधानिक

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक पांडेय ने उत्तर प्रदेश में सात चरणों में विधानसभा चुनाव कराने के चुनाव आयोग के फैसले को असंवैधानिक और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करार दिया है. अशोक पांडेय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सात चरणों में चुनाव कराने के आयोग के फैसले को खारिज कर, दो चरणों में सम्पूर्ण चुनाव निष्पादित करने का आदेश जारी करने का अदालत से आग्रह किया है. श्री पांडेय ने उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में एक फेज़ में और मणिपुर में दो फेज़ में चुनाव कराने के निर्णय का हवाला देते हुए उत्तर प्रदेश में सात चरणों में चुनाव कराने के फैसले को कानूनी चुनौती देते हुए इस फैसले को चुनाव आयोग की साजिश करार दिया है. उनका कहना है कि लंबे अर्से से यूपी में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे हैं. चुनाव के दरम्यान प्रदेश में कहीं भी हिंसा या दंगा-फसाद की घटना नहीं घट रही, फिर किस आधार पर चुनाव आयोग ने यूपी के चुनाव सात लंबे, उबाऊ और खर्चीले चरणों में निपटाने का निर्णय लिया? वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक पांडेय ने कहा है कि चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश और बिहार को भेदभाव की निगाह से देखता है, जबकि इन दोनों राज्यों में लगातार शांतिपूर्ण चुनाव संपादित हो रहे हैं. पिछली बार बिहार में भी विधानसभा चुनाव पांच चरणों में कराए गए. जबकि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान के विधानसभा चुनाव एक ही फेज़ में कराए गए थे. श्री पांडेय ने सात चरणों में यूपी में चुनाव कराए जाने को षड्यंत्र बताया और कहा कि मतदाताओं को दबाव में लेकर वोट प्रभावित करने वाले माफिया और गुंडा तत्वों को एक फेज़ में अपना काम निपटाने के बाद दूसरे फेज़ के लिए दूसरे स्थान पर रवाना होने का मौका दिया जा रहा है. इसलिए इस चुनाव कार्यक्रम को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाना चाहिए. हाईकोर्ट का इस ओर भी ध्यान दिलाया गया कि चुनाव में लंबा-लंबा गैप देकर बाद के चरणों वाले चुनाव क्षेत्रों में प्रत्याशियों को प्रचार के लिए अधिक समय मिलना प्रथम चरण वाले प्रत्याशियों के मौलिक अधिकारों का सरासर उल्लंघन है. वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना है कि इस तरह का फैसला चुनाव आयोग के अधिकारियों का नियोजित षड्यंत्र है.

नोटबंदी

पचास दिन के पचास भद्दे रंग

शफीक आलम

नोटबन्दी के 50 दिन पूरे हो गए. 8 नवम्बर को नोटबंदी की घोषणा करते हुए अपने टेलीवाइज़ भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने खास अंदाज में कहा था कि आज मध्य रात्रि यानी 8 नवम्बर 2016 के रात 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे. उनकी इस घोषणा से देश में प्रचलित लगभग 86 प्रतिशत करेंसी गैरकानूनी हो गई. उनकी घोषणा तक आम जनता को यह एहसास नहीं था कि आने वाले दिनों में उन्हें किसी तरह की परेशानी उठानी पड़ेगी. आम लोग यही सोच रहे थे कि अगर सरकार इन नोटों का प्रचलन समाप्त कर रही है तो उसने अवश्य ही इसका उचित वैकल्पिक प्रबन्ध कर रखा होगा. दो दिन बाद अवश्य उनको पुराने नोटों के बदले नये नोट मिलने लगेंगे. लेकिन दो दिन बाद जो हुआ उसकी मिसाल शायद ही किसी और देश में मिले.

नोटबंदी का विरोध

नोटबन्दी की शुरुआत प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन से हुई थी. दिलचस्प बात यह रही कि दूरदर्शन पर प्रधानमंत्री के संबोधन को लाइव (सीधा प्रसारण) दिखाया गया था, लेकिन बाद में दूरदर्शन के ही एक पत्रकार ने यह दावा किया कि यह प्रसारण रिकॉर्डेड था. बहरहाल, दो दिन बाद का नज़ारा बड़ा विहंगम था. बैंकों के सामने लोगों की सैकड़ों मीटर लाइनें लगने लगीं, लोगों की जेबें पैसा रहते हुए भी खाली हो गईं और देश के अलग-अलग क्षेत्रों से लोगों की मरने की ख़बरें आने लगीं. इस अव्यवस्था को देख हर तरफ से इस फैसले की आलोचना होने लगी. आलोचकों में अर्थशास्त्री, विपक्ष के नेता, कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं एवं विदेशी अखबारों और यहां तक कि ऐसे बैंकर्स जिन्होंने पहले इस क़दम की सराहना की थी भी शामिल हो गए. आम तौर पर उनका मत था कि सरकार ने जनता को एक ऐसी परेशानी में डाल दिया है, जिसका कोई ख़ास फायदा नहीं होने वाला. विपक्ष ने शुरू में इस फैसले के खिलाफ एकजुटता दिखाने का प्रयास किया, लेकिन बाद में एकजुट नहीं रह पाया.

समर्थन और अफवाहों का बाज़ार

ज़ाहिर है जहां आलोचक थे, वहीं उसके हिमायती भी थे. जब नोटबंदी से लोगों की परेशानियां बढ़ने लगीं तो फैसले के पक्षधर लोगों

ने यह कहना शुरू कर दिया कि जब सैनिक सीमा पर खड़े रह कर देश की सेवा कर सकते हैं तो देश-हित में आम जनता लाइनों में खड़ी होकर थोड़ी परेशानी क्यों नहीं उठा सकती है? नोटबंदी को राष्ट्रवाद से जोड़ने वालों में फिल्म अभिनेताओं से लेकर भाजपा के पहली पंक्ति के नेता तक शामिल थे. हाल में दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी का एक विडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें वो कथित तौर पर हंसी उड़ाने की मुद्रा में यह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देश भक्त हैं क़तार में, लगी है भारी भीड़ / नोटबंदी से संवर रही भारत की तकदीर. उनके मुताबिक यह गीत सुनने के बाद कतार में खड़े लोगों ने कहा कि देश के लिए वो 30 दिसम्बर तक यहां खड़े रहने के लिए तैयार हैं. इस विडियो में जब मनोज तिवारी ये बातें कह रहे हैं, तो वहां मौजूद भाजपा के वो चेहरे जो अक्सर टीवी पर दिखाई देते हैं, भी कहकहे लगाते दिख रहे हैं. यह बड़ी हैरानी की बात है कि मेनस्ट्रीम मीडिया ने इस वायरल विडियो का कोई नोटिस नहीं लिया.

लेकिन हकीकत यह है कि देशभक्ति का नुस्खा इतना कारगर साबित हुआ कि लोगों को परेशानी तो हो रही थी लेकिन कोई खुल कर अपनी मुसीबत ज़ाहिर नहीं कर रहा था. जहां तक मीडिया का संबंध है तो पहले दिन से टीवी चैनलों ने यह दिखाना शुरू किया कि लोगों को इस फैसले से तकलीफ तो हो रही है लेकिन लोग अपनी ख़ुशी से लाइन में लगे हैं. एक टीवी चैनल ने तो यह तक खबर चला दी कि इन नोटों में चिप लगी हुई है. लिहाज़ा इनपर सेटेलाइट से नज़र रखी जाएगी. हालांकि सरकारी तौर पर इस खबर का खंडन किया गया, लेकिन तीर निशाने पर लग चुका था. जब देश से रोजाना नए नोटों के पकड़े जाने की खबरें आने लगीं तो लोगों को यह लगा कि यह नोटों में लगे चिप की वजह से हो रहा है.

अफवाहों का सिलसिला यहीं नहीं रुका. एक अफवाह सोशल मीडिया पर वायरल हुई कि 2000 के नए नोटों में ऐसी सियाही इस्तेमाल हुई है, जो दो साल बाद खुद ब खुद उड़ जाएगी और ये नोट बेकार हो जाएंगे. साथ में यह भी कहा गया कि एक साल बाद 2000 के नोटों को फिर से समाप्त कर दिया जाएगा. इन नोटों पर रेडियो एक्टिव मटेरियल की होने की बात भी उड़ाई गई. अब सरकार ने ऐसी अफवाहों पर अपनी चुप्पी साध रखी है.

सरकार के सुर बदलते गए

सरकार को जल्द यह अहसास हो गया कि जिस मकसद के लिए नोटबंदी लागू की गई है, वह मकसद पूरा नहीं होगा. इस फैसले को लागू करने में जल्दबाज़ी हुई है, तो सरकारी सतह पर रोजाना नए फरमान जारी होने लगे. लोगों की अंगुलियों पर नोट बदलने के क्रम में सियाही लगने लगी. समाह में 20,000 रुपए की निकासी की सीमा घटा कर 4000 रुपए कर दी गई. रिज़र्व बैंक की शाखाओं में 31 मार्च 2017 तक पुराने नोट केवल एनआरआई ही जमा कर सकते हैं, इत्यादि. इस संबंध में सबसे बड़ी विडंबना यह थी कि प्रधानमंत्री ने नोटबंदी के फैसले को आतंकवाद, जालीनोट और कालाधन पर हमला करार दिया था, लेकिन कुछ दिनों बाद ही कश्मीर में दो आतंकी मारे गए, जिनके पास से दो हज़ार के नए नोट बरामद हुए. कश्मीर में पांच महीनों से जारी प्रदर्शन में कमी को भी नोटबंदी से जोड़ कर देखा गया, जिसकी सत्यता अलग बहस का विषय है. कालाधन के बारे में यह कहा गया कि देश में जो कुल 14 या 15 लाख करोड़ करेंसी प्रचलित है, उनमें से तकरीबन चार या पांच लाख करेंसी कालाधन है, जो सिस्टम में नहीं आएगा. लेकिन 30 दिसम्बर की अंतिम सीमा से बहुत पहले ही रिज़र्व बैंक के हवाले से छपी आखिरी रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि 12 लाख करोड़ से अधिक की करेंसी वापस सिस्टम में आ चुकी है. लेकिन प्रधानमंत्री ने 30 दिसम्बर के अपने राष्ट्र के संबोधन में यह ज़िक्र नहीं किया कि कितना पैसा सिस्टम में वापस आया और कितना नहीं आया.

कालाधन से कैशलेस की ओर

जब उपरोक्त मकसद में कामयाबी की उम्मीद समाप्त हो गई, तो बड़ी होशियारी से नोटबंदी की पूरी कवायद को कैशलेस इकोनॉमी की तरफ मोड़ दिया गया. ज़ाहिर है यह भी नोटबंदी की तरह बिना सोच-विचार के किया गया फैसला है. जिस देश में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 30 प्रतिशत आबादी अपना नाम भी नहीं लिख सकती और शेष आबादी में से विशाल संख्या ऐसे लोगों की है, जो केवल अपना नाम ही लिख सकते हैं, सरकार उनसे यह उम्मीद कर रही है कि वे मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन पैसों का लेन-देन कर सकेंगे. दूसरा सवाल यह है कि क्या कैशलेस इकोनॉमी में जाने के लिए देश ने ऐसी ऑनलाइन टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है, जो आम लोगों की खून पसीने की कमाई को सुरक्षित रख सके? क्या देश में इंटरनेट सेवा विश्वस्तरीय हो गई है या 1991 से लागू नव उदारवादी अर्थव्यवस्था के तहत विकास की दौड़ से देश की 80 प्रतिशत आबादी जो पहले ही बाहर है, कहीं यह क़वायद उसे और अधिक हाशिए पर धकेलने के लिए तो नहीं की गई है? उन ग्रामीण क्षेत्रों का क्या, जहां बैंकों तक जाने के लिए 20 किलोमीटर तक का सफ़र तय करना पड़ता है?

बहरहाल नोटबंदी के बाद की स्थिति से निपटने के लिए प्रधानमंत्री ने जनता को जो 50 दिन का समय दिया था, वह समाप्त हो गया है. लेकिन आम लोगों की परेशानियां समाप्त नहीं हुई हैं. बड़े शहरों में रहने वाले लोगों को थोड़ी राहत इन मायनों में मिली है कि एटीएम के सामने लगने वाली लंबी लाइनें थोड़ी छोटी हो गई हैं, लेकिन जिस एटीएम से कैश मिलने की संभावना है, वहां लोग ज़रूर खड़े मिल रहे हैं. ऐसे में जब राजधानी दिल्ली और एनसीआर के अधिकतर एटीएम अब भी कैश की राह देख रहे हैं, तो देश के ग्रामीण क्षेत्रों की बात कौन करे? ■

feedback@chauthiduniya.com

प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संदेश

देश ने 50 दिन दिया, देश को क्या मिला

शशि शेखर

कम बोलना ज्यादा बोलने से कम खतरनाक होता है. इस बात को हाल के वर्षों में किसी ने सही तरीके से समझा था तो वो थे तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव. अल्पमत सरकार को 5 साल तक बिना किसी परेशानी के चलाने, आर्थिक उदारीकरण जैसा कड़ा निर्णय लेने और उसे क्रियान्वित करने में वे शायद इसीलिए सफल हुए क्योंकि उन्होंने कम बोलने के महत्व को समझा था. बहरहाल, इस बात को याद करना इसलिए जरूरी है, क्योंकि मौजूदा प्रधानमंत्री बोलते हैं और खूब बोलते हैं. वो शायद इसलिए भी बोलते हैं कि जनता ने पिछले दस साल के दौरान एक कम बोलने वाले प्रधानमंत्री को देखा था और जनता भी चाहती है कि हमारे प्रधानमंत्री खूब बोलें.

अगले ढाई साल में क्या ये संख्या बढ़ेगी?

31 दिसंबर की शाम को जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की समयसीमा समाप्त होने के बाद देश को संबोधित किया, तो उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही. उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ एक जानकारी साझा करना चाहता हूं. इसे सुनने के बाद या तो आप हंस पड़ेंगे या फिर आपका गुस्सा फूट पड़ेगा. उन्होंने कहा कि सरकार के पास दर्ज की गई जानकारी के मुताबिक देश में सिर्फ 24 लाख लोग ये मानते हैं कि उनकी आय 10 लाख रुपए सालाना से ज्यादा है. क्या किसी देशवासी के गले ये बात उतरेगी? देश के बड़े-बड़े शहरों को ही देखें तो किसी एक शहर में आपको सालाना 10 लाख से अधिक आय वाले लाखों लोग मिल जाएंगे. बहरहाल, इसके पीछे का अर्थशास्त्र क्या है, तकनीकी बातें क्या हैं, ये तो अलग है, लेकिन नोटबंदी अगर सफल हुआ है, सरकार की मानें, तो अगले ढाई साल में ऐसे लोगों की संख्या में एक महत्वपूर्ण वृद्धि तो होनी ही चाहिए. यानी, सरकार के सामने यह प्रमुख चुनौती होगी कि वो अगले ढाई सालों में दस लाख रुपए से अधिक की सालाना कमाई घोषित करने वाले लोगों की संख्या को 24 लाख से बढ़ाए.

राजनीतिक दलों ने कौन सा बन्धन स्वीकार किया है?

राष्ट्र के नाम अपने सन्देश में प्रधानमंत्री ने एक अहम मुद्दे को सिर्फ छुआ भर. उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार, कालाधन की जब भी चर्चा होती है, तो राजनेता, राजनीतिक दल, चुनाव खर्च, ये सभी बातें चर्चा के केंद्र में रहती हैं. अब वक्त आ चुका है कि सभी राजनेता और राजनीतिक दल देश के ईमानदार नागरिकों की भावनाओं का आदर करें, जनता के आक्रोश को समझें. यह बात सही है कि राजनीतिक दलों ने समय-समय पर व्यवस्था में सुधार के लिए सार्थक प्रयास भी किए हैं. सभी दलों ने मिलकर, स्वेच्छा से अपने ऊपर बंधनों को स्वीकार किया है. सवाल ये है कि एक अदद सूचना का अधिकार कानून के तहत राजनीतिक दलों को लाने का आदेश केन्द्रीय सूचना आयोग ने दिया था. उस आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए सभी राजनीतिक दल एक हो गए और इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी. यही नहीं, राजनीतिक दलों को आरटीआई कानून के दायरे से बाहर रखने के लिए सभी दलों ने तमाम तरह के कुतर्क दिए. इसमें कांग्रेस, भाजपा, वाम दल सभी शामिल हैं. आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने अपने चन्दे (20 हजार रुपए से कम के चन्दे) का स्रोत तक नहीं बताया है. एक अनुमान के मुताबिक, 2014 का लोक सभा चुनाव अब तक का सबसे महंगा चुनाव था. अनुमानतः, उस चुनाव में तीस हजार करोड़ रुपए खर्च हुए थे. लेकिन, जब चुनाव आयोग को खर्च की जानकारी दी गई तो इसमें प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दलों (कांग्रेस और भाजपा समेत) ने अपना खर्च महज कुछ करोड़ रुपए बताया. सवाल है कि अब तक इन राजनीतिक दलों ने अपने ऊपर कौन सा बन्धन स्वीकार किया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस और भाजपा, दोनों को विदेशी कंपनी से चन्दा लेने का दोषी पाया, दोनों इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए. क्या इसी राजनीतिक शुचिता की दुहाई दी जा रही है? इलेक्टोरल ट्रस्ट से सभी प्रमुख दल चन्दा लेते हैं. क्या आज तक जनता को ये पता भी है कि इन इलेक्टोरल ट्रस्ट को बनाया किन औद्योगिक घरानों ने है? कौन सा औद्योगिक घराना इस इलेक्टोरल ट्रस्ट के माध्यम से किसे कितना चन्दा दे रहा है? होना तो ये चाहिए था कि प्रधानमंत्री घोषणा करते कि आज से राजनीतिक दलों के चन्दे को आरटीआई कानून के तहत लाया जा रहा है. जाहिर है, इस फैसले का जनता तो स्वागत करती ही, यह भी साफ हो जाता कि कौन से राजनीतिक दल हैं, जो इसका विरोध कर रहे हैं.

दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस और भाजपा, दोनों को विदेशी कंपनी से चन्दा लेने का दोषी पाया, दोनों इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए. क्या इसी राजनीतिक शुचिता की दुहाई दी जा रही है? इलेक्टोरल ट्रस्ट से सभी प्रमुख दल चन्दा लेते हैं. क्या आज तक जनता को ये पता भी है कि इन इलेक्टोरल ट्रस्ट को बनाया किन औद्योगिक घरानों ने है? कौन सा औद्योगिक घराना इस इलेक्टोरल ट्रस्ट के माध्यम से किसे कितना चन्दा दे रहा है?

बातें जो अनकही रह गईं...

किसानों और गर्भवती महिलाओं के लिए जैसी घोषणाएं हुईं, उससे भी सवाल उठता है. कहां तो किसान अपने लिए किसी बड़े राहत की उम्मीद लगाए थे, वहीं महज 60 दिनों की ब्याज माफी जैसी घोषणा सुनने को मिली. यह राहत ठीक उसी तरह की रही, जैसे खोदा पहाड़ और निकली चुहिया, वो भी मरी हुई. गर्भवती महिलाओं को 6 हजार रुपए देने की बात कही गई. हालांकि, यह योजना पहले से चली आ रही है, बस इसका दायरा और रकम की सीमा बढ़ाई गई है. लेकिन, इस पूरे भाषण के दौरान ऐसे भी कई मुद्दे रहे, जिस पर जनता प्रधानमंत्री की मन की बात सुनना चाहती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. मसलन, 50 दिनों बाद सरकार को कितना कालाधन मिला? तकरीबन 15 लाख करोड़ रुपए (करेंसी इन सर्कुलेशन) में से कितना पैसा अंतिम तौर पर बैंकों में आया और कितना कालाधन के रूप में बाहर रह गया? उन्होंने बेनामी संपत्ति को लेकर कुछ नहीं कहा, जैसा कि लोग उम्मीद कर रहे थे. प्रधानमंत्री ने यह भी नहीं बताया कि इस पूरे नोटबंदी के कार्यक्रम पर सरकार का कितना पैसा खर्च हुआ? उन्होंने ये भी नहीं बताया कि बैंकों में सामान्य स्थिति कब तक लौटेगी और लोग कब तक बैंकों और एटीएम से अपनी मर्जी और जरूरत के हिसाब से पैसा निकाल सकेंगे? ■

feedback@chauthiduniya.com

नोटबंदी

वे नौकरी से निकालते रहे सरकार फायदे गिनाती रही

चंदन राय

हम भला क्या कर सकते हैं? सरकार ही नियम बनाती है और हमें उसे मानना पड़ता है. सरकार तक हम अपनी आवाज कैसे पहुंचाएं, ये कहते हुए बिहार के जुनैद आलम की आंखें भर आती हैं. जुनैद दिल्ली में बुराड़ी स्थित एक फैक्ट्री में साड़ी में जरी लगाने का काम करते थे. नोटबंदी के दौरान उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, तब से वे अच्छे दिनों की आस में रैन बसेरे में शरण लिए हैं. उन्हें उम्मीद है कि सरकार जल्द ही उन जैसे कामगारों के लिए कुछ राहत की घोषणाएं करेगी. नोटबंदी की मार झेल रहे अलीगढ़ के ताला उद्योग व कानपुर के चमड़ा उद्योग में मातम पसरा है. कमोबेश यही स्थिति सोलापुर व सूरत के सूती कपड़ा उद्योग, कोलकाता के जूट उद्योग, मिर्जापुर के कालीन व बनारस के साड़ी उद्योग की भी है. हर जगह काम ठप पड़ा है. दिहाड़ी मजदूरों को भुगतान नहीं दे पाने की स्थिति में उन्हें फैक्ट्री से निकाल दिया गया है. हालत ये है कि असम के चाय बागानों के मालिक व ठेकेदार, मजदूरों को भुगतान देने के डर से बागान छोड़कर चले गए हैं.

नोटबंदी के सर्जिकल स्ट्राइक ने देश में असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे कामगारों व माइनॉरिटी तबके की कमर तोड़ कर रख दी है. ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 80 फीसदी लोगों के लिए असंगठित क्षेत्र ही रोजगार व आमदनी का जरिया है. लेकिन हाल ये है कि देश भर में 27 करोड़ दिहाड़ी मजदूरों में से अधिकतर बेगार हो चुके हैं. एक अनुमान है कि गुरुद्वारों में होने वाले लंगर में दो महीनों के भीतर तीस फीसद का इजाफा हुआ है.

उठ गया सरकार का इकबाल

नोटबंदी के दौरान सरकार ने अपनी विश्वसनीयता खोई है और बैंकों ने अपनी साख. नोटबंदी के बाद देश जिस हालात में पहुंच गया है, वहां से निकलने के लगभग सभी रास्ते बंद हैं. इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर के निदेशक प्रणव सेन बताते हैं, इस फैसले ने सबसे ज्यादा असंगठित क्षेत्र को प्रभावित किया है. इसे लगभग स्थायी रूप से बर्बाद कर दिया है. कानपुर में जमाल एक जूते की फैक्ट्री में काम करते थे. बताते हैं, दिसंबर महीने में ठेकेदार ने 500 रुपए के पुराने नोट वेतन के रूप में दिए थे. उसी समय कई कामगारों से हिसाब कर लेने के लिए कह दिया गया. जब हाथ में नोट ही नहीं हैं, तो फिर काहे कि नोटबंदी? नोटबंदी ने तो हमारी नौकरी ही छीन ली. सरकार हमें नौकरी क्या देती, चलती हुई नौकरी भी चली गई. मुसलमान कामगार नोटबंदी से ज्यादा परेशान हैं. सूद को हराम समझने के कारण ज्यादातर मुस्लिम कामगार बैंक खाता नहीं रखते हैं. इतना ही नहीं, कैश पर व्यापार करने वाले मुस्लिम व्यापारी भी नोटबंदी से परेशान हैं.

नवंबर में नोटबंदी के कारण टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन आदि की बिक्री 38 फीसदी तक घट गई. जूते, कपड़े बनाने वाली फैक्ट्रियों में ताले लटक गए. छोटे-मंझोले कल-कारखाने बंद हो गए. तांबे की चीजों के लिए मशहूर मुरादाबाद, साइकल व खेल का सामान बनाने वाला लुधियाना, चूड़ियों का शहर फिरोजाबाद व गंजी के कपड़ों के शहर तिरुपुर में मुर्दानगी छाई है. इन उद्योगों में मंदी पहले से थी, अब नोटबंदी ने और हालत खराब कर दी है. इस कहर ने हजारों मजदूरों को शहरों से भाग कर फिर से गांवों में पनाह लेने के लिए मजबूर कर दिया. वहीं, शहरों में दुकानें तो खुली हैं, लेकिन बाजारों में सन्नाटा पसरा है. दिल्ली में एक गारमेंट विक्रेता ने बताया कि लोग 2000 रुपए के नोट लेकर आ रहे हैं. बाजार में छुट्टा है नहीं. हालत ये है कि अब कारोबार बंद करने की नौबत आ गई है.

झोलाछाप अर्थशास्त्रियों ने किया बेहाल

हाल में नोटबंदी के फायदे गिनाते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली कह रहे थे कि इस फैसले के 50 दिन बाद आलोचक गलत साबित हो रहे हैं. हालात उतने खराब नहीं हैं, जितने आलोचक बता रहे हैं. नोटबंदी का एकाध तिमाही में आर्थिक वृद्धि पर प्रतिकूल असर पड़ सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. वहीं अर्थशास्त्री बता रहे हैं कि अगर किसी के शरीर से 86 प्रतिशत खून निकाल दिया जाए, तो मल्टी ऑर्गन फेल्यूर होना लाजिमी है. ठीक ऐसा ही भारत की अर्थव्यवस्था के साथ हो रहा है. अर्थशास्त्री उत्सा पटनायक कहती हैं कि पेशेवर अर्थशास्त्रियों की जगह झोलाछाप किस्म के लोगों की सलाह पर चलने के कारण सरकार ने यह आत्मघाती कदम उठाया है. ■

ताला उद्योग तो जाने दें, ईंट भट्ठा भी बंद

अलीगढ़ मशहूर है ताला उद्योग के लिए, लेकिन एक और कारोबार है, जिसमें 95 हजार से अधिक कामगार दिन-रात काम में जुटे रहते हैं. जिले में 750 से ज्यादा ईंट-भट्ठे हैं. मोहम्मद शरीफ बताते हैं कि वे झारखंड से हैं. यहां बैंक खाता तो है नहीं. अगर खाता होता, तब भी भट्ठा मालिक काम छोड़कर जाने नहीं देगा. नगदी में भुगतान होता था, अब वह भी काम नहीं मिलने से बंद हो गया है. घर लौटने के अलावा कोई चारा नहीं है. वहीं भट्ठा मालिकों की अलग पीड़ा है. भट्ठा मालिक शमशेर बताते हैं नोटबंदी के कारण ईंट की बिक्री पर असर पड़ा है. हाथ में नगदी है नहीं, तो मजदूरों को कहां से वेतन दें. मजबूरन ईंट-भट्ठा बंद करना पड़ा है.

मालेगांव में थम गए हैंडलूम्स के पहिए

महाराष्ट्र का टेक्स्टाइल शहर मालेगांव अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, महंगे बिजली बिल और लेबर लॉज के कारण पहले ही मंदी की मार झेल रहा था. अब नोटबंदी की मार ने यहां के 80 हजार कामगारों को नाउम्मीदी के अंधेरे में धकेल दिया है. चौबीस घंटे चलने वाले हैंडलूम्स कैश के अभाव में अब सप्ताह में तीन दिन ही चलते हैं. पावरलूम उद्योग में कॉटन खरीदने से लेकर कामगारों को पगार देने व तैयार माल बेचने तक का काम कैश में ही होता है. सौ साल से ज्यादा पुराना यह उद्योग, जहां कभी दस करोड़ रुपए प्रतिदिन की आमदनी थी, आज बंद होने के कगार पर है. टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के एक सर्वे के अनुसार, हैंडलूम सेक्टर में कामगारों को औसतन 911 रुपए मासिक पगार मिलती है, लेकिन नौकरी छूटी, तो अब कामगारों को उसका भी आसरा नहीं रहा.

मनरेगा मजदूरों के हाथ खाली

शहरी गरीबों के लिए सरकार के पास रोजगार नहीं है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में भी मनरेगा के तहत अब कामगारों को काम नहीं मिल रहा है. नोटबंदी के दौरान मनरेगा मजदूरों की हालत बदतर हो गई है. उन्हें भुगतान देने के लिए स्थानीय प्रशासन के पास नकदी उपलब्ध नहीं है. अगर आंकड़ों की बात करें तो अक्टूबर माह के मुकाबले नवंबर में मनरेगा के तहत 23 फीसद रोजगार घट गया था. दिसंबर तक यह आंकड़ा 55 फीसद को पार कर गया. सवाल ये है कि अगर ग्रामीण व शहरी इलाकों के करोड़ों मजदूरों को रोजगार न मिले, तो फिर वे करें क्या? इस अराजकता की स्थिति से निपटने के लिए सरकार विकल्पहीनता की स्थिति में आ चुकी है. सरकार को अंदेशा है कि अगर हालात जल्द नहीं सुधरे, तो उसे लोगों के आक्रोश का शिकार होना पड़ सकता है. वहीं अर्थशास्त्रियों का आकलन है कि मुद्रा का चलन सामान्य स्थिति में आने में कम-से-कम 6 माह लग सकते हैं. आगामी चुनाव को देखते हुए मतदाताओं को लुभाने के लिए तरह-तरह के सब्जबाग दिखाए जा रहे हैं, लोक-लुभावन घोषणाएं की जा रही हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

नोटबंदी

इस फैसले ने किसानों को और मार दिया

निरंजन मिश्रा

कृषि आधारित अर्थव्यवस्था कहे जाने वाले भारत में आर्थिक फैसले और विकास के पैमानों का आधार अब ग्रामीण भारत से शहरी भारत की तरफ खिसक रहा है. अगर ऐसा नहीं होता, तो नोटबंदी की सफलता की कहानी में कृषि और किसानों पर इसके कुप्रभावों का भी सरकारी या सियासी उल्लेख मिलता. मेट्रो शहरों के मॉल में लोगों की बढ़ती भीड़, एटीएम के सामने कम होती कतारों और बाजारों की रौनक से नोटबंदी के प्रभावों का विश्लेषण हुआ. नोटबंदी को देशहित और देशभक्ति से जोड़ने वाले सियासी शोर के बीच वे दृश्य कहीं दब गए, जहां अपने पसीने से सींचकर उपजाए गए आलू को कौड़ियों के भाव बेचने की जगह एक किसान ने उसे आप-पड़ोस के लोगों में मुफ्त में बांट देना अच्छा समझा. एक किसान ने अपने खेत के पूरे टमाटर को मवेशियों को खिला दिया, क्योंकि फायदा और लागत तो दूर, उसे बेचने पर मिलने वाले पैसों से बाजार तक माल पहुंचाने का खर्च भी नहीं निकल सकता था. कर्नाटक के कोल्लार के किसानों को तो पहले ही फसलों पर कम बारिश की मार से दो-चार होना पड़ा था. रही-सही कसर नोटबंदी ने पूरी कर दी. अलबत्ता किसानों ने खेतों से निकले टमाटर को मवेशियों को खिलाना ही बेहतर समझा. नोटबंदी के बाद यह भी खबर सुनने को मिली कि जमीन की कीमत गिर जाने के बाद किसान ने खुदकुशी कर ली. तेलंगाना के सिद्दिपेट जिले के धर्मागम गांव में एक किसान वी. बलैया ने अपने परिवार के तीन अन्य सदस्यों के साथ कीटनाशक खा कर खुदकुशी कर ली, क्योंकि नोटबंदी के बाद उसके उस जमीन की कीमत आधी मिल रही थी, जिसे बेचकर वह अपनी बेटी की शादी करने वाला था. देश के कई अन्य हिस्सों से भी किसानों की खुदकुशी की खबरें आईं.

नहीं मिल रहा न्यूनतम समर्थन मूल्य

नोटबंदी के बाद सब्जियों की कीमतों में कमी देखी जा रही है. लेकिन यह कमी खुशखबरी की बात नहीं है. बाजारों तक फल और सब्जियां पहुंचाने वाले किसान मजबूरीवश औने-पौने दामों में अपनी सब्जियां, फल और दाल बेचने को मजबूर हैं. हाल ये है कि मंडियों में किसानों को उनके उत्पाद का लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है. खुदरा व्यापारियों के पास कैश की कमी के कारण मार थोक विक्रेता किसानों पर पड़ रही है. न्यूनतम समर्थन मूल्य में हुई भारी कमी ने किसानों की कमर तोड़ कर रख दी है. बात चाहे नवी मुंबई के एपीएमसी मार्केट की हो या दिल्ली के आजादपुर मंडी की, सभी जगहों पर एमएसपी में 40-50 फीसदी की कमी देखने को मिल रही है. कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा नोटबंदी के बाद के हालात को कृषि और किसानों के लिए संकट मानते हैं. उनका कहना है, 'यह एक तरह से संकट ही है कि लगातार दो साल के सूखे के बाद किसान अभी हालात से उबर ही रहे थे कि नोटबंदी से सामना हो गया. नोटबंदी के पहले 50 दिनों की ही बात करें, तो इस दौरान किसानों की आय में 50-60 फीसदी की कमी हुई है. साल बीतने के साथ ही कर्नाटक के गुलबर्ग, आंध्रप्रदेश के कुरनूल और मध्यप्रदेश के इंदौर में तूर दाल की पहली खेप पहुंच गई. लेकिन मंडी में इसकी कीमत न्यूनतम समर्थन मूल्य से बहुत कम थी. 5050 रुपए एमएसपी की तुलना में आंध्रप्रदेश में यह 3,666 तो कर्नाटक में 4,570 रुपए प्रति क्विंटल बिका.' किसानों द्वारा एमएसपी से कम कीमत पर अपने उत्पादों को बेचने की मजबूरी केवल दाल के मामले में ही नहीं है. सब्जियां, फल और यहां तक की फूलों की खेती करने वाले किसान भी माथा पीटने को मजबूर हैं. शादी-ब्याह के इस मौसम में जब फूल उपजाने वाले किसान अपने लागत और फायदों के लिए बाजारों का रुख करते हैं, इस समय उन्हें उपज की कीमत की जगह निराशा हाथ लग रही है. 30-40 रुपए प्रति किलो बिकने वाले कई फूल दिल्ली के आजादपुर मंडी में 4-6 रुपए प्रति किलो बिक रहे हैं.

सरकार थपथपा रही अपनी पीठ

नोटबंदी के फैसले के बाद लोगों की परेशानी और विपक्ष के चौतरफा हमले के बीच जो आंकड़ा सरकार के लिए कवच-कुंडल साबित हुआ, वह था- रबी फसल की रिकार्ड बुआई. कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने रबी की बुआई का आंकड़ा पेश करते हुए कहा कि बुआई पर नोटबंदी का कोई असर नहीं पड़ा है. उन्होंने कहा, पिछले साल के 438.90 लाख हेक्टेयर के मुकाबले इस साल 472.43 लाख हेक्टेयर में रबी की बुआई हुई है, जो कि 7.64 फीसदी अधिक है. इस एक आंकड़े द्वारा सरकार ने साबित करने की कोशिश की कि खेती-किसानी पर नोटबंदी का कोई असर नहीं पड़ा है. विपक्षी हमलों के जवाब से लेकर समाचार चैनलों के डिबेट में भाजपा प्रवक्ताओं की प्रतिक्रिया और जमीनी स्तर पर लोगों में नोटबंदी की सार्थकता का सरकारी संदेश भी रबी फसल की रिकॉर्ड बुआई के माध्यम से ही होकर गया. हालांकि कृषि मंत्री ने जो आंकड़े पेश किए थे, वे 9 दिसंबर तक के थे. गौरतलब है कि किसान बुआई से पहले ही बीज और खाद के लिए पैसों की व्यवस्था कर लेते हैं. इस बार भी यही हुआ था. किसानों ने पहले से व्यवस्थित संसाधनों के जरिए बुआई तो कर ली, लेकिन समस्या अब सामने आ रही है, जब किसानों को फसल की सिंचाई करनी है और खाद डालने हैं. जो कुछ पैसे किसानों ने खाद-पानी के लिए बचा कर रखे थे, उन्हें भी बैंकों में जमा कराना पड़ गया. उत्तरी भारत के कुछ क्षेत्र जहां किसान धान-गेहूं बेचकर नई फसलों को तैयार करने का काम करते हैं, वहां भी अनाजों की सही कीमत नहीं मिल पा रही है. इस स्थिति में बैंक भी किसानों का सहारा बनते नहीं दिख रहे. ग्रामीण भारत, जिसका 81 फीसदी हिस्सा आज भी बैंकों की पहुंच से दूर है, वहां कैश की ऐसी किल्लत के समय किसान किस तरह बोई गई फसल को अच्छी पैदावार में बदलेंगे, यह एक बड़ी चुनौती है.

देवेंद्र शर्मा कहते हैं, 'कई अर्थशास्त्रियों और फंड मैनेजर्स का मानना है कि यह एक अल्पकालिक समस्या है. धीरे-धीरे पटरी पर लौट रहे व्यापार को देखते हुए हम इसे अल्पकालिक समस्या कह सकते हैं. लेकिन उन किसानों और भूमिहीन लोगों के लिए यह एक गंभीर संकट है, जो खेती-किसानी और अपने जीविकोपार्जन के लिए रोजमर्रा की कमाई पर निर्भर रहते हैं.' नोटबंदी के बाद की परिस्थितियां नि:संदेह ही पैदावार के लिए कुप्रभावी होंगी, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि अच्छी बुआई के बाद पैदावार भी अच्छी ही हो. बुआई के बाद फसलों की देखभाल जरूरी है, जो कि अभी किसानों के लिए एक बड़ी समस्या है. हालात बेहद गंभीर हैं, लेकिन किसी भी हाल में अपने फैसले को सही साबित करने की सियासी जिद इस सच को स्वीकार करने से गुरेज कर रही है कि नोटबंदी के फैसले ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है. ■

feedback@chauthiduniya.com

बिहार

दुनिया भर में प्रकाशपर्व की वाह-वाह

चौथी दुनिया ब्यूरो

पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल जब एक भरी सभा में कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह बादशाह के 350 वें प्रकाशोत्सव में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस शानदार तरीके से तैयारी की, उसकी जिम्मेदारी अगर उन्हें मिलती, तो वह भी नहीं कर पाते. इसके बाद भला कुछ कहने के लिए क्या रह जाता है? प्रकाश सिंह बादल यहीं तक नहीं रुके. उन्होंने कहा कि बिहार ने प्रकाश पर्व पर जितना किया है, वह सिख परम्परा के इतिहास में हमेशा चर्चा का विषय बना रहेगा. सिखों के दसवें गुरु, गुरु गोविंद सिंह की 350वीं जयंती प्रकाश पर्व के रूप में पटना में एक से पांच जनवरी के बीच मनाई गई. गुरु गोविंद सिंह का जन्म राजधानी पटना में हुआ था. अपने बचपन के पहले चार वर्ष उन्होंने यहीं बिताए थे. जानकार मानते हैं कि प्रकाशोत्सव का भव्य आयोजन एक ऐसा उदाहरण बन गया है, जो भविष्य के किसी आयोजन के लिए नजीर के रूप में पेश किया जाएगा. नीतीश सरकार द्वारा प्रकाशोत्सव का शानदार आयोजन क्या समर्थक, क्या विरोधी, सबका दिल जीत लेने वाला रहा. खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी नीतीश से राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता जगजाहिर है, ने नीतीश की तारीफ में कसीदे पढ़े और कहा कि उन्हें लोग बताते थे कि नीतीश जी ने पूरी तैयारी पर खुद ही बारीक नजर रखी है. उन्होंने यहां तक कहा कि बिहार के इस सत्कार को कभी भुलाया नहीं जा सकता है.

यह हकीकत है कि प्रकाशोत्सव की तैयारी बिहार सरकार ने अपने स्तर पर एक साल से करनी शुरू कर दी थी. चमचमाती सड़कें, दुधिया रौशनी में नहाई राजधानी, श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए तीन टेंट सिटी यानी तीन अस्थाई शहरों का निर्माण और आवागमन के लिए दो सौ से ज्यादा मुफ्त बसों का इंतजाम किया गया था. सुरक्षा और सहायता के लिए हजारों पुलिस व गैर पुलिसकर्मी, प्रकाशोत्सव के दौरान सरकारी छुट्टी देकर तमाम अमले को इसी काम में लगाना, कर्मियों की कमी पूरी करने के लिए दूसरे जिलों से बुलाना, मतलब ये कि बिहार सरकार ने अपनी पूरी ताकत और संसाधन प्रकाश पर्व के लिए झोंक दिए. हालांकि इस आयोजन पर सरकार ने कितने खर्च किए, इसकी जानकारी अभी तक सार्वजनिक नहीं हो सकी है. जानकारी मिली है कि सिर्फ पटना के गांधी मैदान पर अस्थाई रूप से बनी टेंट सिटी व गुरुद्वारे के निर्माण पर ही 30 करोड़ रुपये खर्च कर दिए गए.

इसके अलावा गांधी मैदान से 9 किलोमीटर दूर पटना साहब गुरुद्वारे के करीब संकरी गलियों के चौड़ीकरण, रोशनी से नहाई सरकारी इमारतों के सजावट, कंगन घाट, जहां गुरु गोविंद सिंह ने बचपन में अपने हाथों का कंगन गंगा में फेंक दिया था, का सौंदर्यीकरण किया गया. बिहार के निवासियों ने भी जमकर मेजबानी की. इसी का नतीजा था कि प्रकाश सिंह बादल को भी यह कहना पड़ा कि प्रकाशोत्सव के आयोजन की जिम्मेदारी अगर उन्हें सौंपी जाती, तो वे भी ऐसा कमाल नहीं दिखा पाते.

ऐसे में एक सवाल लोगों के जेहन में उभरना लाजिमी है कि आखिर नीतीश सरकार की, सत्कार की ऐसी नजीर पेश करने के पीछे क्या रणनीति थी? आखिर क्यों बिहार सरकार ने अपना आर्थिक व मानव संसाधन इस आयोजन में झोंक दिया? इसके अलावा यह भी कि नीतीश ने इस आयोजन से क्या हासिल करना चाहा? दरअसल, नीतीश बिहारी अस्मिता और बिहारी उपराष्ट्रीयता को बड़ी मजबूती से पकड़ते हैं. वह कट्टरपंथी राष्ट्रवाद की राजनीति के बजाय बिहारियत के ऐसे मुद्दे को अपना हथियार बनाते हैं, जिसका जुड़ाव आम बिहारी से होता है. उन्हें इस बात का बखूबी इल्म है कि बिहार के बाहर, जो यहां की छवि है, उससे खुद अनिवासी बिहारी असहज महसूस करते हैं. ऐसे में बिहारियत की भावना को पकड़ लेना नीतीश का हुनर है. पिछले ग्यारह वर्षों में, जबसे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, ऐसी कई मिसालें हैं. एक ऐसा ही भव्य आयोजन दो वर्ष पहले बिहार दिवस के रूप में नीतीश सरकार ने किया था. नीतीश ने प्रकाश पर्व में बिहारियत की वह भावना जगा दी कि विपक्षी नेता सुशील मोदी को भी यह कहना पड़ा कि प्रकाश पर्व के लिए अच्छी मेहमाननवाजी हुई है. यह मेहमाननवाजी केंद्र व राज्य सरकार के आपसी सहयोग से संभव हो सकी है. सारांश यह कि नीतीश ने प्रकाश पर्व के आयोजन के माध्यम से एक ऐसी लकीर खींची कि मजबूर होकर अन्य बिहारी नेताओं को भी इस लकीर पर चलना पड़ा. ■

feedback@chauthiduniya.com

प्रकाशोत्सव में छुपी सियासत

सियासत अपने हर कदम की कीमत सियासी कसौटी पर ही वसूलती है. प्रकाश पर्व में सत्ता के दखल ने भी सियासी कीमत वसूली. ऐसा होना अपरिहार्य भी था, क्योंकि कोई मुख्यमंत्री अपनी व्यस्ततम दिनचर्या को छोड़कर एक पखवाड़े तक अपनी पूरी नौकरशाही, पूरा संसाधन यूं ही नहीं झोंक सकता. प्रकाश पर्व के समानांतर सियासी गहमागहमी मौन रूप में चल रही थी. प्रकाश पर्व के अंतिम दिन उस समारोह में, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी, पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, भाजपा के कई केंद्रीय मंत्री व राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव समेत उनके मंत्री पुत्रों की पूरी जमात मौजूद थी, मंच पर जो चंद चेहरे थे, उनमें पीएम, सीएम नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, रविशंकर प्रसाद व गर्वनर रामनाथ कोविंद के अलावा पटना साहब गुरुद्वारा के प्रमुख व शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष शामिल थे. इतना ही नहीं, राजद प्रमुख व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आमंत्रित जरूर थे, लेकिन वे सब मंच के सामने फर्श पर बैठे थे. इस धार्मिक आयोजन में जो तकरीरें हुईं, उसमें धर्म से ज्यादा सियासी बातें ही छुपी थीं. नीतीश को इस आयोजन के लिए खूब बधाइयां मिल रही थीं. जब नीतीश ने अपनी बात रखी, तो उन्होंने इन तैयारियों का श्रेय अपने एक- एक नौकरशाहों के नाम गिना-गिनाकर दिया. जबकि अपने एक भी मंत्री, यहां तक कि उपमुख्यमंत्री का भी नाम नहीं लिया. ऐसा कतई नहीं हो सकता कि नीतीश अपने मंत्रियों का नाम भूल गये हों, बल्कि यह उनकी रणनीति का हिस्सा था. उन्होंने मुख्य सचिव, पर्यटन सचिव, पटना के डीएम और यहां तक कि एसएसपी की भूमिका की तारीफ तो की, पर सरकार के किसी विभाग के मंत्री का नाम तक नहीं लिया. गौर से देखें तो इस आयोजन में (जो धार्मिक होते हुए भी राजनीतिक बन चुका था) पीएम मोदी और पंजाब के मुख्यमंत्री ने नीतीश कुमार को वृल्हा घोषित कर दिया और नीतीश ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए अपने आईएएस व आईपीएस अफसरों को सहबाला बना डाला, जहां उनके मंत्री महज बाराती की हैसियत में थे. अपने दल के मंत्रियों का बारात बन जाना तो अलग बात है, लेकिन गठबंधन के सबसे बड़े दल राजद कोटे के मंत्रियों और यहां तक की उपमुख्यमंत्री व लालू के बेटे तेजस्वी यादव की हैसियत भी इन्हीं बारातियों की तरह बना देना स्वाभाविक तौर पर चर्चा का विषय रहा. तब उसी शाम राजद के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद ने इन सवालों को रेखांकित किया. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को वे गंभीरता से लेंगे. हालांकि लालू प्रसाद से जब राज्य सरकार के इस रवैये के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि पीएम मोदी या अन्य लोगों ने बिहार सरकार की तारीफ की है और तारीफ सरकार के मुखिया की ही होती है. इस मामले में आम लोगों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं, राजनीतिक दलों और नेताओं के अपने-अपने जो भी विचार हों, पर इस आयोजन का एक राजनीतिक पहलू तो यह जरूर है कि सीएम नीतीश कुमार ने अपने अंदाज में सियासी शह और मात का आईना जरूर दिखाया. एक बात तो तय है कि इस सियासी आईने में जद (यू) के सहयोगी राजद की बेबसी ही ज्यादा झलकती है. ■

नोटबंदी के दौर में नाकेबंदी ने जीना मुहाल किया

सलाम तिजेब सिंह

जायज मांगों के लिए विरोध और प्रदर्शन करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन अगर इससे नागरिक अधिकार प्रभावित हों, तो इसे उचित नहीं कहा जा सकता. यही काम इस वक्त मणिपुर में हो रहा है. मणिपुर पिछले एक नवंबर से ब्लॉकेड (नाकेबंदी) की मार झेल रहा है. मणिपुर को जोड़ने वाले दोनों नेशनल हाईवे 39 एवं 53 को यूनाइटेड नगा काउंसिल ने ब्लॉक कर रखा है. ट्रांस एशियन रेलवेज प्रोजेक्ट और अन्य नेशनल प्रोजेक्ट भी बंद हैं. दो महीने बाद भी इसका समाधान नहीं निकला है, वहीं सरकार व अधिकारियों की चिंता केवल राज्य में चुनाव जल्द कराने की है. मणिपुर के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और अन्य मंत्री चुनाव जल्दी कराने के लिए अक्सर दिल्ली आते-जाते रहते हैं, लेकिन ब्लॉकेड की वजह से ठप पड़े राज्य के बारे में सोचने की फुर्सत उन्हें नहीं है. ब्लॉकेड के कारण आम लोगों को रोजमर्रा की चीजें, जैसे एलपीजी, पेट्रोल-डीजल, खाने-पीने का सामान एवं दवा आदि की भारी कमी झेलनी पड़ रही है.

इस ब्लॉकेड का कारण है मणिपुर सरकार द्वारा सात नए जिले की घोषणा. सरकार की इस घोषणा का विरोध करते हुए यूएनसी ने नेशनल हाईवे को ब्लॉकेड कर दिया है. यूएनसी एक मणिपुरी नगा संगठन है, जो नगालैंड और मणिपुर में सक्रिय रूप से काम करता है. यूएनसी, एनएससीएन-आईएम के सहयोग से चलने वाली संस्था है, जबकि एनएससीएन-आईएम की केंद्र सरकार के साथ वार्ता चल रही है. मणिपुर में नौ जिले थे, अब सात नए जिले मिलाकर कुल 16 जिले हो गए हैं. इन नए सात जिलों में जिरिबाम, कांगपोकपी, काकचिंग, तेंगनौपल, कामजोंग, नोने एवं फरजॉल हैं. जिरिबाम एवं कांगपोकपी नगा बहुल जिले हैं और सबसे अशांत क्षेत्र भी. पहले भी इन दोनों जगहों पर नाकेबंदी होती रही है. दोनों जगहों को जिला बनाने की घोषणा पर यूएनसी एतराज जता रही है. यूएनसी का मानना है कि नए जिले की घोषणा से नगा लोग अलग-अलग टुकड़ों में बंट जाएंगे. वे चाहते हैं कि एक ही जगह पर, एक ही प्रशासनिक क्षेत्र के अंदर वे रहें. लेकिन नए जिले बनने से एक ही गांव के अलग-अलग हिस्से, अलग-अलग जिलों में बंट जाएंगे. वैसे भी मणिपुर में बसे नगा समुदाय एनएससीएन-आईएम के नगालिम राज्य की मांग का समर्थन करते हैं. उनको ये लगता है कि सरकार उनको बांटने का काम कर रही है, जबकि मणिपुर की सरकार का मानना है कि सात नए जिले बनाना किसी खास जाति या समुदाय के खिलाफ नहीं है. यह केवल एक प्रशासनिक रूप से किया गया विभाजन है. इससे लोगों को प्रशासनिक काम-काज में सुविधा होगी. इससे इतर यूएनसी को एतराज है कि उनके अपने लोगों को अलग-अलग हिस्सों में बांट दिया गया है. राज्य सरकार उनको तोड़ने की साजिश कर रही है.

बहरहाल, राज्य में ब्लॉकेड का इतिहास बहुत लंबा और जटिल भी है. इसके पीछे कई कहानियां छुपी हैं. इसमें राज्य सरकार को निर्दोष नहीं माना जा सकता है. 2011 में भी सदर हिल्स डिस्ट्रिक की मांग को लेकर ब्लॉकेड हुआ था. उसके विरोध में यूएनसी ने 120 दिन का ब्लॉकेड कर आम जनता का जीना दुष्वार कर दिया था. मणिपुर के इस ब्लॉकेड के समाधान में केंद्र से ज्यादा जिम्मेदारी राज्य सरकार की है. 2011 में जब इन संगठनों के साथ सरकार का समझौता हुआ था, तो उस समझौते के शर्तों की जानकारी आज तक लोगों को नहीं दी गई. इतने लंबे समय का ब्लॉकेड कैसे खत्म हुआ था और क्या-क्या शर्तें मानी गईं, यह किसी को नहीं पता चल सका. तुलनात्मक विश्लेषण करें, तो आज यह ब्लॉकेड वैसा ही, जैसा उस वक्त लोग सदर हिल्स डिस्ट्रीक की मांग कर रहे थे. सरकार ने सही निर्णय लेकर क्यों नहीं उसी वक्त समाधान निकाला. सदर हिल्स (जिरिबाम) को एक जिला घोषित करने की रूप-रेखा उसी समय तैयार हो चुकी थी, फिर भी राज्य सरकार ने घोषित नहीं किया. अगर उस वक्त तत्काल घोषणा की गई होती, तो अब यह समस्या पैदा नहीं होती. अब राज्य में चुनाव नजदीक आने के बाद राज्य सरकार ने सात नए जिलों की घोषणा कर लोगों में अशांति का माहौल पैदा कर दिया है.

इस समय राज्य में हालत ये है कि ढाई सौ से तीन सौ रुपए प्रति लीटर पेट्रोल भी लोगों को नहीं मिल रहा है. गांवों में आलू-दाल जैसे आसानी से मिलने वाले सामान भी नहीं मिल रहे हैं. पेट्रोल-डीजल की भारी कमी की वजह से गाड़ियों का आना-जाना बंद हो गया है. जो गाड़ियां चल भी रही हैं, तो उसका भाड़ा दोगुना कर दिया गया है. इस दौरान दो सप्ताह तक इंटरनेट सेवा बंद रखा गया था. एक तरफ लोग नोटबंदी की मार झेलने को मजबूर थे, तो वहीं ब्लॉकेड ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया. ■

feedback@chauthiduniya.com

यूएनसी द्वारा मणिपुर में किया जा रहा इकोनॉमी ब्लॉकेड असंवैधानिक है. यह ब्लॉकेड मणिपुर के 28 लाख लोगों के पेट पर लात मारता है. यह राज्य सरकार की नाकामी है. नए जिले बनाने से सरकार नगाओं के हक नहीं छीन रही है. उनको जो भी स्टेटस पहले से मिल रहा था, वही स्टेटस और सुविधाएं इन नए जिलों में भी सुरक्षित रहेंगे.

-एलांगबम जोनसन, *अध्यक्ष, यूनाइटेड कमेटी मणिपुर (यूसीएम)*

जमीन से नगाओं का अटूट संबंध रहा है. पूर्वजों की परंपरा, संस्कृति और एकता से जुड़ी व्यवस्था और नियम का हमेशा सम्मान करना नगाओं की जिम्मेदारी है. इसपर अगर हमें कोई बांटने की कोशिश करता है, तो हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे.

-पीए थेको (नगा), *सोशल एक्टिविस्ट*

राष्ट्रीय मीडिया कश्मीरियों के खिलाफ दुष्प्रचार करता है

हारून रेशी

कश्मीर के लोगों को आम शिकायत है कि यहां हालात बिगड़ते ही अधिकतर राष्ट्रीय हिन्दी समाचार पत्र व पत्रिकाएं कश्मीरियों के खिलाफ दुष्प्रचार शुरू कर देते हैं. इसके फलस्वरूप कश्मीरी जनता और देश के अन्य हिस्से के लोगों के बीच खाई बढ़ जाती है. भ्रम सच्चाई का रूप धारण कर लेते हैं और इससे नफरत में इज़ाफ़ा होता है. चिंतनशील तबके के लोग लंबे अर्से से यह सवाल पूछ रहे हैं कि आख़िर हिन्दी मीडिया कश्मीर की वास्तविक स्थिति जनता तक पहुंचाने के बजाय दुष्प्रचार क्यों करता है? इसका जवाब हाल में राष्ट्रीय स्तर पर कराए गए सर्वे से मिला है. विभिन्न राज्यों में कराए गए इस सर्वे रिपोर्ट से पता चला है कि हिन्दी भाषा के अधिकतर पत्रकार कश्मीर के वास्तविक हालात व घटनाओं और यहां तक कि ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में भी नहीं के बराबर जानते हैं. मीडिया स्टडी ग्रुप की ओर से देश के विभिन्न राज्यों में कराए गए इस सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि हिन्दी भाषा के अधिकतर पत्रकार कश्मीर के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं. विडंबना यह है कि इनमें से अधिकतर कश्मीर के विषय पर या कश्मीर के हालात और इतिहास के बारे में अपनी जानकारी दुरुस्त करने या इसे बेहतर करने के इच्छुक भी नहीं हैं. रिपोर्ट बताती है कि सर्वे के दौरान हिन्दी भाषा के अधिकतर पत्रकारों को संविधान के आर्टिकल 370 के बारे में भी पूरी जानकारी नहीं है. जबकि संविधान व क़ानूनी विशेषज्ञ आर्टिकल 370 को देश और कश्मीर के बीच संवैधानिक और क़ानूनी रिश्तों को बहाल करने का एक पुल क़रार दे रहे हैं. परेशान करने वाली बात यह है कि देश में हिन्दी अख़बारों, हिन्दी समाचार चैनलों और अन्य समाचार संस्थाओं की जनमत तैयार करने में अहम भूमिका होती है. भारत में अधिकतर लोग हिन्दी भाषा के समाचार–पत्र ही पढ़ते हैं और हिन्दी न्यूज़ चैनल ही देखते हैं. सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 46 प्रतिशत पत्रकारों का कश्मीर से संबंधित ज्ञान का स्रोत स्वयं हिन्दी के अख़बार ही हैं.

सर्वे के दौरान हिन्दी भाषा के अधिकतर पत्रकारों को संविधान के आर्टिकल 370 के बारे में भी पूरी जानकारी नहीं है. जबकि संविधान व क़ानूनी विशेषज्ञ आर्टिकल 370 को देश और कश्मीर के बीच संवैधानिक और क़ानूनी रिश्तों को बहाल करने का एक पुल क़रार दे रहे हैं. परेशान करने वाली बात यह है कि देश में हिन्दी अख़बारों, हिन्दी समाचार चैनलों और अन्य समाचार संस्थाओं की जनमत तैयार करने में अहम भूमिका होती है. भारत में अधिकतर लोग हिन्दी भाषा के समाचार–पत्र ही पढ़ते हैं और हिन्दी न्यूज़ चैनल ही देखते हैं. सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 46 प्रतिशत पत्रकारों का कश्मीर से संबंधित ज्ञान का स्रोत स्वयं हिन्दी के अख़बार हैं.

स्पष्ट है कि कश्मीर के वास्तविक हालात, समस्या और एतिहासिक परिदृश्य से अनभिज्ञ पत्रकार अक्सर तथ्यों के बजाय न केवल खुद इस दुष्प्रचार के शिकार हो जाते हैं, बल्कि अपने पाठकों तक भी भ्रामक सूचनाएं पहुंचाते हैं. श्रीनगर में रहने वाले इक्नॉमिक टाइम्स के संवाददाता हकीम इरफान, जो कई वर्षों तक दिल्ली में भी काम कर चुके हैं, का मानना है कि अधिकतर हिन्दी पत्रकार कश्मीर के हालात के बारे में बहुत कम जानकारी रखते हैं, लेकिन उनकी नज़र में इसके कई कारण हैं. उन्होंने बताया कि कश्मीर के हालात व समस्याएं और यहां के इतिहास के बारे में हिन्दी भाषा में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है. अंग्रेज़ी भाषा के पत्रकारों को इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है. दूसरी अहम बात यह है कि हिन्दी के पत्रकारों को अंग्रेज़ी के पत्रकारों के मुकाबले कम वेतन मिलता है. इस कारण इन पत्रकारों में अधिक मेहनत करने का रुझान भी नहीं है. तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया के विस्तार और अन्य कई कारणों से आमतौर पर पत्रकारिता के पेशे से जुड़े लोगों में सुस्ती पैदा हो गई है. अब ख़बरों की छानबीन करने और रिसर्च करने का रुझान कम हो रहा है. मेरे ख्याल से यही वे कारण हैं, जिसकी वजह से अधिकतर पत्रकारों को कश्मीर के हालात के बारे में कम जानकारी है.

विश्लेषकों का कहना है कि कश्मीर के बारे में भारत के केवल हिन्दी भाषा के पत्रकार ही नहीं, बल्कि उर्दू के पत्रकारों की सूचनाएं और ज्ञान भी अपर्याप्त हैं. विश्लेषक और श्रीनगर में रहने वाले रेडियो तेहरान के संवाददाता सिब्ते मोहम्मद हसन कहते हैं कि मेरे संबंध बहुत सारे भारतीय पत्रकारों से हैं. अपने अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि भारतीय पत्रकारों को कश्मीर के बीते 70 वर्षों के इतिहास के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है. सिब्ते मोहम्मद हसन का कहना है कि अधिकतर हिन्दी और उर्दू पत्रकारों को यह भी नहीं पता कि जम्मू–कश्मीर देश का एकमात्र ऐसा राज्य है, जिसका अपना संविधान है. इस राज्य में दो झंडे हैं, एक राष्ट्रीय ध्वज और दूसरा जम्मू–कश्मीर का झंडा. दो झंडों का समान अनुसरण संवैधानिक और कानूनी लिहाज़ से अनिवार्य है. यही कारण है कि राज्य में जहां कहीं भी तिरंगा देखने को मिलता है, तो उसके बगल में राज्य का अपना झंडा भी लहराता नज़र आता है. राज्यों की विधानसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यगण भारतीय संविधान के तहत नहीं, बल्कि जम्मू–कश्मीर के अपने संविधान के तहत शपथ लेते हैं. यह एकमात्र राज्य है, जहां सरकार का कार्यकाल पांच वर्ष नहीं, बल्कि 6 वर्ष होता है. संसद में पास होने वाले नए कानून, तब तक जम्मू–कश्मीर में लागू नहीं हो सकते, जब तक राज्य विधानसभा इन्हें लागू करने की मंज़ूरी नहीं दे देती है. इस राज्य की अदालतों में अपराध से संबंधित केसों की सुनवाई भारतीय कानून यानी भारतीय दंड संहिता के तहत नहीं, बल्कि राज्य के अपने कानून (रणबीर पिनल कोड) के तहत होती है. भारत और पाकिस्तान के राज्य 14 और 15 अगस्त को एक साथ अस्तित्व में आए, लेकिन जम्मू–कश्मीर 26 अक्टूबर तक एक स्वतंत्र और स्वायत्त राज्य के रूप में स्थापित था. अन्य राज्यों के मुकाबले में जम्मू–कश्मीर का भारत के साथ विलय हुआ न कि एकीकरण. 1953 तक भारत के शेष राज्यों से जम्मू–कश्मीर आने वाले लोगों को एंट्री परमिट प्राप्त करना पड़ता था. 1953 तक इस राज्य में मुख्यमंत्री और गवर्नर के नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री और राज्य प्रमुख के पद हुआ करते थे. इस राज्य में आज भी देश के बहुत सारे कानून लागू नहीं हो सकते हैं. जम्मू–कश्मीर में कोई भी दूसरे राज्य का निवासी जमीन या कोई दूसरी संपत्ति नहीं खरीद सकता है. यह कानून यहां विभाजन के बहुत पहले से लागू है और इसे हिंदू महाराजा ने बनाया था. अन्य राज्यों के निवासियों के उलट जम्मू–कश्मीर का हर निवासी दोहरी नागरिकता रखता है, एक जम्मू–कश्मीर की और एक भारत की. जम्मू–कश्मीर का कोई निवासी अगर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जाना चाहे तो उसे पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि 'कारवान–ए–अमन' नाम की बस सर्विस के तहत वह डिप्टी कमिश्नर (जिला अधिकारी, कश्मीर) की ओर से जारी किए गए परमिट पर जा सकता है. कश्मीर के दोनों विभाजित हिस्सों के बीच बार्टर सिस्टम, यानी चीज़ों की अदला–बदली के तहत कारोबार जारी है. ऐसी बहुत सारी बातें हैं, जिनसे देश के हिन्दी और उर्दू पत्रकारों का एक बड़ा तबका अनभिज्ञ है. जहां तक राज्य के वर्तमान राजनीतिक हालात का संबंध है, यह बात सर्वेक्षण में सामने आई है कि अधिकतर भारतीय पत्रकार सुनी–सुनाई बातों को ही सही समझते हैं. हिन्दी और उर्दू के बहुत कम पत्रकार कश्मीर के हालात को रिपोर्ट करने के लिए यहां आते हैं. यही कारण है कि हाल में जब यहां हालात खराब हुए तो नेशनल मीडिया विशेष रूप से हिन्दी मीडिया ने ऐसी खबरें पेश कीं, जिनका वास्तविकता से दूर–दूर तक कोई लेना–देना नहीं था. आश्चर्य की बात यह है कि भारतीय मीडिया के इस रवैये को बदलने के लिए कहीं भी कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है. इस संदर्भ में बीते दिनों चौथी दुनिया ने परंपरा से हटकर असाधारण भूमिका निभाई है. अखबार के चीफ़ एडिटर संतोष भारतीय ने बीते पांच महीनों के दौरान कम से कम पांच बार कश्मीर का विस्तृत दौरा कर विभिन्न विचारधारा के लोगों से मिलकर जमीनी तथ्यों पर आधारित रिपोर्ट पूरे राष्ट्र के सामने पेश की. ज़ाहिर है कि महज़ एक संस्था की इस पहल से तब तक कुछ बदलाव नहीं होगा, जब तक देश के तमाम मीडिया संस्थान कश्मीर को उसके वास्तविक हालात व घटनाओं के संदर्भ में कवर करने के इच्छुक न हों. जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक कश्मीरियों और देश की बाक़ी जनता के बीच रिश्तों को स्थिर करने और पैदा हुई खाई को पाटना संभव नहीं होगा.■

feedback@chauthiduniya.com

केजरीवाल की सभा से भाजपा और कांग्रेस में हलचल

केजरीवाल ने सभा के दौरान कहा कि मैं पूरे देश में नोटबंदी को लेकर आमलोगों को जागरूक करने के प्रयास में जुटा हूं, यह रैली भी उसी की एक कड़ी है. अभी मध्यप्रदेश में हमारा फोकस संगठन पर है, यूथ स्तर पर संगठन को खड़ा करना है. लगे हाथ उन्होंने प्रदेश के भाजपा और कांग्रेस नेताओं को यह चेतावनी भी दे डाली कि इस रैली के बाद हम फ्रंट पर काम करेंग. हम सभी 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे. आम आदमी पार्टी में चुनाव पार्टी नहीं, बल्कि जनता लड़ती है. मध्यप्रदेश में भी आने वाले दिनों में हम ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे. अरविन्द केजरीवाल ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि हम मध्यप्रदेश से बिजली खरीदकर दिल्ली के लोगों को सस्ती बिजली देते हैं.

सोरिन शर्मा

मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 13 वर्षों के शासनकाल के बाद केजरीवाल की पहली सभा ने भाजपा की चूलें हिला दी हैं. वहीं कांग्रेस भी यह सोचने को मजबूर है कि यदि समय रहते गुटबाजी से हटकर पार्टी हित में काम नहीं करेंगे, तो अस्तित्व बचाना भी मुश्किल होगा. भले ही अन्य पार्टियों के दावों के अनुसार, अरविन्द की सभा में भारी–भरकम भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकी, लेकिन यह भाड़े की भीड़ नहीं थी. भोपाल में लोग आप पार्टी के मुखिया केजरीवाल के भाषणों को सुनने के लिए आए थे. केजरीवाल ने सभा के दौरान अपने अंदाज में प्रधानमंत्री से लेकर मध्यप्रदेश सरकार तक को जमकर घेरा. सभा में मौजूद भीड़ इस बात का संकेत है कि राज्य में जड़ें जमाने के लिए आप ने अपने कदम मजबूती से बढ़ा दिए हैं. मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार में घोटालों, फर्जीवाड़ों और कुपोषण के नाम पर जो खेल चल रहा है, अगर उस पर विराम नहीं लगा, तो 2018 के चुनाव में भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है. भाजपा के सत्ताधीश अपनी पीठ स्वयं थपथपाने में लगे हैं. यही कारण है कि चंद दिनों में ही आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अपनी सक्रियता से प्रदेश में जड़ें जमा लीं. आप की बढ़ती सक्रियता भाजपा के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है. भाजपा ने प्रदेश में कांग्रेस को नेस्तनाबूद करने में कोई कसर नहीं बचा रखी थी, लेकिन ऐसा लगता है कि आप की सक्रियता यह कारनामा जरूर कर दिखाएगी. केजरीवाल ने सभा के दौरान कहा कि मैं पूरे देश में नोटबंदी को लेकर आमलोगों को जागरूक करने के प्रयास में जुटा हूं, यह रैली भी उसी की एक कड़ी है. अभी मध्यप्रदेश में हमारा फोकस संगठन पर है, यूथ स्तर पर संगठन को खड़ा करना है. लगे हाथ उन्होंने प्रदेश के भाजपा और कांग्रेस नेताओं को यह चेतावनी भी दे डाली कि इस रैली के बाद हम फ्रंट पर काम करेंग. हम सभी 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे. आम आदमी पार्टी में चुनाव पार्टी नहीं, बल्कि जनता लड़ती है. मध्यप्रदेश में भी आने वाले दिनों में हम ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे. अरविन्द केजरीवाल ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि हम मध्यप्रदेश से बिजली खरीदकर दिल्ली के लोगों को सस्ती बिजली देते हैं. मध्यप्रदेश में 200 यूनिट बिजली जलाने पर 1200 रुपए बिजली बिल भरना होता है, जबकि दिल्ली में इसके लिए मात्र 400 रुपए देने पड़ते हैं. यह बयान इस बात के संकेत हैं कि आनेवाले दिनों में अब आप के नेता मध्यप्रदेश में बिजली और पानी को मुद्दा बनाएंगे. आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता राज्य में व्याप्त तमाम अव्यवस्थाओं को लेकर जनता के बीच जाएंगे और प्रदेशभर में जन आंदोलन चलाने का प्रयास करेंगे. भोपाल प्रवास के दौरान केजरीवाल की रणनीति से साफ जाहिर होता है कि आगामी दिनों में केजरीवाल भाजपा और कांग्रेस के नेताओं को पटकनी देने की पूरी कोशिश करेंगे. एक बात तो जरूर है कि इस सभा ने भाजपा के हवाबाज नेताओं को यह मैसेज जरूर दिया है कि केवल योजनाओं का ढिंढोरा पीटने से जनता को ज्यादा दिन तक भ्रम में नहीं रखा जा सकता है. सभा की सफलता ने आप कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भर दी है.

राहुल के बयान पर ली चुटकी

केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले कहा था कि उनके पास ऐसे दस्तावेज हैं, जिनसे भूचाल आ जाएगा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उन्होंने मोदी से मुलाकात की. इस मुलाकात पर केजरीवाल ने चुटकी ली और कहा कि मोदी ने राहुल गांधी को वाड्रा की फाइल दिखा दी और वे चुप हो गए. मोदी ने घोषणा कर दी कि राजनीतिक दलों के चंदे की जांच नहीं होगी, लेकिन हम कहते हैं कि राजनीतिक दलों को मिल रहे चंदों की जांच जरूर होनी चाहिए. तेज धूप में केजरीवाल को सुनने के लिए तीन घंटे तक लोग मैदान में बैठे रहे. उनके आने के पहले शहनाज हिंदुस्तानी ने क्रांतिकारी, देशभक्ति गीतों व तुकबंदी से लोगों को बांधे रखा.

असली किसान पुत्र शिवराज नहीं, केजरीवाल–अग्रवाल

आप के प्रदेश संयोजक आलोक अग्रवाल ने आरोप लगाया कि मप्र में 11 साल का सुशासन मनाया गया, जबकि यहां जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है. व्यापम घोटाले में सरकार फंसी है. जनता को महंगे दर पर बिजली दी जा रही है. उन्होंने कहा कि असली किसान पुत्र शिवराज नहीं, बल्कि केजरीवाल हैं. उन्होंने किसानों को मुआवजे के रूप में 20 हजार रुपए प्रति एकड़ राशि दिलाई है. उनके बाद आप यूथ विंग की सचिव वंदना सिंह ने भी रैली को संबोधित किया.

परिवर्तन रैली में आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भाजपा और कांग्रेस दोनों पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि दोनों ही पार्टियां मिली–जुली हैं. ये मिलकर पांच–पांच साल लोगों को लूटती हैं. उन्होंने सभा में बैठे लोगों से सवाल किया कि मैं मध्यप्रदेश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या यहां भ्रष्टाचार कम हो गया है. 2000 का नया नोट निकालने से आप भला भ्रष्टाचार कैसे बंद करेंगे. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मकसद भ्रष्टाचार को खत्म करना नहीं था. आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मोदीजी की नीयत भी खराब है और नीति भी. किसानों और गरीबों का लोन माफ नहीं किया जाता है, वहीं अमीरों का लोन माफ कर दिया जाता है.

छोला दशहरा मैदान में आयोजित परिवर्तन रैली में महिलाओं, किसानों, व्यापारियों और मजदूरों ने सीएम अरविंद केजरीवाल का सम्मान किया. मध्यप्रदेश में आप के संयोजक आलोक अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले 11 साल में सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है. यह कुशासन की सरकार है. उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए देश में दंगा फैलाने में भी संकोच नहीं करती हैं. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी देश की जनता को लूटते हैं और बची–खुची कसर सीएम शिवराज सिंह चौहान पूरी कर देते हैं. 2018 में हम लूट की सरकार को उखाड़ फेकेंगे. ■

feedback@chauthiduniya.com

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

क्षेत्रीय दलों का कमज़ोर होना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है

अब भी फैसला लेने वाले उच्च अधिकारी यानी वित्त मंत्री ये बताएं कि आखिर कब तक पुराने नोट के बदले नए नोट लोगों को मिल जाएंगे. ये कहा जा रहा है कि लगभग सारे विमुद्रीकृत नोट वापस आ गए हैं. अगर ऐसा है, तो कालाधन की जो उम्मीद की गई थी, वो गलत साबित हुई है. नकली मुद्रा और आतंकवाद पर लगाम का दावा पहले ही गलत साबित हो चुका है. प्रधानमंत्री ने अब नोटबंदी का उद्देश्य ही बदल दिया है. वे अब कैशलेस या कम कैश वाली इकोनॉमी की बात कर रहे हैं. दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भाषणों की गुणवत्ता और गरिमा घटती जा रही है. यह काम प्रधानमंत्री का नहीं है कि वे लोगों को समझाएं कि कैसे एक कार्ड को स्वाइप करना है, यह काम तो क्रेडिट कार्ड सेल्समैन का है. हां, सरकार बड़े पैमाने पर इसका प्रचार करने के लिए अपने बैंकों को बोल सकती है. बैंक कर्मचारी लोगों के घरों में जाकर उन्हें समझाएंगे कि पेटीएम, ई वैलेट का उपयोग कैसे करते हैं.

चार राज्यों के साथ यूपी चुनाव की घोषणा हो गई है. इसने राजनीतिक गतिविधियों को गरम कर दिया है और 11 मार्च तक परिणाम आ जाएगा. हम इसका विश्लेषण बाद में करेंगे. पहले मुद्दा ये है कि विमुद्रीकरण से उपजी समस्या अभी तक व्यवस्थित नहीं हो सकी है. बैंकों में पुराने नोटों को बदलने के लिए पर्याप्त मुद्रा नहीं है. पता नहीं किस गणना के आधार पर प्रधानमंत्री और सरकार ने घोषणा की कि 30 दिसंबर तक आप अपने नोट बदल सकते हैं. उन्हें लगा कि तब तक सभी नोट बदल जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. इसके बाद 31 मार्च तक रिजर्व बैंक के माध्यम से नोट बदलने का विकल्प दिया गया.

ऐसा लगता है कि पुराने नोट बदलने के लिए रिजर्व बैंक की शाखाओं के पास पैसे नहीं हैं और न ही नोटों को बदलने की सुविधा है. पहली बात सरकार को ये करनी चाहिए कि वो 31 मार्च तक सभी बैंकों को नोट बदलने की अनुमति दे, ताकि आम आदमी पर दबाव कम हो सके. बेशक, सरकार के पास ही ये आंकड़े होंगे कि कितनी मुद्रा छपी है, कितनी आनी है और वास्तव में कब तक स्थिति आसान होगी. चिदंबरम ने सही भविष्यवाणी की थी कि सबकुछ सामान्य होने में सात महीने का समय लगेगा यानी अप्रैल-मई तक सामान्य स्थिति आ सकती है. मैं सरकार की इस जल्दबाजी को समझ नहीं पा रहा हूं. हर आदमी को उसके पैसे के बदले पैसा मिलना चाहिए. काला या सफेद का मसला आयकर विभाग देखेगा. जिस किसी के पास एक वचनपत्र के रूप में नोट है, उसे नया नोट मिलना ही चाहिए. ये एक बहुत साधारण सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है.

अब भी फैसला लेने वाले उच्च अधिकारी यानी वित्त मंत्री ये बताएं कि आखिर कब तक पुराने नोट के बदले नए नोट लोगों को मिल जाएंगे. ये कहा जा रहा है कि लगभग सारे विमुद्रीकृत नोट वापस आ गए हैं. अगर ऐसा है, तो कालाधन की जो उम्मीद की गई थी, वो गलत साबित हुई है. नकली मुद्रा और आतंकवाद पर लगाम का दावा पहले ही गलत साबित हो चुका है. प्रधानमंत्री ने अब नोटबंदी का उद्देश्य ही बदल दिया है. वे अब कैशलेस या कम कैश वाली इकोनॉमी की बात कर रहे हैं. दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भाषणों की गुणवत्ता और गरिमा घटती जा रही है. यह काम प्रधानमंत्री का नहीं है कि वे लोगों को समझाएं कि कैसे एक कार्ड को स्वाइप करना है, यह काम तो क्रेडिट कार्ड सेल्समैन का है. हां, सरकार बड़े पैमाने पर इसका प्रचार करने के लिए अपने बैंकों को बोल सकती है. बैंक कर्मचारी लोगों के घरों में जाकर उन्हें समझाएंगे कि पेटीएम, ई वैलेट का उपयोग कैसे करते हैं. प्रधानमंत्री का यह सब निजी शौक हो सकता है, लेकिन सार्वजनिक रूप से इस तरह की बात कर वे प्रधानमंत्री पद को छोटा नहीं कर सकते हैं. राजनीति में हर किसी को लगता है कि उसके इस कदम से वो लोकप्रिय हो रहा है. देखते हैं, क्या होता है?

विश्व परिदृश्य में मुझे लगता है कि अमेरिका ये कह रहा है कि भारत मंदी की दिशा में जा रहा है. 8 नवंबर के बाद कई अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक मंदी की भविष्यवाणी की थी. बहरहाल, हमें इंतज़ार करना होगा. अगर ऐसा होता है तो यह एक दुखद स्थिति होगी क्योंकि भारत में इस समय सबसे बड़ी जरूरत रोजगार सृजन है. नोटबंदी से दिहाड़ी मजदूर, निर्माण मजदूर आदि के रोजगार छीन गए हैं. प्लास्टिक कार्ड जब आएगा, तब आएगा, बैंक भी खुलते रहेंगे, लेकिन इस तत्कालिक समस्या से बचा जा सकता था. इसने निश्चित रूप से सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ लोगों के मन में गुस्सा भर दिया है. हालांकि, वे ऐसा नहीं समझते.

यूपी चुनाव पर आते हैं. 403 में से 224 सीट जीतकर 5 साल तक आराम से सरकार चलाने वाली समाजवादी पार्टी आज टूटने के कगार पर है. यह लंबे समय में भारतीय राजनीति के लिए अच्छा नहीं है. कौन जीतता है, यह बहुत छोटी बात है. मतदाता किसी को वोट देंगे, कोई जीतेगा, कोई हारेगा. लेकिन यह संदेश मिलना कि राष्ट्रीय दलों के अलावा अन्य क्षेत्रीय दल शासन कर ही नहीं सकते, गलत है. ज़ाहिर है, मायावती की अपनी पार्टी पर पकड़ मजबूत है. अगर सपा दो धड़ों में बंट कर लड़ती है, तो इसका फायदा मायावती को होगा. अगर ऐसा होता है, तो ठीक है. उनके पांच साल के शासन में, 2007 से 2012 तक कानून-व्यवस्था ठीक थी. उत्तर प्रदेश में दो चीजें महत्वपूर्ण है, कानून-व्यवस्था और रोजगार. जो भी सरकार कानून और व्यवस्था बेहतर बनाने की बात करेगी, उसे फायदा होगा. अखिलेश यादव जो दावा कर लें, उनके कार्यकाल में कानून-व्यवस्था ठीक नहीं थी. पूरे राज्य में सत्तर फीसदी पुलिस स्टेशनों की जिम्मेदारी यादवों को दी गई. यह एक अच्छा संदेश नहीं देता है. बेशक, इसके लिए अकेले अखिलेश यादव ही नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी भी जिम्मेदार है. समाजवादी पार्टी का आधार यादव और मुस्लिम हैं, लेकिन चुनाव प्रचार, शासन, प्रशासन तीन अलग-अलग बातें हैं. चुनाव प्रचार में आप सभी काम करते हैं. एक बार जब आप शासन में आ जाते है, तब आपको निष्पक्ष शासन और प्रशासन के सिद्धांत के मुताबिक चलना होता है. आप पुलिस सेवा, आईएएस और अन्य सेवाओं में जातिवाद नहीं थोप सकते हैं.

जो भी चुनाव नतीजे आएं, उसके दो परिणाम होंगे. एक, या तो उत्तर प्रदेश में एक स्थिर सरकार बनेगी या फिर मोदी की नीतियों और भाजपा की राजनीति की दशा और दिशा तय होगी. यदि भाजपा स्पष्ट बहुमत पा जाती है, तो वे इसे नोटबंदी पर जनमत संग्रह मानेंगे. अगर वे हार गए तो विपक्ष भी यही कहेगा. मेरे हिसाब से ऐसा कहना मुद्दे की सरल व्याख्या करने जैसा होगा. चुनाव कोई एक बार आयोजित होने वाली घटना नहीं है. किसी एक नीति या एक कदम के लाभ या नुकसान हो सकते हैं, लेकिन आप इसे जनमत संग्रह नहीं बता सकते. ऐसा कहना एक खतरनाक बात है.

केजरीवाल और मायावती ने कहा है कि क्या केंद्र सरकार को 1 फरवरी को बजट पेश करने की

मैं उन लोगों में से नहीं हूं, जो ये महसूस करते हैं कि न्यायपालिका हमेशा सही होती है, लेकिन एक संतुलन है और उस संतुलन को बनाए रखा जाना चाहिए. न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायाधीश करें, ये अच्छी बात नहीं है. लेकिन मुझे लगता है कि भारत के राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और सरकार को बुलाकर ये चर्चा कर सकते हैं कि क्या हो रहा है? हमारे संविधान के भीतर से ही समाधान की तलाश की जानी चाहिए, जो बहुत लचीला है.

अनुमति दी जानी चाहिए. वित्त मंत्री ने इसे संवैधानिक आवश्यकता बताया है. इसमें दो तथ्य हैं. पहला, संवैधानिक आवश्यकता ये है कि 31 मार्च से पहले संसद दो या तीन महीने के लिए होने वाले व्यय की स्वीकृति दे दे, जब तक पूरे साल के बजट को मंजूरी नहीं मिल जाती है. यह हर साल होता है, बजट 28 फरवरी को पेश होता है और मार्च में लेखानुदान लिया जाता है. बजट की पूरी प्रक्रिया अप्रैल या मई तक पूरी कर ली जाती है और व्यय में कोई कठिनाई नहीं होती है. चुनाव प्रक्रिया 11 मार्च तक खत्म हो जाएगा. उसके बाद आप 15 मार्च से बजट सत्र बुला सकते हैं, लेकिन केंद्र सरकार को नई योजना की घोषणा करने की अनुमति देना अनावश्यक है. मुझे यकीन है कि चुनाव आयोग योजनाओं की घोषणा न करने की सलाह सरकार को देगा. बजट लोक-लुभावन योजनाओं की घोषणा करने का एक माध्यम है. यहां तक कि मार्च 2014 में जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने बजट पेश किया था, तब उसमें कर के प्रस्ताव नहीं दिए गए थे और यह काम नई सरकार पर छोड़ दिया था. वही काम यहां भी किया जाना चाहिए. जिन राज्यों में चुनाव है, वहां के लिए आप नई रेल लाईन या किसी अन्य योजना की घोषणा नहीं कर सकते हैं. यह चुनाव के लिए ठीक नहीं होगा.

प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री से अधिक पार्टी प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं. बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ते. पटना में गुरु गोविंद सिंह की 350वीं प्रकाशोत्सव के मौके पर राजनीति नहीं होनी चाहिए. उन्होंने वहां नीतीश सरकार की प्रशंसा की, लेकिन असल खेल क्या है? नीतीश कुमार ने विमुद्रीकरण का समर्थन किया है. दरअसल, प्रधानमंत्री का लक्ष्य नीतीश कुमार को लालू यादव से दूर करना है और शायद सरकार बनाना भी है. ये देश के लिए अच्छा नहीं है. मोदी कांग्रेस के खिलाफ बोल सकते हैं, 70 साल की बात कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के 70 साल ने ही ये सुनिश्चित किया है कि चुनाव ठीक से हों, समय पर हों और बिना झड़प के सत्ता हस्तांतरण हो. सेना और पुलिस का इस सब में कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं होता है. आपातकाल की बात छोड़ दें, तो लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं. इमरजेंसी की भूल को भी श्रीमती गांधी ने सुधारा. लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से दोबारा सत्ता में आईं. लेकिन दुर्भाग्य से यह सरकार सभी गलत उदाहरणों का अनुपालन करना चाहती है और स्वस्थ उदाहरणों को छोड़ना चाहती है. यदि हम इंग्लैंड और अमेरिका की नकल कर रहे हैं, तो यह नकल भी बहुत ध्यान से और उचित तरीके से करना चाहिए.

मैं उन लोगों में से नहीं हूं, जो ये महसूस करते हैं कि न्यायपालिका हमेशा सही होती है, लेकिन एक संतुलन है और उस संतुलन को बनाए रखा जाना चाहिए. न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायाधीश करें, ये अच्छी बात नहीं है. लेकिन मुझे लगता है कि भारत के राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और सरकार को बुलाकर ये चर्चा कर सकते हैं कि क्या हो रहा है? हमारे संविधान के भीतर से ही समाधान की तलाश की जानी चाहिए, जो बहुत लचीला है. हमारा संविधान इतना अच्छा है कि इसमें सब समस्याओं का जवाब है. समस्या राजनीतिक दलों के साथ है, वे अपनी सोच, दृष्टिकोण में संकीर्ण होते जा रहे हैं. राजगार पर ध्यान केंद्रित करने की जगह हम कहीं और ध्यान दे रहे हैं. उम्मीद करिए कि सब ठीक किया जा सकता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

'हिंद स्वराज'

कांग्रेस और उसके कर्ता-धर्ता (भाग दो)

महसूल का हक़ प्रजा को होना चाहिए, ऐसी मांग कांग्रेस ने हमेशा की है. जैसा स्वराज्य कैनेडा में है वैसा स्वराज्य कांग्रेस ने हमेशा चाहा है. वैसा स्वराज्य मिलेगा या नहीं मिलेगा, वैसा स्वराज्य हमें चाहिए या नहीं चाहिए, उससे बढ़कर दूसरा कोई स्वराज्य है या नहीं, यह सवाल अलग है. मुझे दिखाना तो इतना ही है कि कांग्रेस ने हिन्द को स्वराज्य का रस चखाया.

पाठक- यह आपने ठीक कहा. दादाभाई नौरोजी की इज्जत करना चाहिए, यह तो समझ सकते हैं. उन्होंने और उनके जैसे दूसरे पुरुषों ने जो काम किए हैं, उनके बगैर हम आज का जोश महसूस नहीं कर पाते, यह बात ठीक लगती है. लेकिन यही बात प्रोफेसर गोखले साहब के बारे में हम कैसे मान सकते हैं? वे तो अंग्रेज़ों के भाईबंद बनकर बैठे हैं. वे तो कहते हैं कि अंग्रेजों से हमें बहुत कुछ सीखना है. अंग्रेज़ों की राजनीति से हम वाक़िफ़ हो जाएं, तभी स्वराज्य की बातचीत की जाए. उन साहब के भाषणों से तो मैं ऊब गया हूं.

संपादक- आप ऊब गए हैं, यह दिखाता है कि आपका मिजाज उतावला है. लेकिन जो नौजवान अपने मां-बाप के ठंडे मिजाज से ऊब जाते हैं और वे (मां-बाप) अगर अपने साथ न दौड़ें तो गुस्सा होते हैं, वे अपने मां-बाप का अनादर करते हैं, ऐसा हम समझते हैं. प्रोफेसर गोखले के बारे में भी ऐसा ही समझना चाहिए. क्या हुआ अगर प्रोफेसर गोखले हमारे साथ नहीं दौड़ते हैं? स्वराज्य भुगतने की इच्छा रखने वाली प्रजा अपने बुजुर्गों का तिरस्कार नहीं कर सकती. अगर दूसरे की इज्जत करने की आदत हम खो बैठें, तो हम निकम्मे हो जाएंगे. जो प्रौढ़ और तजरबेकार हैं, वे ही स्वराज्य भुगत सकते हैं, न कि वे-लगाम लोग. और देखिये कि जब प्रोफेसर गोखले ने हिन्दुस्तान की शिक्षा के लिए त्याग किया, तब ऐसे कितने हिन्दुस्तानी थे? मैं तो खास तौर पर मानता हूं कि प्रोफेसर गोखले जो कुछ भी करते हैं वह शुद्ध भाव से और हिन्दुस्तान का हित मानकर करते हैं. हिन्द के लिए अगर अपनी जान भी देनी पड़े तो वे दे देंगे, ऐसी हिन्द के लिए उनकी भक्ति है. वे जो कुछ कहते हैं, वह किसी की खुशामद करने के लिए नहीं, बल्कि सही मानकर कहते हैं. इसलिए हमारे मन में उनके लिए पूज्य भाव होना चाहिए.

पाठक- तो क्या वे साहब जो कहते हैं, उसके मुताबिक हमें भी करना चाहिए ?

संपादक- मैं ऐसा कुछ नहीं कहता. अगर हम शुद्ध बुद्धि से अलग राय रखते हैं, तो उस राय के मुताबिक चलने की सलाह खुद प्रोफेसर साहब हमें देंगे. हमारा मुख्य काम तो यह है कि हम उनके कामों की निंदा न करें, हमसे वे महान हैं, ऐसा मानें और यकीन रखें कि उनके मुकाबिले में हमने हिन्द के लिए कुछ नहीं किया है. उनके बारे में कुछ अख़बार जो अशिष्टतापूर्वक लिखते हैं, उसकी हमें निंदा करनी चाहिए और प्रोफेसर गोखले जैसों को हमें स्वराज्य का स्तंभ मानना चाहिए. उनके खयाल गलत और हमारे ही सही हैं, या हमारे खयालों के मुताबिक न बरतने वाले देश के दुश्मन हैं, ऐसा मान लेना बुरी भावना है.

पाठक- आप जो कुछ कहते हैं, वह अब मेरी समझ में कुछ आता है. फिर भी मुझे उसके बारे में सोचना होगा. पर मि. ह्यूम, सर विलियम वेडरबर्न वगैरा के बारे में आपने जो कुछ कहा, उसमें तो हद हो गई.

संपादक- जो नियम हिन्दुस्तानियों के बारे में है, वही अंग्रेज़ों के बारे में समझना चाहिए. सारे के सारे अंग्रेज़ बुरे हैं, ऐसा तो मैं नहीं मानूंगा. बहुत से अंग्रेज़ चाहते हैं कि हिन्दुस्तान को स्वराज्य मिले. उस प्रजा में स्वार्थ ज्यादा है, यह ठीक है, लेकिन उससे हर एक अंग्रेज बुरा है, ऐसा साबित नहीं होता. जो हक-न्याय चाहते हैं, उन्हें सबके साथ न्याय करना होगा. सर विलियम हिन्दुस्तान का बुरा चाहने वाले नहीं है, इतना हमारे लिए काफी है. ज्यों-ज्यों हम आगे बढ़ेंगे, त्यों-त्यों आप देखेंगे कि अगर हम न्याय की भावना से काम लेंगे, तो हिन्दुस्तान का छुटकारा जल्दी होगा. आप यह भी देखेंगे कि अगर हम तमाम अंग्रेज़ों से द्वेष करेंगे तो उससे स्वराज्य दूर ही जाने वाला है, लेकिन अगर उनके साथ भी न्याय करेंगे, तो स्वराज्य के लिए हमें उनकी मदद मिलेगी.

पाठक- अभी तो ये सब मुझे फिजूल की बड़ी-बड़ी बातें लगती हैं. अंग्रेज़ों की मदद मिले और उससे स्वराज्य मिल जाय, ये तो आपने दो उलटी बातें कहीं. लेकिन इस सवाल का हल अभी मुझे नहीं चाहिए. उसमें समय बिताना बेकार है. स्वराज्य कैसे मिलेगा, यह जब आप बतायेंगे, तब शायद आपके विचार मैं समझ सकूं, तो समझ सकूं. फिलहाल तो अंग्रेज़ों की मदद की आपकी बात ने मुझे शंका में डाल दिया है और आपके विचारों के खिलाफ़ मुझे भरमा दिया है. इसलिए यह बात आप आगे न बढ़ाएं तो अच्छा हो.

संपादक- मैं अंग्रेज़ों की बात को बढ़ाना नहीं चाहता. आप शंका में पड़ गये, इसकी कोई फिकर नहीं. मुझे जो महत्व की बात कहनी है, उसे पहले से ही बता देना ठीक होगा. आपकी शंका को धीरज से दूर करना मेरा फर्ज है.

पाठक- आपकी यह बात मुझे पसंद आयी. इससे मुझे जो ठीक लगे, वह बात कहने की मुझमें हिम्मत आई है. अभी मेरी एक शंका रह गई है. कांग्रेस के आरंभ से स्वराज्य की नींव पड़ी, यह कैसे कहा जा सकता है?

संपादक- देखिए, कांग्रेस ने अलग-अलग जगहों पर हिन्दुस्तानियों को इकट्ठा करके उनमें 'हम एक राष्ट्र हैं' ऐसा जोश पैदा किया. कांग्रेस पर सरकार की कड़ी नज़र रहती थी. महसूल का हक़ प्रजा को होना चाहिए, ऐसी मांग कांग्रेस ने हमेशा की है. जैसा स्वराज्य कैनेडा में है वैसा स्वराज्य कांग्रेस ने हमेशा चाहा है. वैसा स्वराज्य मिलेगा या नहीं मिलेगा, वैसा स्वराज्य हमें चाहिए या नहीं चाहिए, उससे बढ़कर दूसरा कोई स्वराज्य है या नहीं, यह सवाल अलग है. मुझे दिखाना तो इतना ही है कि कांग्रेस ने हिन्द को स्वराज्य का रस चखाया. इसका जस कोई और लेना चाहे, तो वह ठीक न होगा, और हम भी ऐसा मानें तो बेकदर ठहरेंगे. इतना ही नहीं, बल्कि जो मकसद हम हासिल करना चाहते हैं उसमें मुसीबतें पैदा होंगी. कांग्रेस को अलग समझने और स्वराज्य के खिलाफ़ मानने से हम उसका उपयोग नहीं कर सकते. ■

जब तोप मुक़ाबिल हो

संतोष भारतीय

सरकारें शहीदों का अपमान कर रही हैं

प्रधानमंत्री जी के बहाने मैं सभी देशवासियों से ये पूछना चाहता हूं कि क्या हम सब कृतघ्न हो गए हैं? क्या हमें उन लोगों की जरा भी चिंता नहीं है, जिन्होंने हमारे भविष्य के लिए अपनी जानें दीं. दो तरह के लोगों ने आजादी के आंदोलन में सहयोग दिया था. एक वो, जो गांधीजी के अहिंसक आंदोलन में अंग्रेजों का सामना कर रहे थे, जिन्होंने लाठियां खाईं, अंग्रेजों के घोड़ों की टापें झेलीं और सालों-साल जेल में रहे. उनमें से बहुत से लोग 15 अगस्त 1947 तक जीवित रहे और उन्होंने आजादी का सूरज देख लिया. दूसरी श्रेणी के वो लोग थे, जिन्होंने अंग्रेजों का मुकाबला गोलियों से किया. उन्होंने हथियारों से मुकाबला कर अंग्रेजों को हिन्दुस्तान से भगाने की कोशिश की और अपनी जान गंवाई. उनमें से वे लोग, जो अंग्रेजों की गोलियों से मारे गये, उनके नाम हमें बहुत नहीं मिलते. जो फांसी पर चढ़े, उनमें भी कइयों के नाम हमारे पास नहीं हैं. आजादी के बाद जितनी भी सरकारें बनीं, उनमें से किसी ने भी उनके नाम तलाशने की कोशिश नहीं की, पर हमारे पास कुछ नाम हैं.

हमारे पास वो नाम हैं, जिन्होंने अंग्रेज सरकार का मुकाबला करते हुए फांसी की सजा पाई. उन्होंने हंसते हुए फांसी के फंदे को चूमा और अपने गले में डाल लिया. उनके बारे में किताबों में कहीं-कहीं जिक्र है. कभी कभी उनका नाम भी लिया जाता है, पर ऐसा लगता है कि सारा देश उन्हें भूल चुका है. यह भूलना कृतघ्नता, एहसानफरामोशी और नाशुक्रेपन की निशानी है.

हरियाणा के जिंद जिले के दो लोग, जिनमें एक स्थानीय पत्रकार कुलदीप खंडेलवाल और दूसरे शिक्षक हैं मदनपाल, ये उन लोगों के गांवों और घरों में गए, जिन्होंने फांसी का फंदा चूमा था. वे लोग जब मेरे पास आए और उन्होंने फांसी पाए हुए शहीदों के गांवों में जाकर, उनके घर और परिवार की हालत बताई, तो मन ये करने लगा कि इन स्थितियों को जानने के बाद भी किसी शहीद के परिवार वाले देश सेवा के लिए किसी को कोई प्रेरणा देंगे. सवाल ऐसा है, जिसका किसी के पास उत्तर नहीं है.

पहला नाम शहीद रामप्रसाद बिस्मिल का. पंडित रामप्रसाद बिस्मिल वही हैं, जिनकी लिखी गई लाइनें गाते हुए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और उन्होंने खुद अपनी जान दी. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू-ए-कातिल में है. वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है. पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने शादी नहीं की थी. उनकी मां गांव में रहती थीं, जिनका देहांत शायद सन 1954 में हो गया था. उनके भाई थे, जिनका बेटा ईलाज के अभाव में दुनिया को प्यारा हो गया. इस समय उनके घर में कोई नहीं है और उनके घर का कोई नामोनिशान भी नहीं मिलता. श्री शिव वर्मा ने अपनी किताब में लिखा है कि मैं गोरखपुर जेल में रामप्रसाद बिस्मिल जी से उनकी मां के साथ उनका भाई या शायद बेटा बनकर मिलने के लिए पहुंचा था. उनसे मिलकर जब मैं लौटा, तब से उनकी मां से मेरा कोई संपर्क नहीं रहा. सन 1954 में जब मैं मिला, तो उनकी मां को दिखाई नहीं देता था. मैंने पूछा, मां आपको याद है, आप जब गोरखपुर जेल गयी थीं, तब आपके साथ एक बच्चा था. मां तुरंत बोलीं, अरे शिव है क्या? आज रामप्रसाद बिस्मिल का नाम लेने वालों की स्मृति में कुछ भी ऐसा नहीं है, जिससे पता चले कि देश का इतना बड़ा योद्धा इस गांव, ब्लॉक, जिले या इस प्रदेश में कभी रहा था.

दोनों नौजवानों ने अशफाकउल्लाह खां के गांव की भी यही हालत देखी. अशफाकउल्लाह खां, वो अजीमुश्शान नाम है, जिन्होंने पूरी मुस्लिम कौम का नाम शान से ऊंचा रखा. उनके कब्र की हालत देखकर इन दोनों नौजवानों की आंखों से आंसू निकल आए. उनकी याद में कोई स्मारक तो छोड़ दीजिए, कब्र तक की हालत ठीक करने की, न लोगों को और न सरकार को ही चिंता है.

क्रांतिकारी पंडित राजनारायण मिश्र के घर के लोग भट्ठे में मजदूरी कर रहे हैं. ईंटें उठा रहे हैं और कभी-कभी ईंटें पाथ भी रहे हैं. जब घरवालों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि यहां कभी कोई नहीं आता, कभी कोई नहीं पूछता है. ऐसा लगता है जैसे पंडित राजनारायण मिश्र नाम का कोई शख्स कभी दुनिया में आया ही नहीं.

क्या देश के लोगों या सरकार का ये फर्ज नहीं बनता कि हमारे लिए जान देने वाले लोगों के घरों में, अगर कोई है, तो उनकी देखभाल करें. शहीदों के स्मारक बनवाएं, उनका नाम जिंदा रखें. उनके प्रेरणादायी जीवन की घटनाओं पर एक पुस्तिका छपवा कर आस-पास बटवाएं. दरअसल ये काम तो सरकार का होना चाहिए, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की. लेकिन सरकारें नालायक हैं, काहिल हैं, नाशुक्री हैं. वो उन लोगों की कोई खोज-खबर नहीं रखती, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जानें दे दीं. उनके लिए वो व्यक्ति ज्यादा प्रमुख हैं, जो भ्रष्टाचार से पैसे कमाकर किसी न किसी नेता को आर्थिक लाभ पहुंचाते हैं.

> **क्या देश के लोगों या सरकार का ये फर्ज नहीं बनता कि हमारे लिए जान देने वाले लोगों के घरों में, अगर कोई है, तो उनकी देखभाल करें. शहीदों के स्मारक बनवाएं, उनका नाम जिंदा रखें. उनके प्रेरणादायी जीवन की घटनाओं पर एक पुस्तिका छपवा कर आस-पास बटवाएं. दरअसल ये काम तो सरकार का होना चाहिए, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की. लेकिन सरकारें नालायक हैं, काहिल हैं, नाशुक्री हैं. वो उन लोगों की कोई खोज-खबर नहीं रखती, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जानें दे दीं. उनके लिए वो व्यक्ति ज्यादा प्रमुख हैं, जो भ्रष्टाचार से पैसे कमाकर किसी न किसी नेता को आर्थिक लाभ पहुंचाते हैं.**

लेकिन लोगों को क्या हो गया है? क्या लोग भी नाशुक्रे हो गए हैं? मैं आपसे अपील करता हूं कि अगर आपके आस-पास कोई ऐसा शहीद है, जिसने मुल्क के लिए फांसी पर चढ़कर या गोलियों से जान दी है, आप कृपया हमें बताएं. हम और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनकी स्मृति में, उनके बारे में जानकारी छापकर लोगों को जरूर दे सकते हैं. मैं एक अपील और करता हूं कि आपके आस-पास जो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, जिन्होंने जेल काटे हैं, जिन्होंने अपनी जवानी जेलों में गुजारी है, गांधीजी के आंदोलन में हिस्सा लिया है और अगर वो जीवित हैं, उनके चरण छूकर उनका आशीर्वाद लें. वह आशीर्वाद भगवान के आशीर्वाद के बराबर ही आपको फल देगा. जिन लोगों ने जेलों में अपनी जिंदगी गुजारी है, देश के लिए बिना स्वार्थ लड़ा है, जिन्हें मालूम ही नहीं था कि देश कभी आजाद होगा, ऐसे लोगों को प्रणाम करना हमारा राष्ट्रीय और मानवीय कर्तव्य है. सरकार से भी अपील करना चाहेंगे कि वह उन सभी लोगों के नाम पर स्मारक बनवाए और उनके जीवन पर पुस्तक छपवाए. उदाहरण के लिए मैं अभी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, अस्फाकउल्लाह खां और पंडित राजनारायण मिश्र का नाम आपके सामने रख रहा हूं. मुझे पूरा विश्वास है कि इसके अलावा, जितने भी नाम आपको याद आते हैं, निश्चित रूप से उनके घरों की भी हालत ऐसी ही होगी, जैसी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकउल्लाह खां और पंडित राजनारायण मिश्र के घरों की है. हम अपनी नजरों में कृतघ्न बन रहे हैं, हम अपनी नजरों में नाशुक्रे बन रहे हैं और हम अपनी नजरों में नाइंसाफ बन रहे हैं. मेरी गुजारिश है, मेरी प्रार्थना है कि सरकार करे या न करे, आप अवश्य कुछ करें. कम से कम हमें इसकी जानकारी दें, ताकि हम उन शहीदों, उनके परिवार के लोगों और जीवित स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान उनके बारे में कुछ छापकर कर सकें. ■

editor@chauthiduniya.com

भारत-पाक वार्ता में गतिरोध बने रहने की उम्मीद

शुजात बुखारी

2015 के 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जहाज़ जब अचानक पाकिस्तान के लाहौर हवाई अड्डे पर उतरा और उन्होंने नवाज़ शरीफ़ को उनके जन्मदिन पर व्यक्तिगत रूप से मुबारकबाद दी, तो भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर काफ़ी कानाफूसी हुई. दुर्भाग्य से इस गुब्बारे में से जल्द ही हवा निकल गई, जब पठानकोट के एक एयरबेस पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया. नरेन्द्र मोदी के अचानक दौरे से जो उम्मीदें बंधी थीं, वह चकनाचूर हो गईं. हालांकि इस बात पर भारत का गुस्सा करना जायज था, लेकिन उसने इस मौके पर धैर्य से काम लिया. एक संयुक्त जांच टीम के गठन की घोषणा की गई, जिसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का एक अधिकारी भी शामिल किया गया. इस टीम ने भारतीय क्षेत्र का दौरा किया, लेकिन बाद में पाकिस्तान जाने की अनुमति नहीं मिली. तब से दोनों देशों के बीच तमाम मामले अटके हुए हैं.

इस वर्ष भी मोदी ने नवाज़ शरीफ़ के जन्मदिन पर उनके साथ संपर्क किया, लेकिन इस बार उन्होंने महज़ टेलीफोन लाइन का प्रयोग किया. इस दौरान मोदी और नवाज़ के बीच जिस अंदाज में बातचीत हुई, ज़ाहिर है इस पर पूरे साल दोनों ओर होने वाली घटनाओं का साया ज़रूर मंडराया होगा. इस पर रही-सही कसर कश्मीर की पांच महीने लंबी हड़ताल और नवाज़ शरीफ़ की ओर से संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर समस्या उठाए जाने के कारण पूरी हो गई. उधर खुद पाकिस्तान में एक बार फिर कश्मीर समस्या उभर कर सामने आई है. हालांकि पिछले कुछ अर्से से पाकिस्तान में मीडिया, सरकार और सिविल सोसायटी के स्तर पर कश्मीर को लेकर थकावट सी महसूस हो रही थी, लेकिन आज के हालात अलग हैं. आज वहां कश्मीर हर बहस का हिस्सा बन चुका है और वह भी एक बेहद कड़े रुख़ के साथ. विशेष रूप से पिछले पांच महीनों के दौरान जिस प्रकार से कश्मीर में लोगों को गोलियों और पैलेट गन से मारा गया, अंधा बनाया गया और जेलों में बंद किया गया, इस वजह से पाकिस्तानियों के दिलों में कश्मीर के प्रति बेहद नरम और भावुक रिश्ता पैदा हुआ है.

शुरुआती दिनों यानी 8 जुलाई को बुरहान वानी की मौत और कश्मीर समस्या को लेकर पैदा होने वाले दबाव को छोड़कर बाद के दिनों में कश्मीर में जिस प्रकार के हालात पैदा हुए, उनकी वजह से पाकिस्तानी समाज में कश्मीरियों के प्रति बहुत अधिक हमदर्दी पैदा हुई. हालात ऐसे बन गये कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ को कश्मीर में बढ़ती हुई मौतों पर मातम के लिए एक दिवसीय 'यौम-ए-सियाह' की अपील करनी पड़ी और उनको भारत के प्रति कड़ा रवैया अपनाना पड़ा. पाकिस्तान के रवैये में परिवर्तन और पठानकोट हमले के बाद भारतीय टीम को पाकिस्तान का दौरा करने की अनुमति नहीं देना भी एक वजह बना और भारत ने पाकिस्तान पर और विश्वास न करने का निर्णय कर लिया. प्रधानमंत्री मोदी भी इसके बाद शांति स्थापना के प्रयासों पर आगे न बढ़े, जिस गति से उन्होंने अपने अचानक लाहौर दौरे से इसे शुरू किया था. विडंबना यह कि दोनों ओर लाइन ऑफ कंट्रोल पर बंदूकें तन गईं और तोपों के गोले बरसने लगे, जिसने पहले से लगी आग को और भड़का दिया. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए पनामा गेस्ट स्कैंडल के सामने आते ही यह मजबूरी बन गई कि उसे भारत के प्रति पुरानी नीति पर ही अमल करना पड़ा. नई दिल्ली की ओर से भी वार्ता का दौर दोबारा शुरू करने की कोई कोशिश नहीं की गई. ताज़ा ख़बर यह है कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के संयुक्त चेयरपर्सन आसिफ़ अली ज़रदारी की ओर से 18 महीनों की वतन वापसी के बाद उन्होंने भी कश्मीर मसले को उठाना शुरू कर दिया है. उन्होंने अपने समर्थकों से साफ़ कह दिया है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन कर रहेगा. उन्होंने कश्मीर में बीते दिनों होने वाली घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि पाकिस्तानी झंडा कश्मीर में विरोध का प्रतीक बन चुका है. ज़रदारी का ऐसा कहना कहां तक सही है, यह बात सभी जानते हैं. लिहाज़ा वह ऐसा कर अपने वोट बैंक से मुख़ातिब होना चाहते हैं क्योंकि कश्मीर मसला फिर ज़िंदा हो गया है. इससे पहले पिछले कई वर्षों से कश्मीर की समस्या का मुद्दा पाकिस्तानी चुनावों से ग़ायब ही हो गया था. हालांकि 2013 के चुनावों में किसी एक भी पाकिस्तान की पार्टी ने 'कश्मीर' शब्द का प्रयोग चुनावों के दौरान नहीं किया. इस दौरान आंतरिक हालात, आतंकवाद और भ्रष्टाचार ही ऐसे मुद्दे रहे, जो पूरे चुनावी मुहिम पर छाये रहे, जिसकी वजह से नवाज़ शरीफ़ सत्ता में वापस लौटे. इस पूरे चरण में पाकिस्तानी सेना को छोड़कर हर ओर कश्मीर समस्या को लेकर एक अजीब सी थकावट का प्रदर्शन हो रहा था. कश्मीर के ज़मीनी हालात की वजह से यह अंतर पड़ा है कि खुद प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ को भी सितंबर में संयुक्त राष्ट्र के स्टेज पर कश्मीरी जनता की ज़ोरदार वकालत करना पड़ी और बुरहान को कश्मीर की 'नई नस्ल का हीरो' क़रार देने के लिए मजबूर होना पड़ा. कश्मीर के असामान्य हालात को लेकर राजनीतिक दलों में बढ़त लेने का लगभग मुकाबला ही शुरू हो गया. जाहिर है कि वे इस बात को आगामी चुनावों में भी इस्तेमाल करेंगे. आसिफ़ ज़रदारी के बेटे बिलावल भुट्टो ने भी इसी वर्ष वहां होने वाले चुनावों के दौरान कश्मीर शब्द का प्रयोग किया.

पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कश्मीर को लेकर हमेशा कड़ा रुख रहा है. विश्लेषकों का मानना है कि पीपीपी के उत्थान में कश्मीरी फैक्टर का काफ़ी प्रभाव रहा है. पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय जुल्फिकार अली भुट्टो 1964 में भारतीय प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री और पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल अयूब खान के बीच कश्मीर को लेकर होने वाले ताशकंद समझौते के कड़े विरोधी थे. यह मतभेद भुट्टो के विदेशमंत्री के हैसियत से बेदखली का कारण बना. इससे कुछ दिनों पूर्व उन्होंने भारत के साथ एक हजार वर्षों तक लड़ाई लड़ने की बात भी कही थी. भुट्टो की इस परंपरा को उनकी बेटी बेनज़ीर भुट्टो ने भी जारी रखा. हालांकि उन्होंने अपने शासनकाल में भारतीय समकक्ष राजीव गांधी के साथ मिलकर शांति स्थापना की बहुत कोशिशें कीं, लेकिन उन्होंने कश्मीर समस्या को लेकर अपने कड़े रुख में कोई बदलाव नहीं किया. यह उन्हीं का शासनकाल था, जब इस्लामी देशों की कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर को लेकर एक संपर्क समूह का गठन किया था. इसमें हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया. ज़रदारी का 23 दिसंबर का बयान स्वर्गीय बेनज़ीर भुट्टो के उस रुख की ही अनुशंसा थी, जिसमें उन्होंने एक आज़ाद जम्मू-कश्मीर के रुख को खारिज किया था. यह सोच आज के कश्मीर का चित्रण करती नज़र आती है.

आज की स्थिति यह है कि पाकिस्तान में कश्मीर के पक्ष में एक आंदोलन शुरू हो चुका है. इसी के समान भारत में भी पाकिस्तान विरोधी लहर चल रही है. इस स्थिति के कारण इन लोगों को एक बार फिर सामने आने का मौक़ा मिल चुका है, जो कश्मीर समस्या के हल के लिए केवल और केवल हिंसा को ही एकमात्र तरीका क़रार देते हैं. कश्मीर में बीते महीनों के दौरान भारतीय सेना के हाथों होने वाली मौतों और अत्याचारों ने इस आंदोलन को बढ़ावा देने और अनावश्यक तत्वों को इस तरफ आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. यहां जो भी कुछ होता है, वह सेकंडों में पाकिस्तान में पहुंच जाता है. पैलेट गन के घावों का सोशल मीडिया पर जो प्रचार हुआ, इसका पाकिस्तानी जनता के दिलों पर गहरा असर पड़ा. इस्लामाबाद में रह रहे एक पाकिस्तानी पत्रकार दोस्त ने बताया कि इसकी वजह से 2016 के कश्मीर और 1990 के कश्मीर में अंतर करने में काफी मदद मिली है. इस पूरी स्थिति में मोदी का नवाज़ शरीफ़ को फोन करना महज़ एक रस्म है, जिससे दोनों देशों के बीच वार्ता को लेकर पैदा होने वाले गतिरोध को तोड़ने या वार्ता के लिए कोई माहौल तैयार करने में मदद नहीं मिल सकती. आवश्यकता इस बात की है कि भारत और पाकिस्तान की जनता अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना छोड़कर कोई रास्ता निकालने की कोशिश करें. जहां तक भारत का सवाल है, यहां ऐसा फिलहाल कुछ ऐसा नजर नहीं आता है क्योंकि भारत में अगले तीन महीनों के दौरान पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. इस दौरान भारतीय जनता पार्टी की यही कोशिश होगी कि वह कोई ऐसी रणनीति तैयार करे, जिससे उसे इन चुनावों में अधिक से अधिक समर्थन प्राप्त हो सके. इसकी वजह से भारत में विरोधी तत्वों को और आगे आने का मौक़ा मिलेगा. इन हालात में दोनों ओर विरोधी तत्वों के लिए ही अवसर नज़र आ रहे हैं. ■

पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कश्मीर को लेकर हमेशा कड़ा रुख रहा है. विश्लेषकों का मानना है कि पीपीपी के उत्थान में कश्मीरी फैक्टर का काफ़ी प्रभाव रहा है. पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय जुल्फिकार अली भुट्टो 1964 में भारतीय प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री और पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल अयूब खान के बीच कश्मीर को लेकर होने वाले ताशकंद समझौते के कड़े विरोधी थे. यह मतभेद भुट्टो के विदेशमंत्री के हैसियत से बेदखली का कारण बना. इससे कुछ दिनों पूर्व उन्होंने भारत के साथ एक हजार वर्षों तक लड़ाई लड़ने की बात भी कही थी. भुट्टो की इस परंपरा को उनकी बेटी बेनज़ीर भुट्टो ने भी जारी रखा. हालांकि उन्होंने अपने शासनकाल में भारतीय समकक्ष राजीव गांधी के साथ मिलकर शांति स्थापना की बहुत कोशिशें कीं, लेकिन उन्होंने कश्मीर समस्या को लेकर अपने कड़े रुख में कोई बदलाव नहीं किया. यह उन्हीं का शासनकाल था, जब इस्लामी देशों की कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर को लेकर एक संपर्क समूह का गठन किया था. इसमें हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया.

–लेखक राइजिंग कश्मीर के संपादक हैं.

feedback@chauthiduniya.com

www.vastuvihar.org
वास्तु विहार®
एक विश्वस्तरीय टाउनशिप
AN ISO : 9001 : 2008 : 14001 : 18001 : 2007 COMPANY

बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के 63 शहरों में 117 आवासीय परियोजनाओं की श्रृंखला

Call : 95340 95340

मनोज तिवारी

सरकारी घोषणा के बाद भी नहीं हुआ शौचालय का काम पूरा

अधूरा है स्वच्छ बेलसंड का दावा

एक ओर जहां राज्य सरकार अपने प्रशासनिक तंत्र की बदौलत स्वच्छता मिशन को सफल करार देने में लगी है, वहीं दूसरी ओर सरकार का प्रशासनिक महकमा भी अपनी वाहवाही में व्यस्त है. पिछले 19 नवंबर को सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने निश्चय यात्रा के दौरान सीतामढ़ी जिले के बेलसंड को खुले में शौच से मुक्त अनुमंडल घोषित किया, साथ ही इसे बिहार के अन्य जिलों के लिए अनुकरणीय भी बताया. लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही सच्चाई बयां कर रही है.

वाल्मीकि कुमार

सीतामढ़ी जिले के बेलसंड अनुमंडल क्षेत्र में जब स्वच्छता अभियान की चर्चा शुरू हुई, तब झोपड़ियों में रहने वाले ग्रामीणों को भी लगा था कि अब सचमुच अच्छे दिन आने वाले हैं. सरकारी प्रोत्साहन राशि से घर-घर शौचालय निर्माण की चर्चा मात्र से ही ऐसे परिवारों के लोग खुश हो गए थे, जिनके घर की महिलाओं व बच्चियों को शौच के लिए शाम ढलने का इंतजार करना पड़ता था. निर्धारित कार्यक्रम के तहत जब गांव-गांव में शौचालय निर्माण की कवायद शुरू हुई, तो लोगों ने शुरुआती दिनों में इसे अतिआवश्यक मानकर कार्य को संपन्न कराना मुनासिब समझा. कई जगह तो शाम ढलते ही गांव की सड़कों से महिलाओं को खदेड़ा जाने लगा. हर ओर एक अजीब स्थिति बनती चली गयी. यह भी कहा गया कि जो भी सड़क किनारे खुले में शौच करते पकड़े जाएंगे, उन्हें दंडित किया जाएगा. नतीजतन सभी तबके के लोगों ने शौचालय निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना शुरू किया. प्रशासनिक स्तर पर बताया गया कि शौचालय निर्माण कराने वालों को बाद में सरकार की तरफ से 12 हजार रुपये का भुगतान किया जाएगा. फिर क्या था, गांव-गांव में ईंट गिरने लगे. बालू व सिमेंट का व्यवसाय भी जोर पकड़ने लगा. गरीब व मध्यमवर्गीय परिवार के लोग किसी प्रकार कर्ज लेकर शैचालय निर्माण कराने लगे. बहुत ऐसे भी परिवार हैं, जो प्रयास के बाद भी निर्माण कराने में असमर्थ रहे.

इसे प्रशासनिक शिथिलता कहें, लोगों की आर्थिक परेशानी या जागरुकता का अभाव, बेलसंड को खुले में शौच से मुक्त अनुमंडल कहना एक बेमानी है. बेलसंड अनुमंडल के परसौनी प्रखंड अंतर्गत देमा पंचायत के मुशहरी गांव में वार्ड संख्या 1 में तकरीबन तीन दर्जन परिवार ऐसे हैं, जो शौचालय का निर्माण नहीं करा सके हैं. इस बाबत बातचीत में लोगों ने बताया कि आर्थिक परेशानी ही शौचालय निर्माण की सबसे बड़ी बाधा है. सरकार की तरफ से मिलने वाली राशि, निर्माण के बाद कब तक मिलेगी कहा नही जा सकता. बुधई पासवान, राजकुमार पासवान, किशुन पासवान, रामयश पासवान व संजय पासवान जैसे कई ग्रामीणों को शौचालय निर्माण के बाद भी अब तक राशि का भुगतान नहीं किया जा सका है. ये सभी लोग परेशान हैं, क्योंकि जिन महाजनों से कर्ज लेकर इन्होंने शौचालय का निर्माण कराया था, वे अब पैसों के लिए इनपर दबाव डालने लगे हैं. अपने शौचालय की टंकी का ढक्कन बनवा रही राधिका देवी का कहना था कि क्या करें, हाकिम लोग बार-बार आकर डरा रहे हैं कि अब बाहर खुले में नही जाना है. ऐसी स्थिति में किसी प्रकार से कर्ज लेकर शौचालय बनवा रहे हैं. हरगेन पासवान ने अपने निर्मित शौचालय को दिखाते हुए कहा कि पैसों के अभाव में किवाड़ नही लगवा सके हैं. गांव के विष्णुदेव पासवान, शिवनाथ पासवान, रामचंद्र पासवान, रामबली पासवान, लालबहादूर पासवान, गोपाल पासवान, दरेश पासवान, छकौड़ी पासवान, काशी पासवान, सीताराम पासवान, शिवदयाल पासवान, रेबन पासवान, मुखलाल पासवान, लालबाबू पासवान, मेघू पासवान, अजय पासवान व विजय पासवान समेत दर्जनों परिवार अब तक शौचालय का निर्माण नहीं करा सके हैं. इधर लोहासी पंचायत के वार्ड संख्या 12 निवासी रामचंद्र राय, राम सेवक राय, अकलू ठाकुर, मीना देवी, शत्रुघ्न राय, रामवती देवी, बैद्यनाथ राय व कपिल राय समेत अन्य का कहना था कि शौचालय निर्माण के लिए प्रशासनिक स्तर पर सख्ती के कारण किसी प्रकार निर्माण तो करा लिया है. परंतु अब तक राशि का भुगतान नहीं किया गया है. बेलसंड को खुले में शौच से मुक्त अनुमंडल की घोषणा पर भाजपा के पूर्व विधान पार्षद बैद्यनाथ प्रसाद ने साफ शब्दों में कहा कि जब तक व्यवहारिक रूप में लक्ष्य पूरा नही किया जा सकता तब तक हम इसे पूर्ण नही कह सकते. जिला पदाधिकारी ने अवश्य ही हर संभव और बेहतर प्रयास किया है, लेकिन कुछ स्थानों पर लोगों ने खानापूर्ति किया है. इन्होंने सीएम के पूर्ण स्वच्छ अनुमंडल की घोषणा को राज्य की विधि व्यवस्था व शराबबंदी की घोषणा के समान बताया. कहा कि जमीनी मुआयना के बाद सबकुछ साफ हो सकता है.

हालांकि मुख्यमंत्री की घोषणा के तकरीबन डेढ़ माह बाद से अनुमंडल क्षेत्र में राशि वितरण की कवायद शुरू की गई है. सीतामढ़ी के जिला पदाधिकारी राजीव रौशन का कहना है कि वार्ड सदस्य व मुखिया ओडीएफ पंचायत की घोषणा करते हैं. प्रत्येक पंचायत के मुखिया व वार्ड सदस्यों द्वारा आश्वस्त किए जाने के बाद ही जिला प्रशासन द्वारा राशि दी जा रही है. अगर किसी पंचायत के प्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन को भ्रमित करने का कार्य किया हो, तो जांचोपरांत वैसे पंचायत प्रतिनिधियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी. डीएम ने बताया, परसौनी खिरौधर पंचायत को 2 करोड़ 61 लाख व लोहासी को 1 करोड़ 71 लाख का भुगतान किया जा चुका है. इसके अलावा नानपुर व ददरी पंचायत को भी राशि दी जा चुकी है. शेष पंचायतों के मुखिया व वार्ड सदस्यों द्वारा कार्य समाप्ति की घोषणा के बाद राशि का भुगतान कर दिया जाएगा. इससे पहले बेलसंड अनुमंडल पदाधिकारी सुधीर कुमार ने 21 दिसंबर 2016 को क्षेत्र में शेष बचे घरों के सवाल पर साफ शब्दों में कहा था कि जिन्होंने शौचालय नही बनाए हैं, उन्हे राशि नही दी जाएगी. अब जो लोग खुले में शौच करते पाए जाएंगे, उन्हे पंचायत स्तर पर दंडित किया जाएगा. एसडीओ ने बताया कि राशि दिए जाने से पहले तीन स्तर पर जांच के लिए शिक्षकों को लगाया गया है. हर शिक्षक करीब एक दर्जन परिवारों के शौचालय निमार्ण की जांच कर रिपोर्ट देंगे. जिन लोगों ने शौचालय निमार्ण का कार्य पूरा नहीं कराया है, या जिन्होंने बना लिए हैं, लेकिन उपयोग नहीं कर रहे हैं या जिनका पूर्व से शौचालय बना है, ऐसे लोगों को राशि से वंचित होना पड़ेगा.

बीएन प्रसाद- पूर्व विधान पार्षद

डीएम राजीव रौशन

एसडीओ सुधीर कुमार

अब सवाल उठता है कि अगर किसी गांव में 500 घर हैं, जहां 50 घर के लोगों ने शौचालय नही बनाया, तो इन्हें केवल सरकारी राशि से वंचित कर देना ही समाधान है? क्या ऐसे परिवारों की पहचान कर उन्हें शौचालय निर्माण के लिए प्रेरित नही करना चाहिए? आर्थिक रूप से परेशान लोगों के लिए अग्रिम राशि की व्यवस्था कर उन्हें प्रोत्साहित नही करना चाहिए? क्या पंचायत स्तर पर दंडित किए जाने की बात से सामाजिक विद्वेष नहीं बढ़ेगा? मतलब साफ है कि प्रशासनिक महकमों का मकसद केवल और केवल खुद की वाहवाही भर है. प्रशासन एक तीर से दो शिकार वाली कहावत को चरितार्थ करने में लगा है. एक ओर सरकार से वाहवाही लूटी जा रही है, तो दूसरी ओर अनुमंडल क्षेत्र के गांवों में शौचालय निमार्ण को स्वच्छता के प्रतीक चिन्ह से जोड़कर देखा जा रहा है.■

feedback@chauthiduniya.com

अब भी रेडियो की राह देख रहे हैं महादलित

राजेश सिन्हा

नीतीश सरकार के पहले कार्यकाल में ही सभी महादलित परिवारों को एक-एक रेडियो देने का एलान किया गया था. समाज के सबसे अंतिम पायदान पर खड़े महादलितों के बीच रेडियो का वितरण हो पाया अथवा नहीं, यह अब भी सवालों के घेरे में है. कुछ महादलित परिवारों के बीच रेडियो का वितरण हुआ भी तो रेडियो इतने दोयम दर्जे के थे कि समय से पहले ही जवाब दे गए. रेडियो की गुणवत्ता देखकर कई परिवार के लोगों ने महज कुछ दिनों बाद ही उन्हें औने-पौने दामों पर बेच देना मुनासिब समझा. समस्तीपुर जिले के गोरख सदा तथा खगड़िया जिले के सोनमनकी निवासी बालेश्वर चौधरी का कहना है कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने महादलितों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है. दो जून की रोटी के लिए दर-दर की ठोकरें खाने वाले महादलितों के ज्ञानवर्धन व मनोरंजन के लिए बिहार सरकार ने सरकारी स्तर पर रेडियो उपलब्ध कराने का एलान किया था. वर्षों बीत जाने के बाद कुछ महादलित बस्ती में रेडियो का वितरण भी किया गया, लेकिन उनका लाभ लिया जाता उससे पहले ही वे सरकारी रेडियो जवाब दे गए. ये रेडियो कुछ दिनों तक कुछ लोगों के मनोरंजन का साधन रहे, लेकिन अधिकांश रेडियो जल्द ही खराब हो गए. नतीजतन महादलितों ने अपने पास से बैट्री तक खरीदना मुनासिब नहीं समझा. कई बस्ती के महादलित तो अब तक एक अदद सरकारी रेडियो के लिए लालायित हैं. इस संदर्भ में जब-जब प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ बात करने की कोशिश की जाती है तो टका सा जबाव मिलता है कि किसको कब रेडियो मिलेगा, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है. एक ग्रामीण उमा देवी का कहना है कि ज्ञानवर्धन और मनोरंजन के लिए रेडियो खरीदने का शौक महादलितों को कभी नहीं था. अगर शौक था भी तो इनलोगों की माली हालत ऐसी नहीं है कि रेडियो खरीदने के लिए सोच भी सकें. लेकिन जब बिहार सरकार ने सभी महादलित परिवारों को अपनी तरफ से एक-एक रेडियो उपलब्ध कराने का वादा किया, तो महादलित परिवारों में उम्मीद की एक नई किरण जगी थी. लेकिन ज्यादातर महादलितों को अभी तक रेडियो देखने का मौका भी नहीं मिला है. अनगिनत महादलित हैं, जिनकी शिकायतें

रेडियो को लेकर है. जानकारों की बातों पर अगर भरोसा करें तो एससी-एसटी विभाग के द्वारा सभी रेडियो कम्पनियों से बकायदा इसके लिए कोटेशन (रेडियो की कीमत डिटेल) भी मांगे गए थे. संतोष, विप्रो और फिलिप्स कंपनियों के द्वारा उपलब्ध कराए गए कोटेशन से यह स्पष्ट हो गया था कि महादलितों के लिए रेडियो मिलने की राह आसान नहीं है. ऐसा इसलिए क्योंकि कोटेशन उपलब्ध कराने वाली तीनों कम्पनियों ने यह स्पष्ट कर दिया था कि लगभग पांच सौ से नीचे की कोई ऐसी रेडियो नहीं है, जिसे महादलितों को दिया जा सके. जबकि यह भी जगजाहिर है कि सरकार के द्वारा सभी महादलित परिवारों को रेडियो उपलब्ध कराने के बावत सभी जिलों में बकायदा एक रेडियो मेला लगाकर चार-चार सौ के कूपन उपलब्ध कराए गए थे. हालांकि यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि नकद राशि का भुगतान इसलिए नहीं किया जाएगा, ताकि इस राशि का अन्यत्र उपयोग नहीं किया जा सके. लगभग 22 लाख महादलित परिवारों को इसके लिए चिन्हित भी किया गया था. जानकारों की बातों पर अगर गौर किया जाय, तो इस तरह की योजना का आगाज किए जाने के समय ही यह समझना चाहिए था कि जिन महादलितों के घरों में दोनों शाम ठीक से चूल्हे नहीं जल पा रहे हैं, क्या वे लोग ज्ञानवर्धन और मनोरंजन के लिए रेडियो खरीदने हेतु 100 रुपये भी खर्च कर सकेंगे? इस संदर्भ में युवा शक्ति के प्रदेश संरक्षक नागेन्द्र सिंह त्यागी कहते हैं कि महादलितों को ठगने के लिए जनप्रतिनिधियों ने नए-नए खेल शुरू कर रखे हैं. खगड़िया नगर परिषद के सभापति सह जन अधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष मनोहर कुमार यादव कहते हैं कि महादलितों को आशियाना उपलब्ध कराने का संकल्प तो अभी तक अधर में ही है, नीतीश सरकार ने रेडियो को भी महादलितों के लिए सपना बना दिया. भाजपा के खगड़िया नगर अध्यक्ष सुनील कुमार चौधरी कहते हैं, नीतीश सरकार ने ऐसे तो सभी जाति के लोगों को ठगा गया है, लेकिन महादलितों के साथ घोर अन्याय किया गया है. इधर खगड़िया की जदयू विधायक पूनम देवी यादव, जदयू प्रवक्ता अरविन्द मोहन और बबलू मंडल विरोधियों के इन आरोपों को नकारते हैं. इनका कहना है कि नीतीश सरकार के द्वारा महादलितों ही नहीं, अन्य समाज के लिए भी चलायी गई योजना का लाभ जरूरतमंदो को मिला है.■

ईम्पोर्टेड केमिकल से तैयार, लैब टेस्टेड
पेन्ट डिस्टेम्पर
कोई भी हो
वॉल पुट्टी केवल ईटालियन वॉल पुट्टी
Laboratory Tested
Please Compare Lab Report
Laboratory Tested
Made from Imported Chemicals
ईटालियन
व्हाईट
वॉल पुट्टी
Slight Costly but Superior
लैब रिपोर्ट अवश्य चेक करें ।
लैब रिपोर्ट हमारे सभी डीलर्स के यहां उपलब्ध है
प्रखण्ड स्तर या अपने क्षेत्र हेतू सप्लायर / डीलरशिप के लिए सम्पर्क करें ।
Mob : 9431234022 / 9435040133 Mail ID : mcwaterproof@yahoo.com
सीमेन्ट की ताकत बढ़ाए, घर को मजबुत बनाऐ
सीमेन्ट
कोई भी हो परन्तु
वाटरप्रूफिंग केमिकल सिर्फ
मिस्टर केमिस्ट
सीमेन्ट कोई भी हो लेकिन वाटरप्रूफिंग केमिकल मिस्टर केमिस्ट ही हो, क्योंकि मिस्टर केमिस्ट वाटरप्रूफिंग केमिकल ईम्पोर्टेड केमिकल से बनाया गया है, प्रत्येक पैक पर नम्बर युक्त होलोग्राम से नकल से पूरी तरह सुरक्षित १, ५, १०, २० एवं २०० लीटर होलोग्रामिक पैक में अब आपके यहां भी उपलब्ध । मिस्टर केमिस्ट वाटरप्रूफिंग सीमेन्ट की ताकत बढ़ाए, घर को मजबुत बनाए ।
Mob : 9431234022 / 9435040133 Mail ID : mcwaterproof@yahoo.com

मुंगेर

मनरेगा में फर्जीवाड़े का खेल

कुमार कृष्णन

गरीबों को रोजगार की गारंटी देने वाले मनरेगा योजना में फर्जीवाड़ा का खेल जारी है. यदि हकीकत का जायजा लेना है तो मुंगेर आइये. यहां यह योजना घोटालों की भेंट चढ़ चुकी है. मनरेगा से जुड़े अभियंता, पदाधिकारी करोड़ों रुपये डकार गये. कहीं वृक्षारोपण के नाम पर तो कहीं नहर के नाम पर राशि का बंदरबांट किया गया. लूट का आलम यह है कि लाखों रुपये से विभिन्न क्षेत्रों में जो वृक्षारोपण किये गये, उनका कहीं कोई अता-पता नहीं है. एक तरफ जहां वृक्षारोपण की खानापूर्ति कागज पर ही कर के सरकारी राशि का बंदरबांट किया गया, तो वहीं दूसरी ओर इससे गरीब-मजदूरों की भी हकमारी हुई है. मनरेगा के तहत 100 दिनों के रोजगार की गारंटी है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि बिहार में मजदूरों को इस योजना के तहत 30 दिन का भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है.

महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में घपलेबाजी का आलम यह है कि यहां जिले का चार प्रखंड एक ही कनीय अभियंता के जिम्मे है. तारापुर में पदस्थापित कनीय अभियंता अनिल कुमार पिछले छह वर्षों से इसी प्रखंड में पदस्थापित हैं, जबकि ऊंची पहुंच व पैरवी के बल पर उन्होंने असरगंज, टेटियाबंबर व हवेली खड़गपुर प्रखंड का भी पदभार ग्रहण कर लिया. कनीय अभियंता की विभाग में तूती बोलती है. आलम यह है कि कई अधिकारी इनसे खुद परहेज करते हैं. इन्होंने अपनी पत्नी सहित कई रिश्तेदारों के नाम पर फर्म खोल रखा है और मनरेगा के सामग्री की आपूर्ति उसी फर्म के नाम पर की जाती रही है. यही कारण है कि रोक के बावजूद असरगंज प्रखंड के मामले में उन्होंने अपने रिश्तेदार के फर्म के नाम पर 40.82 लाख की राशि की अवैध निकासी करवा दी. जिला पदाधिकारी उदय कुमार सिंह ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए असरगंज के मनरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारी से 48 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण मांगा था. इस मामले में सामग्री मद में भुगतान पर रोक के बावजूद कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा लगभग 40.82 लाख रुपये का भुगतान मनरेगा से जुड़े कनीय अभियंता के संबंधी के फर्म को कर दिया गया. जिलाधिकारी ने अपने स्पष्टीकरण प्रतिवेदन में साफ तौर पर लिखा है कि सामग्री मद में भुगतान पर रोक के बावजूद असरगंज प्रखंड के कार्यक्रम पदाधिकारी ने 40.82 लाख रुपये का भुगतान किया. यह राशि कनीय अभियंता के संबंधी के खाते में डाला गया है. जिलाधिकारी के मुताबिक प्रथम दृष्टया यह मामला वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है. सूबे में प्रशासनिक कार्रवाई की अपनी अलग ही रफ्तार है. दूसरी ओर मनरेगा के प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी से लेकर कनीय अभियंता तक मामले को दफन करने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं. हालांकि जिलाधिकारी द्वारा मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी से जो स्पष्टीकरण मांगा गया था उस मामले में प्रशासनिक कार्रवाई अभी तक स्पष्ट नहीं हो पायी है.

मुंगेर के तारापुर अनुमंडल के असरगंज, तारापुर एवं खड़गपुर अनुमंडल के टेटियाबंबर में मनरेगा योजना के तहत करोड़ों रुपये का घोटाला किया गया है. वृक्षारोपण के नाम पर बिना वृक्ष लगाये ही राशि की अवैध निकासी कर ली गयी है. मापी पुस्तिका तैयार करने में भी घालमेल किया गया है. बदहाली का आलम यह है कि कई योजनाओं में बिना मापी पुस्तिका तैयार किये मास्टर रौल के ही मजदूरों के नाम पर राशि की निकासी की गयी है. पारामाउण्ट एकेडमी विद्यालय से खानपुर तक नाला सफाई एवं पक्की निर्माण कार्य के योजना कोड ओपी/169918 में दोषी कार्यक्रम पदाधिकारी से जिलाधिकारी ने स्पष्टीकरण मांगा है. कार्यक्रम पदाधिकारी ने वित्तीय वर्ष 2015-16 में ग्राम पंचायत धोबई, लौना, खैरा एवं बिहमा में बगैर वृक्ष लगाये, बिना चापाकल गाड़े और बिना तकनीकी पदाधिकारी द्वारा मापी पुस्तिका तैयार किये, एक स्वयं सेवी संस्था के नाम पर लाखों रुपये की फर्जी निकासी करा दी. वृक्ष पटवन के लिए 44 चापाकल की बोरिंग की जानी थी. लेकिन एक भी चापाकल नहीं लगा और इसके नाम पर फर्जी तरीके से निकासी कर ली गयी. मनरेगा के तहत शौचालय निर्माण कार्य में भी फर्जी तरीके से निजी फर्म के नाम पर राशि की निकासी कर ली गयी है. जिससे लाभुक अनभिज्ञ हैं. इस अनियमितता के साक्ष्य को छुपाने के लिए विगत माह संचिका एवं कम्प्युटर चोरी की प्राथमिकी भी स्थानीय थाना में मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा दर्ज करायी गयी थी. उस मामले के पर्यवेक्षण में पुलिस निरीक्षक ने चोरी की घटना को झूठा करार दिया है. साथ ही गलत प्राथमिकी दर्ज कराने के आरोप में सूचक के विरुद्ध उलटा केस करने की अनुशंसा की है. मामला सिर्फ तारापुर का ही नहीं है, जगह-जगह ऐसी अनियमितता हुई है. मनरेगा योजना के तहत असरगंज प्रखंड के अमैया, रहमतपुर एवं चौरगांव पंचायत में वृक्षारोपण में भारी अनियमितता बरती गयी है. आंकड़ों के मुताविक अमैया पंचायत में लगभग 4800, चौरगांव में 2400 एवं रहमतपुर में 2800 पौधा लगाया गया. लेकिन जमीन पर बीस प्रतिशत पौधे भी दिखाई नहीं दे रहे हैं. मनरेगा से जुड़े लोगों का कहना है कि अमैया पंचायत में बाढ़ के पानी में कुछ पौधे नष्ट हो गये. वृक्ष की सुरक्षा के लिए लगाये गये गैबियन भी कहीं नजर नहीं आ रहे. अमैया पंचायत के ग्रामीण विलास यादव, अर्जुन यादव, बिंदेश्वरी यादव आदि का कहना है कि इस पंचायत में तो वृक्ष ही नहीं लगाये गये हैं. अधिकारी व बाबू लोग मिल कर सभी राशि डकार गये हैं. दूसरी ओर चौरगांव में कुछ स्थानों पर जीर्णशीर्ण अवस्था में गैबियन पड़ा हुआ है. पौधा पटवन के लिए लगाया गया चापाकल भी अब स्थल पर दिखाई नहीं दे रहा. बरियारपुर प्रखंड के हरिणमार व झौवा बहियार पंचायत में वृक्षारोपण के नाम पर करोड़ों की घपलेबाजी हुई है. वित्तीय वर्ष 2015-16 में इन दोनों पंचायतों में 605 यूनिट पौधा लगाने की स्वीकृति मिली थी. जिसमें प्रति यूनिट 2.11 लाख का प्राक्कलन तैयार किया गया था और 1.22 लाख मजदूरों को भुगतान होना था. हरिणमार पंचायत को 605 यूनिट पौधों के लिए 6.43 करोड़ तथा झौवा बहियार पंचायत को 6.33 करोड़ रुपया आवंटित किया गया. लेकिन इसमें भारी अनियमितता बरती गयी. यहां तक कि वृक्ष की खरीद से लेकर वृक्षारोपण, उसकी घेराबंदी और चापाकल लगाने में राशि का बंदरबांट किया गया. इन दो पंचायतों में ही अधिकारी, अभियंता व मनरेगा से जुड़े पदाधिकारी करोड़ों रुपये डकार गये. अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निमुर्लन संघर्ष समिति के प्रदेश महासचिव विजय कुमार मंडल एवं जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार जयसवाल ने इस घोटाले की जानकारी प्रधानमंत्री, केंद्रीय ग्रामीण विकास

उदय कुमार सिंह (डीएम)

मंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव को दी है और मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है. इनलोगों का कहना है कि कनीय अभियंता को चार-चार प्रखंडों का प्रभारी बनाकर रखना और उनके रिश्तेदारों द्वारा चलाये जा रहे फर्म को राशि का आवंटन करना बड़े घोटाले को उजागर कर रहा है. मामला उजागर होने के बाद प्रशासनिक स्तर पर जो जांच की कार्रवाई प्रारंभ हुई, वह महज खानापूर्ति बनकर रह गयी है.

मनरेगा घोटाले के संबंध में नौ प्रखंडों की जांच के लिए 19 दिसंबर को जिला पदाधिकारी द्वारा जांच टीम गठित की गयी. टीम ने 21 दिसंबर को निर्धारित प्रखंडों व पंचायतों में मनरेगा योजना की जांच की. हालांकि निर्धारित पंचायतों में वे अधिकांश पंचायत शामिल नहीं हैं, जिनमें वृक्षारोपण के नाम पर लाखों-करोड़ों की अनियमितता हुई है. जांच टीम में शामिल एक वरीय पदाधिकारी ने कहा कि इस मामले में तो सब कुछ पूर्व से ही तय है जांच तो महज एक खानापूर्ति है. ■

feedback@chauthiduniya.com

मगध विश्वविद्यालय में पीएचडी घोटाला

सुनील सौरभ

शैक्षणिक अराजकता और फर्जी डिग्री के मामले में देश में चर्चित मगध विश्वविद्यालय में इन दिनों एक और घोटाले की चर्चा खूब हो रही है. पीएचडी घोटाला के आरोप में सामने आये इस मामले की जांच बिहार सरकार की निगरानी विभाग द्वारा की जा रही है. मगध विश्वविद्यालय से पीएचडी करने वाले तीन सौ विदेशी जांच के घेरे में आ गये हैं. निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने मगध विश्वविद्यालय से जांच के दायरे में आये इन पीएचडी धारकों से संबधित पूरी जानकारी मांगी है. निगरानी का पत्र मिलते ही मगध विश्वविद्यालय में हड़कंप मच गया है. मगध विश्वविद्यालय ने निगरानी विभाग द्वारा मांगे गये 15 बिंदुओं पर जवाब देने के लिए अपने कर्मचारियों की छुट्टी भी रद्ध कर दी है. जवाब 6 जनवरी 2017 तक मांगा गया है. निगरानी की टीम ने जब मगध विश्वविद्यालय में आकर जांच के घेरे में आये पीएचडी धारकों से संबधित कागजात तथा पूरे विवरण की जानकारी मांगी तो अधिकारियों के पसीने छूटने लगे. क्योंकि इस मामले में मगध विश्वविद्यालय के अधिकतर कर्मी जानते हैं कि यहां एक पीएचडी की उपाधि देने में लाखों का खेल होता रहा है. पिछले ढाई दशक में मगध विश्वविद्यालय से पीएचडी करने वाले विदेशियों की उपाधि जांच की जाये, तो हजारों मामले सामने आ सकते हैं. लेकिन निगरानी विभाग ने 2011 से 2015 तक डिग्री लेने वाले विदेशियों को ही जांच के घेरे में लिया है. सभी पीएचडी की उपाधि मगध विश्वविद्यालय के बौद्ध अध्ययन विभाग से दी गयी है. इसकी जांच कर रही निगरानी ब्यूरो की डीएसपी प्रतिभा सिन्हा और महाराजा कनिष्क कुमार सिंह पीएचडी उपाधि लेने वाले विदेशियों से

संबधित कागजात लेकर पटना लौट चुके है. मगध विश्वविद्यालय से 15 विभिन्न बिदुओं पर जवाब की मांग निगरानी की ओर से की गई है. निगरानी को यह जानकारी मिली थी कि मगध विश्वविद्यालय से सैकड़ों ऐसे विदेशी छात्रों को पीएचडी की उपाधि दी गयी है, जो योग्यता नही रखते है. ऐसे विदेशियों को भी पीएचडी की उपाधि दी गयी है, जो टूरिस्ट तथा बिजनेस वीजा पर भारत आये थे. इनमें अधिकतर ऐसे थे, जिन्होंने मगध विश्वविद्यालय परिसर में अध्ययन ही नही किया. आरोप तो यह भी है कि कभी भारत नहीं आने वाले विदेशियों को भी पीएचडी की उपाधि दे दी गई. मगध विश्वविद्यालय के बौद्ध अध्ययन विभाग में एडहॉक पर काम कर रहे कई शिक्षकों ने अपने अधीन विदेशियों को पीएचडी कराकर लाखों का खेल खेला है. यह मामला मगध विश्वविद्यालय के उच्च अधिकारियों तक पहुंचा तो जरूर होगा, लेकिन इसे किसी भी तरह से रफा दफा करा दिया गया होगा. हालांकि अब इस पीएचडी घोटाले की जांच बिहार सरकार के निगरानी विभाग ने अपने जिम्मे लिया है. निगरानी विभाग ने कहा है कि मगध विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री लेने वाले विदेशी छात्रों के नाम, पिता का नाम, स्थायी आवास, अस्थायी आवास, पासपोर्ट नम्बर, वीजा से संबधित कागजात, वीजा का नेचर, यानी टूरिस्ट वीजा है या बिजनेस वीजा आदि की जानकारी मांगी गयी है. सबसे महत्वपूर्ण बात है कि टूरिस्ट व बिजनेस वीजा वाले विदेशी किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय में नामांकन के लिए योग्य नहीं हैं. निगरानी की तरफ से पीएचडी सुपरवाईजर, सुपरवाईजर की योग्यता व पीएचडी डिग्री पाने वाले छात्रों की पूरी शैक्षणिक योग्यता की मांग की गई है. निगरानी टीम ने मगध विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग के कई बैंक एकाउंट का विस्तृत विवरण भी मांगा है, जिससे यह पता चल सके कि किस खाते में कितनी राशि जमा है और वह राशि किसी दूसरे खाते से ट्रांसफर तो नहीं हुई है. निगरानी की जांच के बाद मगध विश्वविद्यालय के कर्मियों में दहशत व्याप्त है, क्योंकि निगरानी सूत्रों के अनुसार मगध विश्वविद्यालय से जवाब मिलने पर यह तय होगा कि जवाब संतोष जनक है या नही. यदि इस मामले में गड़बड़ी पायी गयी, तो 6 जनवरी 2017 के बाद दोषी कर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जायेगी. वहीं दूसरी ओर मगध विश्वविद्यालय के बौद्ध अध्ययन विभाग के अध्यक्ष डा. सुशील कुमार सिंह का कहना है कि विदेशियों को दी गयी पीएचडी की उपाधि कही से भी गलत नहीं है. कुछ लोगों द्वारा इस संबंध में गलत अफवाह फैलाकर बिहार सरकार और मगध विश्वविद्यालय को परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है.■

नवजात को रोटावायरस से बचायें
नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं
ariskon Pharma Pvt.Ltd.
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.
डॉ. राजेश कुमार गुप्ता | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हुलासगंज जहानाबाद
मानपुर बाजार गया

गया से डॉ. राजेश कुमार गुप्ता जो बच्चों के पेडियाट्रिक्स डॉक्टर हैं इन दिनों ठंढ में बच्चों को संभाल कर रखने की बात करते हैं और बताते हैं बच्चों को गर्म कपड़े में लपेट कर रखें और सावधानी से रखें। जुराब गर्म कपड़े और गर्म तापमान वाले कमरे में रखें। इन दिनों बच्चों में कोल्ड वायरस या कोल्ड डायरिया ज्यादा दिखने को मिल रहा है कई बार तो बच्चों की इससे मौत भी हो जाती है। इसकी वजह रोटावायरस है। 2 – 3 साल तक के बच्चों में इससे परेशानी ज्यादा देखी गयी है। इससे बचाव के लिए जब बच्चों डीपीटी का सुई पड़ता है उसी वक्त जरूरत है इन्हें यह टीका दिलवाने की । डब्लू एचओ ने इस दिशा में पहल शुरू की है। रोटावायरस के भैक्सिन के लिए सरकार भी इस दिशा में अपने तरफ से प्रयास रही है लेकिन जरूरी है कि आप रोटावायरस का टिका अवश्य दिलवायें। इसके लक्षणों में या इसकी पहचान है कि बहुत ज्यादा अतिसार होना रोटावायरस के प्रमुख लक्षण हैं। जिससे जानलेवा निर्जलीकरण (पानी की कमी होना) हो जाता है इसके अतिरिक्त बुखार और उल्टी भी हो सकती । यदि तीन माह से कम आयु के बच्चे इसके शिकार हो जायें तो उनमें यह लक्षण सहजता से नहीं दिखाई देते हैं। यह संक्रमित व्यक्ति के दस्त से दूसरे व्यक्ति को असानी से हो जाता है। अक्सर बच्चों को यह बीमारी उनके मुंह में लेने वाली अंगुली क आदत से पकड़ती है। इसलिए सफाई का ख्याल रखना प्राथमिकता मानी जाती है। इसके मुख्यतः दो प्रकार के टिके रोट्रिक्स जिसकी दो खुराक दी जाती है तथा दूसरा रोटाटेक जिसकी तीन खुराक दी जाती है।▪ भारती

ACOBA CAP/SYP/INJ
Methylcobalmin, Lycopene, Multivitamin Multimineral, Ginseng & Antioxident
Carbo - XT
Ferrous Ascorbate with Folic Acid Tab.
AREX
Dextromethorphan, Guaiphenesine Ammonium chloride Cough Syp.
ASRFEN-P
Acedofenac+Paracetamol Serratiopeplidase Tab.
ECTALOPAM
Escilalopram oxalate & Clonazepam Tablets
SILIPLEX
Silymarin, Vitamin B-Complex & Lactic acid, Calcium, Bacillus Cap/Syp
NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma

यूपी में अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित–जाति में शामिल करने की सपाई पहल

चुनाव की डोर से लटकी जलेबी

एसआर दारापुरी

उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार ने 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव पारित कर इसे केंद्र सरकार को भेजने का निर्णय लिया है. सूची में निषाद, बिन्द, मल्लाह, केवट, कश्यप, भर, धीवर, बाथम, मछुआरा, प्रजापति, राजभर, कहार, कुम्हार, धीमर, मांझी, तुरहा तथा गौड़ आदि जातियां शामिल हैं. सरकार का यह कदम इन जातियों को कोई वास्तविक लाभ न पहुंचा कर केवल उनको भुलावा देकर वोट बटोरने की चाल है.

इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी वर्ष 2006 में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने 16 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची तथा तीन अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए शासनादेश जारी किया था. अंबेडकर महासभा तथा अन्य दलित संगठनों द्वारा दी गई चुनौती के बाद अदालत ने उसे रद्द कर दिया था. परन्तु सपा ने यह दुष्प्रचार किया था कि इसे मायावती ने 2007 में सत्ता में आने पर रद्द कर दिया था. वर्ष 2007 में सत्ता में आने पर दलितों की तथाकथित स्वयंभू मसीहा मायावाती ने भी इसी प्रकार से 16 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने की संस्तुति (2011 में) केंद्र सरकार को भेजी थी. इस पर केंद्र सरकार ने इसके औचित्य के बारे में सूचनाएं मांगीं. मायावती इसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सकीं, लिहाजा केंद्र सरकार ने उस प्रस्ताव को वापस भेज दिया था.

इससे स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी और बसपा इन पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जातियों में शामिल करने और अधिक आरक्षण दिलवाने का लालच देकर उनका वोट प्राप्त करने की राजनीति कर रही है, क्योंकि दोनों पार्टियां यह अच्छी तरह जानती हैं कि इन जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने का अधिकार उनके पास नहीं है और न ही उक्त जातियां अनुसूचित जातियों के मापदंड पर सही उतरती हैं. वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार किसी भी जाति को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने अथवा इस से निकालने का अधिकार केवल संसद को है. राज्य सरकार औचित्य सहित केवल अपनी संस्तुति केंद्र सरकार को भेज सकती है. इस

सम्बन्ध में केंद्र सरकार रजिस्ट्रार जनरल आफ इंडिया तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से परामर्श के बाद संसद के माध्यम से किसी जाति को सूचि में शामिल कर सकती है अथवा निकाल सकती है. संविधान की धारा 341 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करके संसद द्वारा कानून पास करवा कर इस सूचि में किसी जाति का प्रवेश अथवा निष्कासन कर सकत हैं. इसमें राज्य सरकार को कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं है. वास्तव में ये पार्टियां अपनी सिफारिश केंद्र सरकार को भेज कर सारा मामला कांग्रेस (तत्कालीन केंद्र सरकार) की झोली में डालकर यह प्रचार करती रही हैं कि राज्य ने तो उक्त जातियों को अनुसूचित जातियों की सूचि में शामिल करने की पहल कर दी, लेकिन केंद्र सरकार इसमें रुचि नहीं ले रही. यह सीधा–सीधा अति पिछड़ी जातियों को गुमराह करके वोट बटोरने की राजनीति है, जिसे अब उक्त जातियां भी अच्छी तरह से समझ रही हैं. यह भी उल्लेखनीय है कि अखिलेश यादव की सपा सरकार अथवा मायावती की बसपा सरकार द्वारा अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जातियों की सूचि में डालने की जो संस्तुति पहले की गई थी अथवा आगे की जाएगी वह मान्य नहीं होगी, क्योंकि ये जातियां अनुसूचित जातियों की अस्पृश्यता की आवश्यक शर्त पूरा नहीं करती हैं. यह सर्वविदित है कि अनुसूचित जातियां सवर्ण हिन्दुओं के लिए अछूत रही हैं, जबकि सम्बन्धित पिछड़ी जातियों के साथ ऐसा नहीं है. लिहाजा, उन्हें किसी भी हालत में अनुसूचित जाति की सूचि में शामिल किया जाना संभव नहीं है. यदि सपा सरकार इन पिछड़ी जातियों को वास्तव में आरक्षण का लाभ देना चाहती है, तो उसे इन जातियों की सूची को तीन हिस्सों में बांट कर उनके लिए 27 प्रतिशत के आरक्षण को उनकी आबादी के अनुपात में बांट देना चाहिए. वर्तमान में उन्हें पिछड़ों में यादव, कुर्मी और जाट जैसी समृद्ध जातियों के कारण आरक्षण लाभ नहीं मिल पा रहा है. देश के अन्य कई राज्यों बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि में यह व्यवस्था पहले से ही लागू है. मंडल आयोग की रिपोर्ट में भी इस प्रकार की संस्तुति की गई थी.

उत्तर प्रदेश में इस सम्बन्ध में 1975 में डॉ. छेदी लाल साथी की अध्यक्षता में सर्वाधिक पिछड़ा आयोग गठित किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट 1977 में उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दी थी. लेकिन उस पर आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई. साथी आयोग ने पिछड़े वर्ग की जातियों को तीन श्रेणियों में बांटने तथा उन्हें 29.5 प्रतिशत आरक्षण देने की संस्तुति की थी. साथी आयोग के मुताबिक तीन श्रेणियों में अ श्रेणी में उन जातियों को रखा गया था जो पूर्ण रूपेण भूमिहीन, गैर–दस्तकार, अकुशल श्रमिक, घरेलू सेवक हों और हर प्रकार से ऊंची जातियों पर निर्भर हों. उन्हें 17 प्रतिशत आरक्षण देने की संस्तुति की गई थी. ब श्रेणी में पिछड़े वर्ग की वे जातियां थीं, जो कृषक या दस्तकार हैं. इन्हें 10 प्रतिशत आरक्षण देने की संस्तुति की गई थी. स श्रेणी में मुस्लिम पिछड़े वर्ग की जातियां रखी गईं, जिन्हें 2.5 प्रतिशत आरक्षण देने की संस्तुति की गई थी. मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध है. अतः डॉ. छेदी लाल साथी आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप पिछड़ी जातियों को तीन हिस्सों में बांट कर उपलब्ध आरक्षण को उनकी आबादी के अनुपात में बांटना अधिक न्यायोचित होगा. इससे अति पिछड़ी जातियों को अपने हिस्से के अंतर्गत आरक्षण मिलना संभव हो सकेगा.

इन अति पिछड़ी जातियों को यह भी समझना होगा कि सपा सरकार इन अति पिछड़ी जातियों को इस सूचि से हटा कर अपनी समृद्ध जातियों यादव, कुर्मी और जाट के लिए आरक्षण बढ़ाना चाहती है और उन्हें अनुसूचित जातियों से लड़ाना चाहती है. अतः उन्हें सपा और बसपा की इस चाल को समझना चाहिए और उन के झांसे में न आ कर डॉ. छेदी लाल साथी आयोग की संस्तुतियों के अनुसार अपना आरक्षण अलग कराने की मांग उठानी चाहिए. इसी प्रकार कुछ जातियां जो वर्तमान में अनुसूचित जातियों की सूचि में हैं परन्तु उन्हें अनुसूचित जनजातियों की सूचि में होना चाहिए. ऐसी जातियों को सपा सरकार से मांग करनी चाहिए कि वह एक आयोग का गठन कर उनकी स्थिति का आकलन करे और केंद्र से इसके लिए सिफारिश करे. तभी इन जातियों को भी उचित न्याय मिल सकेगा, वरना वे इन पार्टियों के झूठे आश्वासनों पर इसी तरह ठगे जाते रहेंगे. ■

feedback@chauthiduniya.com

सांप्रदायिक पार्टियां देश की अस्मिता के लिए ख़तरा हैं: बुनी नईम हस्नी

[इस बार उत्तर–प्रदेश के विधानसभा चुनावों पर पूरे देश की नज़र है. ज़ाहिर सी बात है कि 18 प्रतिशत से अधिक मुस्लिम आबादी वाले राज्य में मुसलमानों की भूमिका बड़ी ही महत्वपूर्ण और निर्णायक होगी. इन्हीं बिन्दुओं को मद्देनज़र रखते हुए यूपी के मौजूदा हालात पर 'ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड' के महासचिव बुनी नईम हस्नी से चौथी दुनिया ने बातचीत की. प्रस्तुत हैं बातचीत के महत्वपूर्ण अंश...]

आपके संगठन का नाम उलेमा बोर्ड है, लेकिन मुहिम आप जनता में जाकर चला रहे हैं?

बोर्ड का प्रयास यह होता है कि तमाम विचारधाराओं के उलेमा, उलेमा–ए–देवबन्द, बरेलवी, सलफी सभी मसलकों के उलेमा संगठित होकर एक प्लेटफार्म पर आएं. उलेमा के संगठित होने से जनता को आसानी से संगठित किया जा सकता है. लिहाज़ा उलेमा बोर्ड शहरों और कस्बों के इमामों और दरगाहों के जिम्मेदारों को भी इस मुहिम से जोड़ता है.

मुसलमानों को संगठित करने का आपका क्या मक़सद है?

मेरा मक़सद हर क्षेत्र में मुसलमानों को संगठित करना है. विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में इनका संगठित होना बेहद जरूरी है. इस्लाम में शिक्षा पर बहुत जोर दिया गया है. लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि मुसलमान आज शिक्षा में सबसे पीछे हैं. मुसलमानों के शैक्षणिक पिछड़ेपन का अनुमान सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से लगाया जा सकता है. शैक्षणिक मज़बूती से दीन व दुनिया दोनों में वर्चस्व मिलता है. इसलिए हमारी कोशिश है कि मुसलमान शिक्षा के मैदान में आगे आएं.

आपका बोर्ड राजनीति में भी रूचि लेता है?

हमारा संगठन कोई राजनीतिक दल नहीं है. हमने न तो चुनाव आयोग में राजनीतिक दल की हैसियत से पंजीकरण कराया है और न ही हम वे फायदे लेते हैं, जो सियासी पार्टियों को मिलते हैं. हम तो चुनाव के मौके पर जनता में जाकर केवल उन्हें वोट के महत्व को बताते हैं और यह समझाते हैं कि पैसा लेकर वोट देना हराम है. वोट देना इस्लाम के दृष्टिकोण से एक शहादत (गवाही) है और शहादत देना हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है. हमारे इस अमल से वोट प्रतिशत में इज़ाफे की संभावनाएं बढ़ेंगी और एक पारदर्शी सरकार का गठन होगा.

उत्तर प्रदेश में आप अपनी राजनीतिक मुहिम का आगाज़ कहां से और कैसे करेंगे?

हमारी मुहिम का आगाज़ लखनऊ से होगा. मस्जिदों–मदरसों से लेकर मुहल्लों तक में व्यक्तिगत मेलजोल और नुक्कड़ सभाओं के द्वारा जागरूकता मुहिम चलाई जाएगी. मुहिम चलाने में नौजवानों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा. हमारे यहां एक यूथ विंग भी है, जिसकी जिम्मेदारी लखनऊ के खलीकुर्रहमान साहब के ऊपर है. वह हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं. उनकी निगरानी में युवाओं में जागरूकता लाने का अमल चलता है. चुनावों के लिए हम महिलाओं को भी जागरूक करने का काम करेंगे. हमारे बोर्ड की बहुत सी महिला सदस्या हैं. वे आम महिलाओं के बीच जाकर, इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगी. बोर्ड की ओर से इसकी जिम्मेदारी ऊरूफी सिद्दीक़ी साहिबा को दी गई है.

क्या आप किसी पार्टी विशेष को ध्यान में रखते हुए जनता को प्रेरित करेंगे?

सबसे पहली बात तो यह है कि वोट धर्म की बुनियाद पर न हो, बल्कि विकास के नाम पर हो. बोर्ड में किसी दल विशेष के लिए प्रेरणा पर अमल नहीं किया जाता है. हम उसे ही अच्छी पार्टी मानेंगे, जो मुसलमानों को अधिक से अधिक

हम तो चुनाव के मौके पर जनता में जाकर केवल उन्हें वोट के महत्व को बताते हैं और यह समझाते हैं कि पैसा लेकर वोट देना हराम है. वोट देना इस्लाम के दृष्टिकोण से एक शहादत (गवाही) है और शहादत देना हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है. हमारे इस अमल से वोट प्रतिशत में इज़ाफे की संभावनाएं बढ़ेंगी और एक पारदर्शी सरकार का गठन होगा.

प्रतिनिधित्व दे, मुसलमानों के लिए काम करे और उनकी शिक्षा व विकास पर ध्यान दे. वह पार्टी किसी मुसलमान की ही हो, ऐसा नहीं है. वह किसी भी जाति धर्म की कोई भी पार्टी हो सकती है. उलेमा बोर्ड केवल मुसलमान ही नहीं, बल्कि सभी अच्छी सोच रखने वाले लोगों से संगठित होकर अच्छे उम्मीदवारों को वोट करने की अपील करता है. उलेमा बोर्ड किसी दल विशेष का प्रतिनिधित्व नहीं करता है. हम इसपर भी ध्यान देंगे कि बड़ी पार्टियों जैसे बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने पिछली बार मुसलमानों से जो वादा किया था, उनपर कितना अमल हुआ. इन सभी बिन्दुओं पर विचार करने के बाद फैसला होगा कि अच्छी पार्टी कौन सी है. इसे लेकर मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि हम भाजपा जैसी सांप्रदायिक पार्टी का किसी भी हाल में समर्थन नहीं कर सकते, क्योंकि सांप्रदायिकता पर विश्वास रखने वाली इस प्रकार की पार्टी देश की अस्मिता के लिए खतरा है.

क्या आप किसी दल के पास अपनी मांगे लेकर गए थे?

अभी किसी पार्टी का घोषणा–पत्र सामने नहीं आया है. जब सभी पार्टियां अपने घोषणा–पत्र जारी कर देंगी, तो हम उनके पास जाएंगे और अपनी मांगे रखेंगे. इसके बाद देखा जाएगा कि कौन सी पार्टी हमारी मांगें मानती है और कितना मानती है. इसके बाद ही निर्णय होगा कि पार्टी को समर्थन करना चाहिए या नहीं. फिलहाल हमारी मुहिम, केवल जनता में जागरूकता लाने की होगी.

इस समय मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है?

मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा मसला उनकी सुरक्षा का है. यही कारण है कि हम उस पार्टी को बेहतर समझते हैं, जो मुसलमानों की सुरक्षा की गारंटी दे और 'दंगा निरोधक बिल' जैसे मुद्दों का समर्थन करे. मुसलमानों की दूसरी समस्या शिक्षा की है. शिक्षा में यह वर्ग बेहद पिछड़ा है. हम चाहेंगे कि पार्टियों के मसलों में मुसलमानों के शैक्षणिक संस्थानों, विशेष रूप से मदरसों को संरक्षण देने और उनमें पानी व बिजली की उपलब्धता की गारंटी की बात हो. वे हमारे लिए नए संस्थान, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोलने में अपना सहयोग दें. इसके अलावा मुसलमानों की वक्फ संपत्तियां सुरक्षित हों. वक्फ संपत्तियों को हर ओर से लूटा जा रहा है. सरकार इन संपत्तियों को सुरक्षा देने की गारंटी दे. ■

feedback@chauthiduniya.com

परिवर्तन यात्रा की समापन रैली में जुटी भारी भीड़ देख कर उत्साहित मोदी ने कहा

यूपी में विकास का वनवास खत्म होना चाहिए

सूफी यायावर

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भाजपा की परिवर्तन रैली में जुटी भीड़ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अचंभित थे. मोदी ने कहा भी कि ऐसा जनसैलाब उन्होंने कभी देखा नहीं था. मोदी ने कहा कि यह उनके जीवन की सबसे बड़ी रैली है. मोदी ने परिवर्तन यात्रा के आखिरी दौर में लखनऊ में हुई रैली में कोई चुनावी घोषणा या वादा तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने यूपी में भाजपा की सरकार बनाने के लिए जनता से आशीर्वाद जरूर मांगा. मोदी ने सपा बसपा और कांग्रेस तीनों पार्टियों को आड़े हाथों लिया और कहा कि तीनों पार्टियों के कारण उत्तर प्रदेश में विकास का मसला काफी पीछे चला गया. मोदी ने जनता के सामने हिसाब भी दिया कि केंद्र सरकार ने पिछले ढाई साल में यूपी को ढाई लाख करोड़ रुपये दिए, लेकिन प्रदेश सरकार ने इस धन का इस्तेमाल प्रदेश के विकास के लिए नहीं किया. उन्होंने कहा कि ऐसे में उत्तर प्रदेश में अब पिछले 14 साल के विकास का वनवास खत्म होना जरूरी है. मोदी ने खुद को उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधि बताया और कहा कि देश के विकास के लिए उत्तर प्रदेश काविकास आवश्यक है.

लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में दो जनवरी को आयोजित परिवर्तन महारैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारिवारिक कलह में उलझी हुई समाजवादी पार्टी पर तीखा प्रहार किया और कहा कि भाजपा उत्तर प्रदेश के लोगों को ऐसे लोगों से बचाने के लिए आई है. मोदी ने कहा कि क्या उन्हें ऐसी सरकार मंजूर है जो लोगों की जमीनें हड़पे, गुंडागर्दी करे, बेटियों की प्रतिष्ठा पर हाथ डाले, भ्रष्टाचार करे! मोदी ने कहा, हमें अवसर दीजिये, भाजपा सुख-चैन की जिंदगी देने वाली सरकार देने का वादा करती है.' लखनऊ के विकास में पूर्व प्रधानमंत्री और लखनऊ के सांसद अटल बिहारी वाजपेयी के योगदानों को रेखांकित करते हुए मोदी ने तीनों भाजपाई मुख्यमंत्रियों कल्याण सिंह, रामप्रकाश गुप्त और राजनाथ सिंह के कार्यकाल की सराहना की और रैली में जुटी भारी भीड़ देख कर यह उम्मीद जताई कि यह उत्तर प्रदेश में राजनीतिक बदलाव का संकेत हैं. केंद्र में भाजपा की सरकार बनाने में उत्तर प्रदेश की भूमिका की खास तौर पर मोदी ने प्रशंसा की और कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता के सहयोग से ही केंद्र में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी. मोदी बोले कि यूपी के लोग राजनीतिक दृष्टि और समझ रखने वाले लोग हैं.अब लोग जात-पांत से ऊपर उठ रहे हैं. अब लोग यूपी के विकास के लिए वोट करेंगे और यूपी को बदलने में भूमिका अदा करेंगे. प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपी में विकास तौल कर किया जाता है. यूपी सरकार को केंद्र से हर वर्ष एक लाख करोड़ रुपया ज्यादा खर्च करने के लिए मिला, लेकिन ढाई साल में मिले ढाई लाख करोड़ रुपये का सही उपयोग हुआ होता तो यूपी का विकास कहां से कहां होता.भीड़ से गदगद मोदी ने कहा कि पॉलिटिकल पंडित चुनाव का हिसाब-किताब लगाते हैं. यूपी का चुनाव किस दिशा में जाएगा उसका हिसाब करने वालों को अब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. हवा का रुख अब साफ है.मोदी ने कहा कि सरकार बदलने के छह महीने बाद लोग पुरानी सरकार को भूल जाते हैं, लेकिन मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि भाजपा की जो सरकारें चलीं आज 14 साल भी यूपी के लोग उसे याद करते हैं और वर्तमान सरकारों के साथ तुलना करते हैं.अब भाजपा का 14 साल का वनवास खत्म होने वाला है, अब यूपी में विकास का वनवास खत्म होने वालाहै.

मोदी ने सपा और बसपा पर कड़े प्रहार किए. नोटबंदी का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि राजनीतिक तौर पर ये दोनों दल एक दूसरे के धुर विरोधी दिखते हैं, लेकिन नोटबंदी के मसले पर दोनों एक हो गए हैं.मैं कहता हूं कि भ्रष्टचार और कालेधन को हटाओ तो ये कहते हैं मोदी को हटाओ.' रैली में जुटे लोगों सेमोदी ने अपने अंदाज में हामी भरवाई कि देश से कालाधन खत्म होना चाहिए और भ्रष्टचार रुकना चाहिए.मोदी ने कांग्रेस, बसपा और सपा पर तीखा प्रहार किया. उन्होंने दलों के नाम तो नहीं लिए लेकिन जिस तरह बात कही उससे लोगों तक सीधा संदेश गया. मोदी बोले कि एक दल ऐसा हैजो 15 साल से अपने बेटे को स्थापिक करने की कोशिश कर रहा है. एक दल अपना काला धन बचाने और बैंकों में जमा कराने की जुगाड़ में ही लगा हुआ है और एक दल पूरी ताकत से अपने परिवार का भविष्य बचाने में लगाहुआ है.इनमें से किसी भी दल को प्रदेश के विकास की कोई चिंता नहीं है. भजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने भी रैली को संबोधित किया. ■

feedback@chauthiduniya.com

मोदी की रैली से हताश हो रहे हरीश

राजकुमार शर्मा

मोदी की रैली में देवभूमि की जनता का दून परेडग्राउंड में उमड़ना उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत और उनकी कांग्रेस पार्टी के लिए हताशा का कारण बना हुआ है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब यह कहा कि यह देवभूमि और वीर माताओं की भूमि है, मैं सभी को नमन करता हूं तो तालियों की गड़गड़ाहट से परेड ग्राउंड गूंज उठा. चारधाम हाई-वे प्रोजेक्ट का शिलान्यास करते हुए मोदी ने कहा कि यह उत्तराखंड त्रासदी में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि है. मोदी ने उत्तराखंड के विकास के लिए दो इंजनों को जरूरी बताया, एक देहरादून और दूसरा दिल्ली. उन्होंने कहा कि इतनी भारी संख्या में लोगों का आना यह बताता है कि अब उत्तराखंड के लोग विकास के लिए इंतजार नहीं करना चाह रहे हैं. मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार ने देश को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया और अब इससे निपटने का वक्त आ गया है. मोदी ने जनता से सीधा संवाद भी स्थापित किया. उन्होंने यह भी कहा कि जब वे 2014 में आए थे तब यह मैदान आधा भी नहीं भरा था, तब लोगों ने लोकसभा की पांच की पांचों सीटें दी थीं. इस बार मैदान पूरा का पूरा भरा है तो विधानसभा में भी पूरी की पूरी सीटें मिलनी चाहिए. दूसरी तरफ उत्तराखण्ड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उत्तराखण्ड दौरे को निराशाजनक बताया. उन्होंने कहा कि रैली के लिए मुजफ्फरनगर, बिजनौर एवं पौंटा से सौ-सौ बसें तथा सहारनपुर से 200 बसों में भरकर भाजपाइयों ने भाड़े की भीड़ इकट्ठी की थी. ■

शिलान्यास के बाद से अटकी पड़ी है कुशीनगर की मैत्रेय परियोजना

मैत्रेय के रूप में कब आओगे बुद्ध!

शत्रुंजय सिंह रैकवार

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 13 दिसम्बर 2013 को जब कुशीनगर में मैत्रेय परियोजना का शिलान्यास किया था, तो ऐसा लगा था कि अब पूर्वांचल में विकास की गंगा बहेगी. जनपद कुशीनगर के निवासियों की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था. लेकिन इन तीन वर्षों में लोगों की उस खुशी की रंगत उतरने लगी. लोग अब यही कह रहे हैं कि सरकार चाहे जिसकी भी हो मैत्रेय परियोजना शायद अब कभी भी जमीन पर साकार नहीं हो पाएगी. यह मात्र एक छलावा ही साबित हुआ है. उक्त संदर्भ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव शरद कुमार सिंह का कहना है कि प्रदेश में चाहे भाजपा की सरकार रही हो या बसपा की या सपा की, इन सभी दलों की सरकारों ने लोगों को ठगने का काम किया है. मैत्रेय परियोजना की हकीकत यह है कि इसके नाम पर किसानों का आन्दोलन खड़ा कराया गया और नेता लोग सरकार से पैसे लेकर नेपथ्य में चले गए. भोली-भाली जनता हतप्रभ रह गई. जिस मैत्रेय परियोजना का शिलान्यास मुख्यमंत्री के हाथों हुआ था, उस शिलान्यास स्थल पर आज गंदगी का अम्बार लगा है. इससे प्रदेश के विकास की असलियत का अहसास होता है.

आज से लगभग 15 वर्ष पूर्व महत्वाकांक्षी मैत्रेय परियोजना का खाका खींचा गया था. बुद्ध के शांति, अहिंसा, करुणा और जगत कल्याण के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने और दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करने वाली परियोजना को जमीन पर उतारने की योजना तब और परवान चढ़ी जब बौद्ध गुरु दलाईलामा ने इसे भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में स्थापित करने की इच्छा जताई. उनकी इच्छा को दैवीय इच्छा मान कर परियोजना पर काम शुरू हुआ था. प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने 6 नवम्बर 2001 को दलाईलामा को इस बारे में पत्र लिखा था. फिर 6 फरवरी 2002 को दलाईलामा ने पत्र लिखकर परियोजना को उत्तर प्रदेश में शीघ्र स्थापित करने की गुजारिश की थी. इसके बाद बैठकों का दौर चला और 9 मई 2003 को ट्रस्ट और सरकार के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुए.

वर्ष 2001 में मैत्रेय परियोजना के प्रस्ताव के बाद ही किसान खुलकर इसके विरोध में उतर आए. विरोध सड़क से लेकर दफ्तरों तक चला. किसानों को मनाने और विरोध कम करने में ही पूरे 11 साल बीत गए. 2003 में हुए करार के बाद सरकार ने परियोजना के लिए जून, 2004 में सात गांवों की कुल 800 एकड़ जमीन अधिग्रहीत की. इसके बाद परियोजना के विरोध में पहले से फूटा स्वर और मुखर हो चला. तेज हुए विरोध ने इसके बाद कभी थमने का नाम ही नहीं लिया. गोवर्धन गोंड की अध्यक्षता में भूमि बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले सिसवां महंथ में आंदोलन का बिगुल बजा जो अनवरत जारी रहा. विरोध के बाद जून 2007 में किसानों ने आंदोलन स्थल पर ही क्रमिक अनशन शुरू कर दिया. इस बीच घेराव, सड़क जाम और प्रशासन से झड़पें भी हुईं. विरोध का असर यह रहा कि सन् 2012 तक परियोजना का काम शुरू नहीं हो पाया. 20 नवम्बर 2012 को जब अखबारों में यह खबर छपी कि विदा हुआ मैत्रेय प्रोजेक्ट, तो पूरे प्रदेश में हंगामा मच गया और परियोजना के विरोधी जश्न मनाने लगे. कुशीनगर के तत्कालीन जिलाधिकारी रिग्जियान सैम्फिल ने सक्रियता दिखाते हुए सरकार से पत्र व्यवहार शुरू किया और बात मुख्यमंत्री तक पहुंची. 23 नवम्बर को सरकार ने साफ कर दिया कि परियोजना और कहीं नहीं जाएगी, कुशीनगर में ही रहेगी. प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ब्रम्हाशंकर त्रिपाठी ने क्षेत्र के विकास से जुड़ी इस परियोजना को कुशीनगर में उतारने की वकालत की, तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुख्य सचिव को तलब कर परियोजना के प्रतिनिधियों से वार्ता करने का निर्देश दिया. उच्च स्तरीय बैठक में संस्था को भरोसा दिलाने के बाद अध्यात्मिक गुरु रिन्पोछे ने एक बार पुनः परियोजना को शीघ्र जमीन पर उतारने की पहल की. 13 दिसम्बर 2013 को मैत्रेय परियोजना का शिलान्यास हुआ. लेकिन उसके बाद परियोजना पर काम आगे नहीं बढ़ा. मुलायम बार-बार यह कहते रहे कि शिलान्यास के साथ-साथ उद्घाटन की तारीख भी बताई जाए. लेकिन पिता की बात सुनता ही कौन था.

परियोजना की राह का सबसे बड़ा रोड़ा किसानों का विरोध था. यह विरोध वर्ष 2001 में ही खड़ा हो गया था. इस विरोध के साये से मैत्रेय परियोजना कभी उबर नहीं पाई. वर्ष 2004 में परियोजना के विरोध में आंदोलन स्थल सिसवां महंथ में क्रमिक अनशन शुरू हुआ, तो इसको विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी हवा दी. स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी किसानों के विरोध को समर्थन दिया. जमीन का क्षेत्रफल कम करने के बाद भी बात नही बनी. प्रशासन ने बीच का रास्ता निकाला तो यहां भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सूर्यप्रताप शाही के जमीन का पेंच फंस गया. परियोजना के बीच में पड़ने वाली 10 एकड़ जमीन के कारण अड़ंगा लग गया. इससे परियोजना को बड़ा झटका लगा. अभी यह सब चल ही रहा था कि परियोजना विरोधी किसानों का समूह हाईकोर्ट की शरण में चला गया. हाईकोर्ट ने किसानों की जमीन लेने पर रोक लगाते हुए सरकार से ही जवाब-तलब कर दिया. इसके बाद तो मुआवजा वितरण और किसानों से करार का काम पूरी तरह से ठप्प हो गया. लगा कि अब परियोजना ठंडे बस्ते में चली जाएगी. तत्कालीन जिलाधिकारी रिग्जियान सैम्फिल की सकारात्मक पहल पर लखनऊ की उच्च स्तरीय बैठक में 202 एकड़ जमीन पर ही परियोजना को जमीन पर उतारना तय हुई. इस पर सरकार और परियोजना के प्रतिनिधि मान भी गए. परियोजना की स्थापना के रास्ते खुल गए, लेकिन लालफीताशाही और नेतागीरी ने काम आगे नहीं बढ़ने दिया. ■

13 वर्ष के 13 पड़ाव

1. मैत्रेय परियोजना के लिए वर्ष 2000 में यूपी में भूमि चयन के साथ-साथ प्रतिमा की डिजाइनिंग का काम शुरू हुआ.
2. 6 नवम्बर 2001 और 6 फरवरी 2002 को तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने दलाई लामा को पत्र लिखकर मैत्रेय प्रोजेक्ट को यूपी में स्थापित करने का अनुरोध किया.
3. कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मंदिर के पास सात गांवों की 750 एकड़ भूमि परियोजना के लिए चिन्हित हुई.
4. 9 मई 2003 को मैत्रेय प्रोजेक्ट ट्रस्ट और प्रदेश सरकार के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुए.
5. सरकार ने भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा कर लिया लेकिन किसानों के विरोध के कारण उस पर कब्जा नहीं ले सकी.
6. मई 2011 में प्रदेश सरकार ने मैत्रेय परियोजना को 273 एकड़ में सीमित करने का प्रस्ताव दिया जिस पर मैत्रेय प्रोजेक्ट ट्रस्ट राजी हो गया.
7. भूमि मिलने में देरी से हताश मैत्रेय प्रोजेक्ट के आध्यात्मिक निदेशक लामा जोपा रिनपोछे ने नवम्बर 2012 में परियोजना को कुशीनगर से हटा कर बोधगया में स्थापित करने की घोषणा की.
8. 22 नवम्बर 2012 को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि मैत्रेय प्रोजेक्ट को कुशीनगर से जाने नहीं दिया जाएगा. उन्होंने तत्कालीन मुख्य सचिव जावेद उस्मानी को प्रोजेक्ट की राह की अड़चनें दूर करने का निर्देश दिया.
9. 23 नवम्बर को लखनऊ में हुई उच्चस्तरीय बैठक में 945 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से किसानों से जमीन लेने का निर्णय हुआ.
10. 28 नवम्बर 2012 को किसानों से करार का काम शुरू हुआ. तीन महीने में 202 एकड़ भूमि मिली.
11. फरवरी से अगस्त तक परियोजना के काम में एक बार फिर सुस्ती आई. मैत्रेय प्रोजेक्ट ट्रस्ट ने एमओयू निरस्त करने की नोटिस दी तो बातचीत फिर शुरू हुई.
12. 18 अक्टूबर 2013 और फिर 3 दिसम्बर 2013 को लखनऊ में हुई बैठक के बाद मुख्यमंत्री के हाथों परियोजना के शिलान्यास का कार्यक्रम टल गया और एक बार फिर उहापोह की स्थिति बन गई.
13. 6 दिसम्बर 2013 की शाम मुख्यमंत्री कार्यालय व संस्कृति विभाग ने कुशीनगर जिला प्रशासन को बताया कि 13 दिसम्बर को ही शिलान्यास होगा. प्रशासन ने युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कीं, शिलान्यास भी हुआ, लेकिन काम आगे नहीं बढ़ा.

कहानी

पर्स

(जिस चीज़ का वजन कम हो तो उसकी गति अधिक होती है)

आप हंसेंगे कि आज भी और आज से दस पंद्रह साल पहले भी, भीड़ में मुझे कोई लड़की टक्कर मार जाये तो मेरे दिमाग में तुरंत पिछले दिनों की अख़बार में पढ़ी ख़बर की कटिंग दौड़ जाती है कि आजकल महिला पॉकेटमारों का गिरोह काफी सक्रिय है. पंद्रह साल पहले वाली बात मैंने अपने चरित्र के बारे में बताने के लिये कही.

विमल चन्द्र पाण्डेय

अपनी जानकारी में मैं दुनिया का सबसे चौकन्ना इंसान हूं. आप इस बात की तस्दीक मेरे मुहल्ले या ऑफिस के किसी भी आदमी से कर सकते हैं और मैं यह अच्छी तरह जानता हूं कि कौन सा आदमी मेरे चौकन्नेपन के बारे में बताने के लिये कौन सा उदाहरण देगा. यह भी मेरे चौकन्नेपन का एक नमूना है.

वैसे तो मैं आपको इस बात के दसियों उदाहरण दे कर साबित कर सकता हूं, घर परिवार के, दफ्तर के, सेहत के, जीवन के हर मोड़ पर आपको मेरे चौकन्नेपन का जलवा दिखायी देगा. घर परिवार की बातों पर आप भी ज़रूर अपनी या अपने किसी चहेते की बात उठा लाएंगे या ऑफिस की बात कहने पर कह सकते हैं कि यह चौकन्नापन नहीं चमचागिरी या कुछ और है. मैं एक ऐसे उदाहरण से अपनी बात को सही साबित करूंगा कि आप को फिर कुछ सूझेगा नहीं.

बयालीस साल की उम्र तक दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में नौकरी करते हुये, बाकायदा मुंबई की लोकल और दिल्ली में डीटीसी बसों की यात्रा करते हुये अगर किसी आदमी की जेब कभी न कटी हो तो आप क्या कहेंगे? खा गये न चक्कर? कभी नहीं मतलब कभी नहीं. नहीं मान्यवर, एक बार भी नहीं. अरे मेरी याद्दाश्त पर शक मत कीजिये, यह आज भी चौबीस की उम्र जैसी है.

बसों या लोकल ट्रेन में चढ़ते हुये मेरे दिमाग में न ऑफिस होता है न भीड़. मेरी हथेली तुरंत मेरी पिछली जेब पर जाती है और मैं अपना बटुआ निकाल कर जींस के आगे वाली जेब में रख लेता हूं. भीड़ भरी लोकल में खड़ा मैं सोचता रहता हूं कि आज फिर मेरा पर्स नहीं मारा जा सकता. मैं अपने से चार आदमियों के बाद खड़े एक लुक्खा दिखते नवयुवक की ओर देखता हूं तो मुझे लगता है कि यह पॉकेटमार है. जब मैं चढ़ा था तो इसने मेरी पिछली जेब पर हाथ फिराया होगा और पर्स न पाकर अब मुझे गुस्से से घूर रहा है. मैं उसकी ओर देख कर विजयी मुस्कान मुस्कराता हूं. मेरा पर्स मारना इतना आसान नहीं बच्चे वाला भाव मेरे चेहरे पर है और मुझे मुस्कराते देख अपनी इज़्ज़त रखने के लिये वह भी मुस्कराता है. वह अपनी भंगिमाओं से मुझे कहता हुआ दिख रहा है, अगली बार नहीं बचेगा तुम्हारा पर्स. मैं उसकी मुस्कराहट से डर जाता हूं और अनायास ही मेरी हथेली अपनी अगली जेब पर होती है. पर्स सही सलामत है. मेरा पर्स मारना बच्चों का खेल नहीं. आज तक एक बार भी मेरी जेब नहीं कटी.

मैं बाइक से कहीं जा रहा होता हूं, मसलन घर से ऑफिस या ऑफिस से किसी काम से स्टेशन तो कभी-कभार एकाध लिफ्ट मांग रहे लोगों को अपनी बाइक की पिछली सीट पर बिठा लेता हूं. मुझे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है. लेकिन उसके बैठते ही मुझे याद आता है कि शिट, मेरा पर्स तो पिछली ही जेब में है और अब मैं बाइक रोक कर पर्स निकाल कर अगली जेब में रखूं, यह अच्छा नहीं लगेगा. जब यह बैठा था तो मैं खड़े होने के बाद टेढ़ा होकर फिर बैठा था, उस एक पल के लिये मेरा ध्यान अपनी जेब से हटा था, अगर इसे मारना होगा तो इसने मेरा पर्स मार दिया होगा, होगा क्या, मार ही दिया लगता है. मैं अपने पर्स को महसूस करने के लिये बाइक की सीट पर पीछे की तरफ दाहिनी ओर झुकता हूं. अपना दाहिना नितम्ब सीट पर दबा कर महसूस करता हूं तो लगता है कि पर्स पीछे वाले जेब में सलामत है. लेकिन यह बात मैं सौ प्रतिशत निश्चित होकर नहीं कह सकता. हालांकि अस्सी प्रतिशत संभावना है कि पर्स जेब में ही है लेकिन बीस प्रतिशत इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि उसने बैठते ही पर्स मार लिया हो. शक्ल से स्कूली छात्र लगता है, मुझे अंकल कहा है लेकिन आजकल स्कूली छात्र ही तो सबसे ज़्यादा इन सब कामों में लगे रहते हैं. फैशन और नशे ने युवा पीढ़ी को बरबाद कर रखा है. मैं बहुत कम पीता हूं और अपने जीवन के बयालिस सालों में सिर्फ दो मौके ऐसे रहे हैं जब मैं पीकर होश खो बैठा हूं. वह भी कॉलेज टाइम की बात है, उस समय मेरे जीवन में कोई अनुशासन नहीं था. अब दो तीन पेग के बाद कोई दोस्ती की कसम देता देता मर जाये, मैं टस से मस नहीं हो सकता. मेरे विल पॉवर की कसमें खायी जाती हैं भाई साहब.

अंकल यहीं रोक दीजिये. थैंक्यू अंकल. कह कर लड़का जाने के लिये पलटा है. इधर लड़का पलटा है और उधर मेरी हथेली मेरी पिछली जेब तक पहुंची है. शिट! पर्स सही सलामत मौजूद है. मुझे ख़ुद पर इस वक्त लोकल ट्रेन जैसी खुशी नहीं बल्कि शर्म सी महसूस हुयी है. एक अच्छा काम किया, अब उसका भी पुण्य मुझे नहीं मिलने वाला. एक बार शक कर मैंने अच्छे काम पर पानी फेर दिया हैं.

मेरी बगल से कोई भिखारी गुज़र जाये या फिर कोई सेल्समैन रास्ते में मुझसे टाइम पूछ कर आगे निकल जाये, छूटते ही मेरा हाथ जेब पर होता है. अगर आपको तुरंत पता चल जाये तो पॉकेट मारने वाले को आप दौड़ा कर पकड़ सकते हैं. आप हंसेंगे कि आज भी और आज से दस पंद्रह साल पहले भी, भीड़ में मुझे कोई लड़की टक्कर मार जाये तो मेरे दिमाग में तुरंत पिछले दिनों की अख़बार में पढ़ी ख़बर की कटिंग दौड़ जाती है कि आजकल महिला पॉकेटमारों का गिरोह काफी सक्रिय है. पंद्रह साल पहले वाली बात मैंने अपने चरित्र के बारे में बताने के लिये कही. उस उम्र में जब लड़के को लड़की के अलावा कोई और बात नहीं सूझती, मैंने कई लड़कियों से टकराने के बावजूद आज तक अपना पर्स नहीं खोया। मेरा ध्यान हमेशा पर्स पर रहता था. आपको विश्वास नहीं होगा कि मेरी पत्नी भी मेरी इस बात पर मेरा लोहा मानती है कि मेरी जेब में कितने रुपये पड़े हैं, चवन्नी की हद तक मुझे याद रहता है. अरे पचीस रुपये की ली थी मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती, पच्चीस रुपये की दही, तीन रुपये का पान खाया था और पांच रुपये का अदरक धनिया खरीदा था, कुल हो गये अठावन रुपये तो जेब में बचे चार सौ बयालिस रुपये। अब श्रीमती जी अपना हुनर दिखाएंगीं तो मैं अगले दिन उनसे पूरे आत्मविश्वास से कहूंगा, आपने मेरी जेब से एक सौ बयालिस रुपये निकाल लिये हैं वो वापस करिये. उनके चेहरा देखने लायक होगा. इससे बचने के लिये शुरुआती ऐसे कुछ मौकों के बाद उन्होंने मेरे पर्स में हाथ डालना बंद कर दिया.

मेरी इस ख़ूबी का सभी लोग लोहा मानते हैं लेकिन एक मेरे बचपन का दोस्त रासबिहारी है जो इसके लिये मुझे कोसता है. मैं इसके पीछे का कारण समझता हूं. वह बहुत गरीब परिवार से है. बेचारे के पिताजी एक सरकारी ऑफिस में चपरासी थे और कई भाई बहन होने के कारण इसकी मां और बहनों को पहले लिफाफे बनाने पड़ते थे. अब अपनी मेहनत से रासबिहारी ने बैंक में अच्छी नौकरी पायी है. उसने बहुत गरीबी देखी है और वह जीवन का आनंद लेना चाहता है. मैंने तो जीवन के बहुत आनंद लिये हैं. पत्नी को लेकर शादी के बाद घूमने कश्मीर भी गया था.

रासबिहारी मुझे कंजूस कहता है लेकिन दरअसल बात यह है कि मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रही इसलिये मुझे किसी चीज़ की हाह ने नहीं पीट रखा है. मेरे पिता ने मुझे दसवीं और बारहवीं में नेपाल और भूटान घुमाया था, मैं कश्मीर घूम चुका हूं, अब कितनी जगहें देखेगा आदमी, हर जगह तो वही पहाड़ और नदियां होती हैं. कश्मीर इतनी खूबसूरत जगह है कि यहां घूमने के बाद आदमी इससे खूबसूरत जगह और कहां घूमेगा. श्रीमती जी मेरे इस तर्क पर नाराज़ हो जाती हैं और मुझे कंजूस कहने लगती हैं. वह रासबिहारी का उदाहरण देने लगती हैं जो साल भर इसलिये पैसे जुटाता है कि साल में वह अपने परिवार को एक बार कहीं घुमाने ले जा सके. अभी वह केरल घूम कर लौटा है और मेरी श्रीमती जी हैं कि उनके बेटे के कंप्यूटर पर नारियल के पेड़ों और समुद्र की तस्वीरें जब से देख कर आयी हैं, केरल जाने की ज़िद लिये बैठी हैं. मैंने कुल खर्चा जोड़ा है, इतने में हम साल भर आराम से बिजली का बिल भर सकते हैं. इन औरतों को भी न भाई साहब सब कुछ देखा देखी करना होता है. मैं अपनी पत्नी को खुश करना जानता हूं. मैं उसे अपनी लक्ष्मी कहता हूं. जब से वह मेरी ज़िंदगी में आयी है, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ता गया है. मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि पता नहीं कब कहां कोई बाहरवाला इस बात को सुन रहा हो. भले ही यह कहानी है और इसके लेखक ने मेरा किरदार तैयार किया है लेकिन सच कहूं भाई साहब मुझे सचमुच इतना डर लगता है कि मैं कहानी में भी नहीं बता सकता कि मेरे कितने बैंक खातों में कितनी रकम है, नहीं फुसफसा कर भी नहीं. मैं इसे सोचने से भी डरता हूं कि कहीं किसी के पास यह बात टेलीपैथी के ज़रिये न पहुंच जाय.

(शेष अगले अंक में)

(लेखक युवा कथाकार और ज्ञानपीठ की ओर से विद्द जाने वाले नवलेखन अवार्ड से सम्मानित हैं)

feedback@chauthiduniya.com

करमर्द (करौंदा)

परिचय

करमर्द की हमेशा हरी-भरी रहने वाली झाड़ी होती है. इसके कटंक अत्यन्त तीक्ष्ण तथा मजबूत होते हैं. आयुर्वेदीय संहिताओं में दो तरह के करौंदों का वर्णन प्राप्त होता है 1 करौंदा 2 करौंदी. करौंदे के फल पकने के पश्चात् काले पड़ जाते हैं. इसलिए इसको कृष्णपाक फल कहते हैं. यह प्रायः भारत के गुजरात, पंजाब, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश व अन्य प्रान्तों में प्राप्त होता है तथा इसकी खेती की जाती है.

औषधीय प्रयोग मात्रा एवं विधि

- **मसूड़ों के रोग-** करौंदे के फल की चटनी बनाकर खाने से मसूड़ों के रोग मिटते हैं.
- **शीतादरोग-** करौंदे के 1-2 फलों का नियमित सेवन करने से शीतादरोग का शमन होता है.
- **शुष्क कास-** 5 मिली करौंदा पत्रस्वरस में शहद मिलाकर चटाने से शुष्क कास में लाभ होता है.
- **अतिसार-** करौंदे के अपक्व शुष्क फल चूर्ण 1-2 ग्राम तथा मूल चूर्ण को मिलाकर सेवन करने से अतिसार उदरशेग एवं उदर कृमियों का शमन होता है.
- **आमाशय विकृति-** 1-2 ग्राम करौंदा मूल चूर्ण का सेवन करने से आमाशय विकृति में लाभ होता है.
- **तृष्णा-** अपक्व फल के 1-2 ग्राम चूर्ण का सेवन करने से पित्त एवं कफ विकृति, अतिपिपासा, अजीर्ण तथा अरुचि में लाभ होता है.
- **अरुचि-** करौंदे के पके हुए फलों को खाने से अरुचि तथा पित्त-विकारों में लाभ होता है.
- **उदरशूल-** 1-2 ग्राम करौंदे के पुष्प चूर्ण का सेवन करने से उदरशूल का शमन होता है.
- **कृमि-** करौंदे की जड़ को पीसकर उसका चूर्ण बनाकर 1 ग्राम चूर्ण में शहद मिलाकर सेवन करने से उदरशूल में लाभ होता है.
- **पामा-** करौंदा मूल को पीसकर लेप करने से पामा तथा खुजली में लाभ होता है.
- **त्वग्-विकार-** करौंदे के पक्व फल को पीसकर लगाने से त्वग्-विकार, पामा, कण्डू तथा दाह में लाभ होता है.
- **खाज/खुजली-** करौंदे की मूल को अश्व मूत्र, नींबू रस तथा कपूर के साथ पीसकर लगाने से खुजली का शमन होता है.
- करौंदे की मूल को पानी में पीसकर, तेल में पका लें, तेल को छानकर ठंडा करके लगाने से खुजली मिटती है.
- **व्रण-** करौंदे की मूल को पीसकर व्रण पर लगाने से व्रण जल्दी भर जाता है.
- **अविरामी-ज्वर-** करौंदे के पत्रों का क्वाथ बनाकर, 10-20 मिली मात्रा में सेवन करने से अविरामी-ज्वर नियमित रहने वाला ज्वर में लाभ होता है.
- **पैरों का फटना-** करौंदे के बीजों को पीसकर पैरों पर लगाने से बिवाई पैरों का फटना में लाभ होता है.
- **ज्वर-** करौंदे के पत्तों का क्वाथ बनाकर, 15-30 मिली तक पिलाने से ज्वर तथा ज्वरजन्य दाह का शमन होता है.
- **मानस रोग-** करौंदे के फलों का सेवन करने से मानस रोगों में लाभ होता है.
- **मिर्गी रोग-** 5 ग्राम करौंदों के पत्तों को पीसकर दही के साथ मिलाकर खिलाने से मिर्गी में लाभ होता है. ■

प्रयोज्यांग : पत्र, मूल तथा फल.
मात्रा : पत्र क्वाथ 20-40 मिली.

आचार्य बालकृष्ण

साईं वंदना

साईं-जीवन

बाबा स्वयं में सर्वशक्तिमान हैं

पिछले अंक से आगे

डॉ. चन्द्रभानु सतपथी

यह एक अत्यन्त रोचक तथ्य है कि आज के इस घोर व्यक्तिवादी आणविक युग में भी बाबा के भक्तों की संख्या कई गुना अधिक बढ़ी है और उनके ऐसे अनेक आध्यात्मिक अनुभव लगातार हजारों-लाखों लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, जबकि आज लोग और भी अधिक शिक्षित एवं प्रबुद्ध/जागरूक हुए हैं तथा उनकी बुद्धि, तार्किकता एवं तटस्थता से संचालित है. आज मनुष्य द्वारा निर्मित जाति, धर्म, समाज एवं अर्थ पर आधारित आपसी भेदभाव को भूलकर भक्त लोग बाबा की समाधि तक पहुंचने के लिए ठीक वैसे ही कतार लगाए हुए हैं, जैसे कि बाबा ने कभी अपनी किसी आध्यात्मिक भावावेश की स्थिति में कहा था. आज के युवकों में पश्चिमी सभ्यता के प्रति लगाव रहते हुए भी बाबा का सन्देश वैसा ही प्रासंगिक और प्रभावशाली है, जो लोगों को उनकी ओर आकर्षित करता है. यही कारण है कि पूरे विश्व भर में बाबा के अनेक मन्दिर निर्मित होते जा रहे हैं और भक्तों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है. बाबा ने केवल मानव-मात्र ही नहीं बल्कि उससे भी परे सभी प्राणियों को शरण दी. श्री साईं सच्चरित्र में बाबा द्वारा विभिन्न प्राणियों (जैसे कि कुत्ता, सांप, शेर और यहां तक कि चिड़ियों) के प्रति करुणा प्रकट करने के अनेक उदाहरण मिलते हैं.

आज औसतन लगभग 35 हजार लोग प्रतिदिन शिरडी आते हैं और समाह के अन्त में यह संख्या एक लाख तक पहुंच जाती है. श्री साईं के प्रति लोगों की आस्था में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जो कि उनके मन्दिरों के निर्माण, पत्रिकाओं, अनुसंधान, साहित्य रचनाओं और भक्ति-संगीत आदि के रूप में देखी जा सकती है. बाबा के प्रति समर्पित ऐसे भक्तों की संख्या बढ़ रही है जो कि शिरडी साईं बाबा का नाम और सन्देश दूर-दूर तक प्रसारित कर रहे हैं. आज यह दिव्य साईं-आन्दोलन केवल महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं है, जैसे कि बाबा के समय में था अपितु उनके देह-त्याग के उपरान्त दशाब्दियों के भीतर ही वह राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर समस्त विश्वव्यापी आन्दोलन बन गया. साईं-भक्ति की यह सहस्रधारा भक्त के जीवन के धार्मिक पहलू को ही नहीं प्रभावित करती है, अपितु भक्तों के जीवन के हर पहलू (जैसे परिवार, संस्कृति, सामाजिक व्यवहार आदि) को भी प्रभावित करती है. भक्तों के लिए बाबा उनके जीवन का एक हिस्सा ही नहीं है, बल्कि उनके जीवन के सभी पहलुओं के साथ उनका सम्पूर्ण जीवन है.

श्री साईं की चेतना आज पहले से कहीं ज्यादा सक्रिय एवं जीवंत है. इससे हमारे मन में स्वाभाविक रूप से एक मूल प्रश्न उठता है कि- साईं बाबा कौन है? कुछ लोग उन्हें सद्गुरु कहते हैं, कुछ फकीर कहते हैं, कुछ उन्हें योगीराज कहते हैं, कुछ उन्हें संत कहते हैं और अधिकांश भक्त यह मानते हैं कि श्री साईं बाबा स्वयं में सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं. उन्हें एक सगुण साकार अवतार माना जाता है. जिसका अर्थ है कि वे ईश्वर ही हैं, जो कि मानव-रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं. इतिहास ने यह दर्शाया है कि अवतारों द्वारा धर्म की स्थापना का जो महत् कार्य आरम्भ हुआ था, उसका उनके देह-त्याग के बाद अत्यंत विस्तार-लाभ हुआ. ईसाई, बौद्ध, जैन आदि धर्म का प्रसार इस प्रकार हुआ था. उसी प्रकार श्री साईं महाराज के दिखाये हुए पथ पर चलने वाले लोगों की संख्या आज निरंतर बढ़ती जा रही है, जिससे यह विश्वास स्थापित हो रहा है कि श्री साईं बाबा मात्र सद्गुरु ही नहीं, अपितु एक सगुण-साकार अवतार हैं. इससे बाबा द्वारा दिया गया यह वचन प्रमाणित होता है कि अपनी देह-त्याग के बाद भी वे अपनी समाधि में सदैव जीवित रहेंगे और भक्तों का कल्याण करते हुए उन्हें राह दिखाते रहेंगे. आज भी बाबा सूक्ष्म रूप में विद्यमान हैं, जो कि इस पृथ्वी पर मानव-रहित सभी प्राणियों में करुणा, प्रेम, सत्य एवं सहनशीलता का प्रसार और धर्म की पुरस्थापना कर उन्हें एक-सूत्र में बांध रहे हैं.

आज विश्व, प्रांतीयतावाद, जातिवाद, आर्थिक एवं सामाजिक विभाजन, धार्मिक मतांग्रह, कट्टरता और अनास्था के कारण टुकड़े-टुकड़े होकर बिखर रहा है. साईं-जीवन आज के समाज की समस्त बुराइयों को निर्मूल करने का एक अचूक मंत्र है. हम सभी इस साईं-युग का अभिनंदन करें और उसे हृदय में धारण करें एवं आने वाले सुखमय भविष्य का देखें. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

साईं भक्तों! आप भी चौथी दुनिया को साईं से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मालूम, साईं से आप कब और कैसे जुड़े. साईं की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साईं को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साईं भक्त. साईं बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है? साईं बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

भारतीय खेल प्राधिकरण
sports authority of india

बदलता दिख रहा है भारतीय खेलों का भविष्य

धंधा नहीं चलेगा

सैयद मोहम्मद अब्बास

भारतीय खेलों में राजनीतिक दखलअंदाजी इतनी है कि विदेशों में होने वाले खेलों या हाल ही में हुए रियो ओलम्पिक को लें तो खिलाड़ियों से अधिक खेल संघ के पदाधिकारी और उनके लग्गू-भग्गू विदेश जाने की होड़ में लगे रहते हैं. इससे भारतीय खेल का भारी नुकसान हो रहा है. रियो ओलम्पिक में भारतीय खेल अधिकारियों की मौज-मस्ती का भेद भी खुला जब 42 किलोमीटर की मैराथन दौड़ में भाग ले रही ओपी जैशा बेहोश पड़ी रही और उनका हाल पूछने के लिए देश का कोई प्रतिनिधि अधिकारी वहां मौजूद नहीं था.

भारतीय खेल संघों का गंदा खेल किसी से छुपा नहीं है. देश में जो संस्था भारतीय खेलों को बुलंदियों पर पंहुचाने का जिम्मा लेती हैं, वही इस खेल के साथ गद्दारी करने से भी नहीं चूकतीं. भारतीय ओलम्पिक संघ इसका जीता जागता उदाहरण है. ओलम्पिक जैसी प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बारे में अक्सर सवाल उठाये जाते हैं लेकिन देश में चलाने वाली खेल संस्थाएं इससे पल्ला झाड़ती हैं. सुविधाओं के अभाव में खिलाड़ी अपनी प्रतिभा के साथ न्याय नहीं कर पाते. पिछले काफी समय से भारतीय ओलम्पिक संघ को लेकर कई बार उठा-पटक हो चुकी है. इस बार नया मामला यह है कि भारतीय ओलम्पिक संघ ने कलमाड़ी और अभय चौटाला जैसे दागियों को फिर से अपने परिवार में शामिल करने का फैसला किया. इन दोनों के आने के बाद भारतीय खेल जगत में हड़कम्प मच गया. स्पष्ट है कि दोनों की वापसी भारतीय खेल को फिर से गर्त में ढकेलने का काम करेगी. इसे ध्यान में रखकर खेल मंत्रालय हरकत में आया और आनन फानन में इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन को निलम्बित कर दिया. हालांकि कलमाड़ी ने अभी अध्यक्ष पद लेने से किनारा करने की बात कही है, जबकि अभय चौटाला अभी इसपर कुछ बोलने से बच रहे हैं. दरअसल देश को चलाने वाली खेल संस्था खेल माफियाओं के चंगुल में है. खेल संस्थाओं पर राजनीति भी उतनी ही हावी है. देश में खेलों को बढ़ावा देने वाली हर खेल संस्था में नेताओं, कारोबारियों व नौकरशाओं का रोल अहम रहता है. भारतीय खेल इनके चंगुल से आजाद नहीं हो पा रहा है. इसी कारण से भारतीय खेल विश्व खेल

पटल पर असरदार प्रदर्शन करने में भी सक्षम नहीं हो पा रहा है. नेताओं, कारोबारियों और नौकरशाओं ने खेल के माध्यम से अपनी जेबों में अपार धन भरा लेकिन खिलाड़ियों को कुछ नहीं दिया. खिलाड़ी मैदान में पसीना बहाता है लेकिन खेल संघ उसकी प्रतिभा चमकाने के लिए कुछ नहीं करते. सुरेश कलमाड़ी और अभय चौटाला दो ऐसे नाम हैं जो भारतीय खेलों को दीमक की तरह चाट गए. दोनों महानुभावों ने भारतीय खेलों की साख का सत्यानाश कर दिया. सुरेश कलमाड़ी ने साल 1996 से लेकर 2011 तक भारतीय ओलम्पिक संघ की कमान अपने हाथ में रखी. इन्हीं सालों में भारतीय खेलों में भ्रष्टाचार चरम पर रहा. कलमाड़ी ने साल 2010 में कॉमनवेल्थ खेल का दिल्ली में आयोजन कराया लेकिन इस दौरान जमकर भ्रष्टाचार हुआ. कलमाड़ी को कुर्सी ही नहीं गंवानी पड़ी बल्कि जेल भी जाना पड़ा. घोटाले के आरोपों के तहत कलमाड़ी को 10 महीने जेल में बिताना पड़ा. इसके बाद अभय चौटाला ने भारतीय ओलम्पिक संघ की कमान संभाली. चौटाला ने दिसम्बर 2012 में

इस पद को सम्भाला था लेकिन उनके ऊपर भी तमाम आरोप लगे. चौटाला इस पद पर फरवरी 2014 तक काबिज रहे. दिल्ली से लेकर राज्यों तक खेल संस्थाओं का हाल यही है. प्रत्येक खेल में खिलाड़ियों का कम नेताओं और नौकरशाहों का बोलबाला है. फेडरेशन से खिलाड़ियों को कुछ भी मदद नहीं मिलती है. खेल संघों से जुड़े नेता अपनी जेब में माल जमा करने में लगे रहते हैं, जबकि भारतीय खिलाड़ियों की सफलता में फेडरेशन का हाथ न के बराबर होता है. पीवी सिंधु ने पदक जीता तो इसमें गोपीचंद का बहुत बड़ा योगदान था. दीपा जैसी प्रतिभावान जिम्नास्टिक खिलाड़ी को फेडरेशन से कोई मदद नहीं मिली. फेडरेशन केवल नेताओं की गोद में बैठने वाली संस्था बनकर रह गया है. भारत के खेल संघों पर काबिज लोगों ने खूब घोटाले किए. कलमाड़ी और चौटाला जैसे महानुभावों की कमी थोड़े ही है.

भारतीय खेलों में राजनीतिक दखलअंदाजी इतनी है कि विदेशों में होने वाले खेलों या हाल ही में हुए रियो ओलम्पिक को लें तो खिलाड़ियों से अधिक खेल संघ के पदाधिकारी और उनके लग्गू-भग्गू विदेश जाने की होड़ में लगे रहते हैं. इससे भारतीय खेल का भारी नुकसान हो रहा है. रियो ओलम्पिक में भारतीय खेल अधिकारियों की मौज-मस्ती का भेद भी खुला जब 42 किलोमीटर की मैराथन दौड़ में भाग ले रही ओपी जैशा बेहोश पड़ी रही और उनका हाल पूछने के लिए देश का कोई प्रतिनिधि अधिकारी वहां मौजूद नहीं था. इस पर सरकार ने कोई कार्रवाई भी नहीं की. सवाल है कि आखिर कब तक भारतीय खेल इन खेल माफियों के बीच फंसा रहेगा, कब तक मेडल के लाले पड़े रहेंगे, कब तक भारतीय खेल संघ ठोस योजना बनाने में फेल साबित होता रहेगा, कब तक खिलाड़ी सुविधाओं से वंचित होते रहेंगे और नेता नौकरशाह उनके नाम पर धन हड़पते रहेंगे? फिलहाल तो सरकार के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है. ■

सुप्रीम कोर्ट के झटके से चेत जाएं खेल संघ

विश्व क्रिकेट में अपना जोरदार दबाव रखने वाला भारतीय क्रिकेट बोर्ड इससे पहले कई मामलों में घिरा. इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के सहारे पैसों की खान बनाने वाला बोर्ड शुरू में अपनी ताकत के बल पर कई मामलों को दबाने में सफल रहा. साल 2013 शायद बीसीसीआई के लिए सबसे बुरा दौर था. यही वह साल था जो बीसीसीआई की बर्बादी का कारण बना.

भारत की सबसे बड़ी खेल संस्था भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई को सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है. बीसीसीआई न केवल भारत बल्कि विश्व क्रिकेट में अपने अलग रुतबे के लिए जाना जाता है. इतना ही नहीं उसकी हनक से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद तक दबाव में रहती है. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई पर कड़ा रुख अपनाते हुए बोर्ड के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर को पद से हटाने का फारमान जारी कर दिया है. बोर्ड के सचिव अजय शिर्के को भी चलता कर दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें मानने से जो भी इंकार करेगा उसे बीसीसीआई से जाना होगा. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड लगातार सुर्खियों में रहा है. लोढ़ा कमेटी से बचने के लिए अनुराग ठाकुर ने कई तरह के हथकंडे अपनाए लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से बोर्ड की बोलती बंद कर दी है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद क्रिकेट ही नहीं अन्य खेलों के पदाधिकारियों के माथे पर भी बल आ गया है. उन तमाम खेल संघों के लिए खतरे की घंटी बजी है, जो खेल के साथ खिलवाड़ करने में लगे रहते हैं. खेलों को साफ सुथरा बनाने की मुहिम को अब नया बल मिल गया है. दुनिया का सबसे अमीर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड लगातार लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों से किनारा कर रहा था. लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लेकर बोर्ड शुरू से ढुलमुल रवैया अपनाता रहा. कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी बोर्ड लगातार अपना बचाव करने में ही जुटा रहा.

बीसीसीआई के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर लगातार सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे थे और अजय शिर्के उनका साथ दे रहे थे. इन दोनों पर ही बीसीसीआई में सुधार को लेकर लोढ़ा पैनल की सिफारिशों को लागू कराने का जिम्मा था, लेकिन दोनों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई. सुप्रीम कोर्ट से मिल रही लगातार फटकार के बाद भी दोनों ने राज्य क्रिकेट संघों का हवाला देकर इसे लागू करने से कन्नी काटने की कोशिश की. लेकिन आखिरकार बोर्ड शीर्ष अदालत के हत्थे चढ़ ही गया.

विश्व क्रिकेट में अपना जोरदार दबाव रखने वाला भारतीय क्रिकेट बोर्ड इससे पहले कई मामलों में घिरा. इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के सहारे पैसों की खान बनाने वाला बोर्ड शुरू में अपनी ताकत के बल पर कई मामलों को दबाने में सफल रहा. साल 2013 शायद बीसीसीआई के लिए सबसे बुरा दौर था. यही वह साल था जो बीसीसीआई की बर्बादी का कारण बना. आईपीएल में फिक्सिंग का गंदा खेल इसी साल पूरी दुनिया के सामने आया और बोर्ड के पैरों तले जमीन खिसक गई. तब भेद खुला कि आईपीएल फिक्सिंग और अय्याशी का अड्डा बन गया है. आईपीएल के मैच खुलेआम फिक्स हो रहे थे. टीमों के कई मालिक और खिलाड़ियों का इसमें सबसे अहम रोल था. इसी आईपीएल विवाद में राजस्थान रॉयल्स के तीन नामी गिरामी खिलाड़ी मैच फिक्सिंग में दबोचे गए. तीनों खिलाड़ियों पर फिक्सिंग के नए स्वरूप यानी स्पॉट फिक्सिंग का आरोप लगा. जांचों के लम्बे दौर के बाद इसमें उस वक्त के बोर्ड अध्यक्ष एन श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मय्यपन का नाम सामने आया. इसके बाद पूरे क्रिकेट जगत में हड़कम्प मच गया. इस खेल में गुरुनाथ मय्यपन के आलावा कई और लोगों से कड़ी पूछताछ की गई. बोर्ड ने भी आनन फानन में कई बड़े फैसले लेने की बात की. इसी दौरान श्रीनिवासन को लेकर भी कई बातें सामने आईं. बोर्ड इस मामले को रफा-दफा करने में जुटा रहा लेकिन कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद बोर्ड की मुश्किलें बढ़ती ही चली गईं. सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मुकुल मुद्गल के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई. जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद बीसीसीआई के होश उड़ गए. कमेटी की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस लोढ़ा कमेटी बना डाली. इस कमेटी ने बीसीसीआई पर लगाम लगाने के लिए कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की. लोढा कमेटी की कई सिफारिशों पर बोर्ड ने पहले तो हामी भर दी लेकिन बाद में वह इसे मानने से कन्नी काटने लगा. आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को सीधे आदेश देकर अध्यक्ष और सचिव को हटाना पड़ा. बोर्ड के 88 साल के इतिहास में पहली बार किसी अध्यक्ष और सचिव को इस तरह से हटना पड़ा. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खेल संस्थाओं का ढांचागत बदलाव होना तय है. क्रिकेट में चल रही तानाशाही पर भी अब लगाम लगेगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

जब ओम पुरी और नंदिता पुरी के रिश्तों में आई थी दरार

ओम पुरी की पत्नी नंदिता पुरी पत्रकार और स्तंभकार हैं. उन्होंने ओमपुरी पर एक किताब लिखी है, *अनलाइकली हीरो : द स्टोरी ऑफ ओमपुरी*. किताब में ओमपुरी और नंदिता पुरी के प्रेम संबंधों का जिक्र है, जो बहुत ही व्यक्तिगत है. इस किताब को लेकर ओमपुरी ने अपनी नाराज़गी जाहिर की थी. उन्होंने कहा था कि उनकी पत्नी ने इस किताब की प्रसिद्धि के लिए इसके अंदर कुछ ऐसे वाकयों का जिक्र किया, जिनसे उन्हें काफी झटका लगा. उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था.

बायोग्राफी को लेकर इनहीं विवादों के बाद, दोनों के संबंधों में कड़वाहट आ गई. ओमपुरी पर घरेलू हिंसा के आरोप भी लगे. नंदिता पुरी से शादी के पहले ओमपुरी की शादी सीमा कपूर से हुई थी, जो अभिनेता अन्नू कपूर की बहन हैं,

प्रदीप कुमार
feedback@chauthiduniya.com

श्रद्धांजलि

ओम पुरी के निधन से पूरा बॉलीवुड सदमे में

देश के बेहतरीन अभिनेताओं में शुमार ओम पुरी का 6 जनवरी को निधन हो गया. वह 66 वर्ष के थे. मुंबई के वर्सोवा स्थित आवास पर शुक्रवार सुबह उन्हें दिल का दौरा पड़ा था. उनकी मौत की ख़बर सुन कर पूरा बॉलीवुड और उनके प्रशंसक सदमे में हैं.

बॉलीवुड के साथ-साथ उन्होंने हॉलीवुड में भी अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया था. 18 अक्टूबर 1950 को अंबाला के एक पंजाबी परिवार में जन्में ओम पुरी ने फिल्म एंड टेलिविजन इंस्टिट्यूट पुणे से पढ़ाई की थी. मराठी फिल्म *घासीराम कोतवाल (1976)* से उन्होंने अपना करियर शुरू किया था. 1980 में आई *आक्रोश* ओमपुरी की पहली हिट फिल्म थी. इस फिल्म ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया और वह अपने शानदार अभिनय के लिए बॉलीवुड में जाने जाने लगे. फिल्म आक्रोश के लिए उन्हें फिल्म फेयर के बेस्ट सपोर्टिंग अभिनेता के अवॉर्ड से भी नवाजा गया.

1993 में ओम पुरी ने नंदिता पुरी के साथ शादी की थी. लेकिन 2013 में उनका तलाक हो गया था. ईशान नाम का उनका एक बेटा भी है. फिल्म *अर्धसत्य* के लिए ओम पुरी को नेशनल अवॉर्ड मिला था. फिल्म में उनका किरदार सामाजिक और राजनैतिक बुराइयों का विरोध करता है. इसके अलावा फिल्म *आरोहण* के लिए भी ओम पुरी को नेशनल अवॉर्ड मिल चुका है.■

एक समय था जब ओम पुरी वड़ा पाव खाकर गुजारा करते थे

ओम पुरी को भले ही आज लोग एक सफल कलाकार के रूप में देखते हों लेकिन उन्होंने यह मुकाम कैसे हासिल किया, इसकी भी बड़ी दिलचस्प कहानी है. एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी जिंदगी के संघर्षों के बारे में पूरी दुनिया को बताया था.

विविध भारती पर *उजाले उनकी यादों के* कार्यक्रम में यूनुस ख़ान ने उनसे विशेष बातचीत की थी, तब पता चला कि ओम पुरी ने अपनी जिंदगी में कितने संघर्षों का सामना किया है.

ओम पुरी ने बताया था, 'मेरा जन्म भले ही अंबाला में हुआ था, लेकिन मेरी शिक्षा मामा के घर पटियाला में हुई. मैं बहुत छोटा था, तभी से मामा के पास पला और बड़ा हुआ. मेरी शिक्षा हिंदी और पंजाबी में हुई. मैं पढ़ाई में हमेशा अव्वल आता और क्लास का मॉनिटर भी बना रहा. 11 वीं कक्षा में आते-आते नाटकों में काम करने का शौक हो गया था.

पटियाला से मैं दिल्ली चला आया और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (एनएसडी) में एडमिशन ले लिया. लेकिन फीस भरने के पैसे नहीं थे. दिल्ली में रहने की समस्या आई तो मैं पंजाब हाऊस पहुंचा, इस उम्मीद से कि कहीं रहने का ठिकाना मिल जाएगा. लेकिन वहां पर एक बंगाली आदमी ने कहा कि तुम्हारा दिल्ली में रहने का इंतजाम नहीं हो सकता. मैं बहुत मायूस होकर वापस आ रहा था, तभी उन्होंने आवाज दी. मैं लौटा, उन्होंने कहा कि मैं दो कमरे के मकान में अकेला रहता हूं, लिहाजा तुम मेरे साथ कुछ दिनों तक रह सकते हो. संयोग था कि उनका घर एनएसडी के पास ही था.

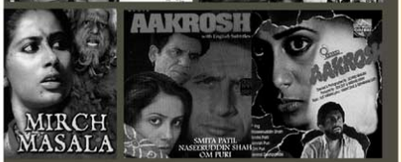

तब एनएसडी में मेरे साथ नसीरुद्दीन शाह भी पढ़ते थे. उनसे मेरी गहरी दोस्ती हो गई. मैं बहुत मध्यमवर्गीय परिवार से था और मेरे पास फीस भरने के भी पैसे नहीं थे. मैंने एनएसडी वालों से कह दिया कि मैंने पंजाब सरकार से स्कॉलरशिप के लिए आवेदन दिया है, वहां से पैसे आते ही मैं फीस भर दूंगा. 3600 रुपए की स्कॉलरशिप आई और इस तरह मेरी फीस जमा हुई.

एनएसडी में हम स्टेज शो करते थे, जिसे काफी पसंद किया जाता था. एनएसडी से निकलने के बाद मैंने सोचा, क्या किया जाए? कुछ दोस्तों ने पुणे के फिल्म इंस्टिट्यूट में दाखिला लेने की सलाह दी. पुणे के फिल्म इंस्टिट्यूट में इंटरव्यू के लिए मेरे पास एक अच्छी सी शर्ट तक नहीं थी. तब मुझे नसीरुद्दीन शाह ने एक चेक वाली शर्ट गिफ्ट की और मैं पुणे पहुंच गया. वहां मेरा दाखिला भी हो गया. बाद में नसीर भी पुणे आ गए. उस वक्त सुरेश ओबेराय, राकेश बेदी, नसीरुद्दीन शाह आदि मेरे क्लासमेट थे.

इंटरव्यू में ओम पुरी ने आगे बताया कि 'मुझे पुणे में भी खाने की दिक्कत होती थी, क्योंकि मेरे पास पैसे तो होते नहीं थे. उस समय मेरे पास रेजगारी होती थी और मैं वड़ा पाव खाकर और चाय पीकर दिन गुजारता रहा. नसीर मुझसे पहले मुंबई पहुंच गए थे और 1976 में मैंने मुंबई का रुख किया.

जब मैंने मुंबई में अपना कदम रखा था, तब चिकने चेहरे वाले कलाकार ही फिल्मी दुनिया में छाए हुए थे. एक स्टेज शो के दौरान मुझे गोविंद निलहानी ने देखा था और उन्होंने मुझे और नसीर को एक डॉक्यूमेंट्री कम एड फिल्म में मौका दिया. नसीरुद्दीन शाह और मैं मजदूर बने थे, बदले में हमें 600 रुपए का मेहनताना मिला. जिस दिन पैसे मिले, मैंने और नसीर ने जिंदगी में पहली बार एक एयरकंडीशंड होटल में जाकर अच्छा खाना खाया, वरना हम दोनों एक सरदार जी के ढाबे पर ही सस्ता खाना खाया करते थे. जब मेरी फिल्म *अर्धसत्य* ने रुपहले परदे पर धूम मचाई, तब बॉलीवुड ने जाना कि मैं भी कलाकार हूं. जहां तक मेरी संवाद अदायगी की बात है, तो यह कला मुझे एनएसडी में सिखाई गई थी. तब मुझे लगता था कि हमें तो एक्टिंग करना है फिर संवाद अदायगी की क्लास क्यों, लेकिन अब लगता है कि इसका फायदा हमें आगे चलकर मिला. मैं खुशनसीब हूं कि मुझे हमेशा अच्छे लोगों का साथ मिला और मैं जिंदगी में आगे बढ़ता चला गया.'■

कैसा रहा फिल्मी सफर?

साधारण चेहरे के बावजूद ओम पुरी अपनी ख़ास एक्टिंग, आवाज़ और डायलॉग डिलिवरी के लिए जाने जाते हैं.

1980 में आई *भावनी भवई*, *आक्रोश*, 1981 में *सद्गति*, 1982 में *अर्धसत्य* और *डिस्को डांसर*, 1986 में आई *मिर्च मसाला* और 1992 की *धारावी* से ओम पुरी को शोहरत मिली.

सनी देओल के साथ *घायल* में पुलिस इंस्पेक्टर और 1996 में गुलजार की *माचिस* में उन्होंने सिख आतंकवादी का किरदार निभाया. *माचिस* में बोला गया उनका डायलॉग *आधों को 47 ने लील लिया और आधों को 84 ने* काफी मशहूर हुआ था. इसके अलावा उनकी प्रमुख फिल्में हैं- आक्रोश, गांधी, विजेता, जाने भी दो यारो, आरोहण, सत्याग्रह, मिर्च मसाला, नासूर, आघात, नरसिम्हा, चाची 420, आस्था, गुप्त, प्यार तो होना ही था, विनाशक, चाइना गेट, कुंवारा, हेरी फेरी, दुल्हन हम ले जाएंगे, घात, फ़र्ज, गदर-एक प्रेम कथा, मक़बूल, चुप चुपके, सिंग इज किंग, मुखबीर, लंदन ड्रीम, दबंग, अग्निपथ (2012), ओह माई गॉड, मालामाल वीकली, डर्टी पॉलिटिक्स, बजरंगी भाईजान, मिस तनकपुर हाजिर हो, हो गया दिमाग़ का दही, मिर्जिया, गांधीगिरी आदि. ■

ओम पुरी कई अवार्ड से नवाजे गए

वर्ष 1980 में फिल्म आक्रोश में शानदार अभिनय के लिए ओम पुरी को फिल्म फेयर के बेस्ट सह अभिनेता के अवॉर्ड से नवाजा गया.

1982 में फिल्म *आरोहण* के लिए उन्हें नेशनल अवॉर्ड मिल चुका है. इसके अगले ही साल 1983 में ओम पुरी को फिल्म *अर्धसत्य* के लिए भी नेशनल अवॉर्ड मिला.

इसके अलावा उन्हें फिल्म घायल (1990), माचिस (1996), गुप्त (1997), प्यार तो होना ही था (1998) के लिए फिल्म फेयर के बेस्ट अभिनेता के लिए नमांकित गया था.■

पीएम मोदी ने ओम पुरी के निधन पर जताया शोक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताते हुए ट्विटर पर एक पोस्ट साझा किया.

पीएम मोदी ने लिखा, ओम पुरी की निधन की ख़बर सुनकर काफी दुख हुआ. ओम पुरी को हमेशा ही उनके बॉलीवुड के लंबे सफर और थियेटर के लिए याद किया जाएगा.■

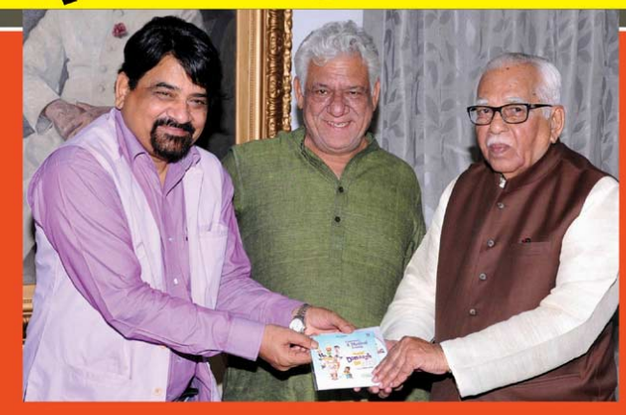

एक अच्छे अभिनेता, एक सच्चे इंसान का जाना...

एक ऐसा अभिनेता, जिसने रील लाइफ में समाज की बुराईयों और कटु सच्चाईयों को जिया, जिसने रियल लाइफ में भी समाज की विषमताओं, कटुताओं पर जम कर बोला, उसे कोई टीवी चैनल या सोशल मीडिया पर मौजूद उपद्रवी तत्व देशभक्ति का पाठ पढ़ाए, तो मान लेना चाहिए कि अर्धसत्य, सत्य पर भारी पड़ रहा है. शायद, ओमपुरी को भी इस बात का एहसास हुआ होगा, जब पाक कलाकारों को देश से भगाने के मुद्दे पर उनके एक बयान की वजह से मीडिया ने उन्हें आड़े हाथों लिया. उन्हें भला-बुरा कहा गया. लेकिन, ओमपुरी की समझदारी और समाज के प्रति उनकी संवेदना उतनी ही बेहतरीन है, जितना उनका अभिनय.

1980 में आई फिल्म आक्रोश में एक पीड़ित आदिवासी की भूमिका हो या अर्धसत्य का एक युवा इंस्पेक्टर, हर किरदार को उन्होंने निभाया ही नहीं, बल्कि पर्दे पर जिया भी. आक्रोश के लिए तो उन्हें सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया गया. 1982 में आई फिल्म आरोहण के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया. इसके बाद सन 1984 में आई फिल्म अर्धसत्य के लिए एक बार फिर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया. ओमपुरी का जाना, सिर्फ एक अभिनेता का जाना भर नहीं है. उनका जाना, अभिनय के एक स्कूल का बंद होने जैसा है. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें. चौथी दुनिया परिवार की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि.

ओम पुरी के निधन पर बॉलीवुड हस्तियों ने क्या कहा

बॉलीवुड के इस मशहूर अभिनेता के आकस्मिक निधन से बॉलीवुड सदमे में है. करन जौहर ,अनुपम खेर और कई बॉलीवुड सेलेब्रिटियों ने उनकी मौत पर शोक जताया है.

अभिनेता अनुपम खेर ने ट्विटर पर लिखा, मैं ओमपुरी को पिछले 43 साल से जानता था. यकीन नहीं हो रहा है कि वो अब हमारे बीच इस दुनिया में नहीं है. उनकी अचानक हुई मौत से गहरा धक्का लगा है.■

महेश भट्ट लिखते हैं, अलविदा ओम! आज तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी का भी एक हिस्सा चला गया. मैं उन लम्हों को कैसे भूल सकता हूं, जब हमने फिल्म और जिंदगी की बातें करते हुए कितने रातें बिताई.■

अभिनेता बोमन ईरानी लिखते हैं, हमने आज बेहतरीन प्रतिभा, बेहतरीन शख्सियत, बेहतरीन आवाज को खो दिया है.■

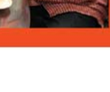

मधुर भंडारकर ने कहा, यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा हुआ है. उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर अपने अभिनय का कमाल दिखाया है. मुझे ये खबर सुनकर बहुत दुख हुआ है.■